खण्ड-07 सत्र-03 (भाग-04) अंक-35

बृहस्पतिवार 19 जनवरी, 2023 / 29 पौष, 1944 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

तीसरा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 सत्र-03 (भाग-04) में अंक 32 से अंक 35 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

राज कुमार

सचिव

RAJ KUMAR

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-3 (भाग-4) बृहस्पतिवार, 19 जनवरी, 2023/29 पौष, 1944(शक) अंक-35

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	याचिका समिति का द्वितीय व तृतीय अंतरिम प्रतिवेदन एवं उस पर चर्चा	6-40
4.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	41
5.	अनुदानों की अनुपूरक मांगे (2022-23) का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर संक्षिप्त वक्तव्य	42-52
6.	दिल्ली विनियोजन (संख्या 01) विधेयक, 2023 (वर्ष 2023 का विधेयक संख्या-02)	53-57
7.	ध्यानाकर्षण (नियम-54)	58-74
8.	अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)	75-130

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-3 (भाग-4) बृहस्पतिवार, 19 जनवरी, 2023/29 पौष, 1944(शक) अंक-35

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.30 बजे समवेत हुआ।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री अजय दत्त
2. सुश्री आतिशी
3 श्री अब्दुल रहमान
4 श्री बी एस जून
5 श्री धर्मपाल लाकड़ा
6 श्री दिनेश मोहनिया
7 श्री दुर्गेश कुमार
8 श्री गिरीश सोनी
9 श्री गुलाब सिंह
10 श्री हाजी युनूस
11 श्री जय भगवान
12 श्री जरनैल सिंह
13 श्री करतार सिंह तंवर
14 श्री कुलदीप कुमार
15 श्री मोहिन्दर गोयल
16 श्री महेन्द्र यादव
17 श्री नरेश बाल्यान
18 श्री नरेश यादव

19 श्री प्रवीण कुमार
20 श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
21 श्री प्रकाश जारवाल
22 श्री ऋतुराज गोविंद
23 श्री राजेश गुप्ता
24 श्री राजेन्द्र पाल गौतम
25 श्रीमती राजकुमारी ढिल्लों
26 श्री राजेश ऋषि
27 श्री रोहित कुमार
28 श्री शरद कुमार चौहान
29 श्री सोमदत्त
30 श्री शिवचरण गोयल
31 श्री सौरभ भारद्वाज
32 श्री सहीराम
33 श्री एस के बग्गा
34 श्री विशेष रवि
35 श्री विनय मिश्रा
36 श्री वीरेंद्र सिंह कादियान
37 श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
38 श्री अभय वर्मा
39 श्री अनिल कुमार बाजपेयी
40 श्री अजय कुमार महावर
41 श्री जितेंद्र महाजन
42 श्री मदन लाल
43 श्री मोहन सिंह बिष्ट
44 श्री ओमप्रकाश शर्मा
45 श्री पवन शर्मा
46 श्री प्रलाद सिंह साहनी
47 श्री सोमनाथ भारती
48 श्री सुरेंद्र कुमार
49 श्री विजेंद्र गुप्ता

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-3 (भाग-4) बृहस्पतिवार, 19 जनवरी, 2023/29 पौष, 1944(शक) अंक-35

दिल्ली विधान सभा

सदन पूर्वाह्न 11.30 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः आज माननीय सदस्य श्री अजय महावर जी का जन्मदिन है मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

(पक्ष के सभी सदस्य वैल में आ गये और नारे लगाने लगे)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यों से प्रार्थना है अपने-अपने स्थान पर बैठें। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं अपनी-अपनी चेयर पर बैठें। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कृपया अपनी-अपनी कुर्सियों पर बैठें। माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर बैठें हाउस की गरिमा बनाकर रखें। माननीय सदस्य प्लीज़ अपने-अपने स्थान पर बैठें। मैं पुनः एक बार सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं हाउस को चलने दें अपनी कुर्सियों पर बैठें। माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर बैठें। हाउस पौने बारह (11.45) बजे तक एडजार्न किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही प्रातः 11.45 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

सदन पूर्वाह्न 11.45 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः बैठिये, माननीय सदस्यगणों से प्रार्थना है बैठें प्लीज़।

(पक्ष के सभी सदस्य वैल में आ गये और नारे लगाने लगे)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण से प्रार्थना है अपनी-अपनी कुर्सी पर बैठें। माननीय सदस्यगण कृपया आप बैठें अपने-अपने स्थान पर बैठें। माननीय सदस्यगण, भई ये मेरे सामने से हट जाएं जरा। इनको कहो ये हट जाएं यहां से, मेरे सामने से हट जाएं, इधर आ जाइये, साइड में आइये, सामने मत आइये। माननीय सदस्यगणों से प्रार्थना है अपने-अपने स्थान पर बैठें। माननीय सदस्यगण कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठें। हाउस सवा बारह बजे (12.15) तक एडजार्न किया जाता है। श्रीमान दिलीप पाण्डे जी जरा एक बार मेरे चैंबर में आएं।

(सदन की कार्यवाही प्रातः 12.15 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 12.15 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

(पक्ष के सभी सदस्य वैल में आ गये और नारे लगाने लगे)

माननीय अध्यक्षः बैठिये, झा साहब अब बैठिये प्लीज़ बहुत हो गया बैठिये, बैठिये। मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कृपया बैठिये। माननीय सदस्य बैठ जाएं बहुत हो गया अब। झा साहब आगे से, बैठिये सब बैठिये।

माननीय सदस्यगणों से प्रार्थना है कृपया बैठें। सभी माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी कुर्सियों पर बैठें। सभी सदस्य बैठ जायें, सभी सदस्यों से प्रार्थना है बैठ जाएं। अरे बिजनेस इतना बाकी है।

(विपक्ष के सभी सदस्य वैल में आ गये और नारे लगाने लगे)

माननीय अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। माननीय सदस्य अपनी कुर्सियों में बैठें। बिधूड़ी जी बैठाइये उनको बैठाइये अब बैठा दिया है सबको। माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठें। माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर बैठें। महावर जी आज आपका जन्मदिन है आप तो बैठों कम से कम। आज का दिन तो मर्यादा रखो, आपको तो बैठना चाहिए। बैठिये सभी, अपने जन्मदिन पर ऐसा मत करो महावर जी। चलिए बैठिये-बैठिये जितेन्द्र जी बैठिये प्लीज़। अनिल जी बैठिये प्लीज़ बैठिये हो गया बहुत हो गया। बिधूड़ी जी बैठिये, बिधूड़ी जी बैठिये प्लीज़। माननीय सदस्यगण बैठिये, बैठिये, बैठिये हो गया अब बैठिये। सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है शांत रहें, बैठ जाइये, बैठ जाइये अपनी सीट पर बैठिये। बिधूड़ी जी बैठिये, बिधूड़ी जी से प्रार्थना है कृपया बैठें। विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है बैठें। बिधूड़ी जी कृपया बैठिये, बिधूड़ी जी आप सीनियर नेता हैं बैठिये। बिधूड़ी जी से प्रार्थना है कृपया बैठें। सभी माननीय सदस्य बैठें। सभी माननीय सदस्य बैठ जाएं। आप बैठिये-बैठिये बिधूड़ी जी बैठिये, प्लीज़ बैठिये। मैं बार-बार कह रहा हूं बैठिये, बैठिये प्लीज़। भई अब चलिए आप उधर चलिए, चलिए उधर, उधर चलिए मैं रोक रहा हूं सबको। आप अपने स्थानों पर बैठिये। मैं विपक्ष के साथियों से प्रार्थना कर रहा हूं कृपया बैठें, हाउस को चलने दें। बैठिये, जरनैल जी आप बैठिये। देखिये, हाउस साढ़े बारह बजे (12.30) तक एडजार्न किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही प्रातः 12.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए ।

(विपक्ष के सभी सदस्य वैल में आ गये और नारे लगाने लगे)

माननीय अध्यक्षः देखिये बैठिये, बिधूड़ी जी नहीं, देखिये मुझे अब एक्शन लेना पड़ेगा। हाउस तीन बार एडजार्न कर चुका हूं। बिधूड़ी जी, मेरी तरफ भी देख लो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, बैठिये। बिधूड़ी जी बैठिये कृपया बैठिये। बैठिये, मैं माननीय सदस्यों को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं बैठिये। मार्शल्स प्लीज़, अब सदन चलाना है मुझे, मार्शल्स प्लीज़। माननीय सदस्यगण बाहर जायें, मैं नेमिंग कर रहा हूं बिधूड़ी जी, अजय महावर जी, मोहन सिंह बिष्ट जी सभी बाहर जायें, अनिल बाजपेयी जी, विजेन्द्र गुप्ता जी नाम बोल रहा हूं, नाम बोल रहा हूं। विजेन्द्र गुप्ता जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, अनिल बाजपेयी जी, महाजन जी। मैंने बोल दिया है नाम, नाम बोला है कि बाहर जायें।

(सभी विपक्ष के सदस्यों को मार्शल्स द्वारा बाहर किया गया)

माननीय अध्यक्षः आज 280 सभी सदस्यों का पढ़ा हुआ माना जाए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद। अब श्री अखिलेश पति त्रिपाठी जी याचिका समिति का द्वितीय तथा तृतीय अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः माननीय अध्यक्ष जी, मैं याचिका समिति का द्वितीय व तृतीय प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष जी, जो हालात

दिल्ली में है एल.जी. साहब ने जिस तरीके से ऑफिसर्स को डायरेक्ट करके दिल्ली के एक-एक कामों को रोकने का काम किया है उसी के संदर्भ में मैं ये याचिका समिति की द्वितीय व तृतीय जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं अध्यक्ष जी, ये "abrupt stoppage of pension of old age citizen in Delhi at behest of Hon'ble Lt. Governor of Delhi." ये इसका टाइटल है इस interim report का। अध्यक्ष महोदय, चुनाव एमसीडी का सर पर था, भारतीय जनता पार्टी को ये पता था कि दिल्ली के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। एल.जी. के माधयम से अधिकारियों को डरा-धमकाकर के जून से लेकर के दिसम्बर तक का ओल्ड एज़ पेंशन 4 लाख 10 हजार लोंगों का ओल्ड एज़ पेंशन रोकने का काम किया गया, उन लोगों का पेंशन रोकने का काम किया गया जो रोटी खाने के लिये अपने उसी पेंशन पर आश्रित हैं, जिनके महीने की दवाईयां दिल्ली सरकार द्वारा दिये जाने वाले 2 हजार और 25 सौ की पेंशन पर आधारित है। अध्यक्ष महोदय, उन गरीब बुजुर्ग लोगों को मरने के लिये अपने हालात पर छोड़ दिया। जब पता किया गया बुलाया गया अधिकारियों को तो पहले तो बताया गया कि केन्द्र सरकार ने पिछले डेढ़ साल से जो दौ सौ रुपया उसमें उनका अनुदान राशि होता है 2 हज़ार में वो 200 रुपये नहीं दे रही है उसका एक परेशानी था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार दे रही है या नहीं दे रही है हम उस हैड को भी पूरा करके गरीब लोगों के साथ खड़े होकर के उनका पेंशन देने का काम करेंगे, वो पेंशन की राशि रिलीज़ करने के लिये आदेश दिया लेकिन फाइनॉन्स डिपार्टमेंट, फाइनॉन्स सेक्रेटरी ने उसमें चाल चली, पहले उन्होंने रोकने का काम किया फाइल को उसके बाद जो समाज

कल्याण सचिव और डायरेक्टर थे उन्होंने एक नया करामात कर दिया, अध्यक्ष महोदय चलती हुई व्यवस्था जो पिछले 8–10 सालों से चल रही थी centralize level पर pension लोगों को मिल रहा था वो ये कहकर के कि हम सिस्टम को इम्प्रुव कर रहे हैं उस सिस्टम के इम्प्रुवमेंट के नाम पर पिछले छः, सात, आठ महीने, पांच महीने, चार महीने ऐसे गरीब लोगों को लोगों को पेंशन नहीं मिली। जब यहां बुलाकर पूछा गया तो कहते हैं नहीं जी, हम तो उसको डिस्ट्रिक लेवल पर कर रहे हैं। मैंने कहा ये कौन आपको बताया कि डिस्ट्रिक लेवल पर कर रहे हैं, कौन रोक रहा है आपको। डिस्ट्रिक लेवल पर करिये खूब अच्छी बात है लेकिन जो इन्ट्रिम व्यवस्था है जैसा सौरभ भाई ने कल बताया कि कमाल की बात है कि पहले उन्होंने कहा कि मकान बदलता है, पहले लाकर के सामान रोड़ पर रख दिया और उसके बाद मकान खोजना शुरू कर दिया, वो ही हालत यहां पर भी किया गया। जिस तरीके से जल बोर्ड में किया गया इसी तरीके से यहां किया गया। पेंशन बंद कर दिया गया और कह रहे हैं जी हम तो डिस्ट्रिक लेवल पर कर रहे हैं। आज हालत ये था कि उसका एक बहुत बड़ा असर लोगों के, जनमानस के दिल पर पड़ा, इन अधिकारियों के माध्यम से केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई और जब बहुत जद्दोजहद कमेटी ने करा, उनको सदन की शक्तियों का अहसास कराया गया और तब जाकर के उन 4 लाख 10 हजार लोगों को जो है न्याय मिलने का काम हुआ है अध्यक्ष जी। आज भी एक चीज़ में बताना चाहता हूं, लोगों को पता चले कि 4 लाख 10 हजार लोगों का जो केन्द्र सरकार का दो सौ रुपया अनुदान के रूप में मिलता था आज तक डेढ़ साल से दिल्ली के लोगों को नहीं मिला, केन्द्र की सरकार इस दुर्भावना के साथ अरविंद केजरीवाल जी

की सरकार के साथ काम कर रही है। ये है मोदी जी की सच्चाई, 4 लाख 10 हजार लोगों का रोटी छीनने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं अध्यक्ष जी जिन अधिकारियों ने इसमें ब्रीफ तरीके से बताया गया कि किस तरीके से सोशल वेलपफेयर की जो सेक्रेटरी हैं उसकी डायरेक्टर हैं और फाइनॉन्स डिपार्टमेंट की मिलीजुली भगत और पीछे के ना जाने कौन सी शक्तियां थीं जो इशारा कर रही थीं जिसकी वजह से 4 लाख लोगों को मरने के लिये मजबूर किया गया, छोड़ा गया, इसको अपराध के रूप में ये सदन ले, उन 4 लाख लोगों की रोटी छीनने का काम किया ये अपराध किया उसमें कई लोग मर भी गये होंगे अध्यक्ष जी जो सदन को नहीं पता, ऐसे मज़बूर लोगों का रोटी छिनने का काम किया अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिये, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिये, मैं ऐसा सदन से उम्मीद करता हूं और इसीलिये रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं कि कम से कम उनके बच्चे सुने जिन अधिकारियों ने पेंशन रोकने का काम किया, उनके परिवार वाले रिश्तेदार आज देख रहे होंगे। उनको कम से कम आईना देखना चाहिये, शर्म आनी चाहिये कि 4 लाख गरीब लोगों का, उन मज़बूर लोगों का जिनके प्रति संवेदना होना चाहिये सबके दिल में, ऐसे संवेदनहीन अधिकारी, ऐसे लापरवाह अधिकारी, ऐसे सेंसलैस अधिकारियों का क्या किया जाये इसका पूरा का पूरा ब्यौरा इस रिपोर्ट में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। मैं समिति के सारे सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अथक परिश्रम करके, अपना समय देकर के समिति की कार्यवाही में भाग लिया, उसको चलाने में एक-एक गहन स्टडी करने में मेरा सहयोग किया, मैं विधानसभा के सचिवालय के सारे सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे सारे सदस्यों ने जांच

करने में मेरी मदद करी। ये रिपोर्ट प्रस्तुत हो ताकि जब भी ये पढ़ा जाये रिपोर्ट तो ये पता चले कि जब-जब कार्यपालिका के अधिकारी मदांध होकर के व्यवस्थापिका के मंदिर के प्रति अपनी जवाबदेही भूलेंगे, ये सदन व्यवस्थापिका उनको लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने देगी। संविधान द्वारा प्रदत्त संसदीय व्यवस्था के अधिकारों को संरक्षित करने के लिये सदन के माधयम से समितियां काम करती रहेंगी और ये समितियों का रिपोर्ट जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से समितियां काम करके जनता के मताधिकार को जनता के विश्वास को बनाये रखने के लिये साल भर काम करती है बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका रिपोर्ट पूरी तरीके से लागू हो और ऐसे संवेदनहीन अधिकारियों को ना केवल कभी भी फ्रंटलाइन की कोई जिम्मेदारी ना दी जाये इनके सर्विस रिकार्ड में ये चीज़ें दर्ज की जायें कि ये लापरवाह लोग हैं संवेदनहीन लोग हैं ऐसे लोग कभी भी फ्रंटलाइन की जिम्मेदारी के लायक नहीं हैं इसकी सूचना माननीय लोकसभा स्पीकर को भी दिया जाये और भी जहां भी उचित प्लेटफार्म है सब जगह भेजकर के ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिये, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद-धन्यवाद, श्री सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज सदन के आगे हमने याचिका समिति की दो और रिपोर्ट्स सदन के मैम्बर्स के सामने रखी है और ये जो रिपोर्ट हैं पहली रिपोर्ट तो वृद्धावस्था पेंशन के विषय में है मुझे याद है और हमारे जितने विधायक साथी यहां पर बैठे हैं उनको ये बात याद होगी दिवाली से पहले हर विधायक के कार्यालय में हर विधायक के ऑफिस में विधायक बाज़ार में मिल जाये, गली में मिल जाये किसी फंग्शन में मिल

जाये हर जगह बुजुर्ग विधायकों को ये बात कह रहे थे कि भई हमारी दो-दो, तीन-तीन महीने हो गए, हमारी पेंशन नहीं आई, पूरा दशहरे के समय, नवरात्रों के समय रामलीलाओं में जाते थे अध्यक्ष जी, जो बुजुर्ग मिलता था वो यही कहता था भई पेंशन नहीं आई अब आप सोचिये कि एक विधायक क्या करे और उसका क्या समाधान दे अगर आपके पास बुजुर्ग बोले कि भई मेरी पेंशन नहीं आई दूसरा बुजुर्ग की तरफ आप देखो वो कहे मेरी भी नहीं आई। दिल्ली के अंदर लाखों लोग जब सब लोग नवरात्रे मना रहे थे जो गरीब बुजुर्ग हैं हमारी दिल्ली में उनके भी नाती-पोते घर आते हैं वो भी ये सोचते हैं कि चलो अब नाती-पोते घर आये कुछ मैं अपनी पेंशन से कुछ इनको 10 रुपये 20 रुपये की कुछ चीज़ दिला दूं, कोई बेटी घर आई है तो उसके हाथ में 100 रुपये रख दूं यही बुजुर्गों का काम होता है और वो इस पेंशन के ऊपर आश्रित होते हैं, हमारी कमेटी के अंदर एक ऐसी महिला भी आई जिसने ये बताया कि मेरे पति को कैंसर है और मैं उनका सफदरजंग में अस्पताल में ईलाज करा रही हूं मैं उनके ईलाज के लिये ऑटो से जाना चाहती हूं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ईलाज करा लूं इतनी हालत खराब होती है और विधायक जो है वो सोशल वेलपफेयर डिपार्टमेंट में पूछते हैं कि भई पेंशन क्यों नहीं आ रही और सोशल वेलपफेयर डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट मुझे लगता है अपने आप में सबसे ज्यादा संवेदनशील होना चाहिये क्योंकि ये डिपार्टमेंट तो वो है जो वृद्धावस्था की पेंशन देता है, जो निराश्रित महिलायें होती हैं उनकी पेंशन मिलती है जो हैन्डिकैप होते हैं दिव्यांग, विकलांग उनकी पेंशन देता है मतलब जो आदमी सबसे ज्यादा मजबूर है उनकी मदद करने का काम सरकार करती है इन डिपार्टमेंट्स के हवाले से सोशल वेलपफेयर डिपार्टमेंट और महिला बाल

विकास विभाग की तरफ से और जब लोग जरूरतमंद लोग इन डिपार्टमेंट्स में जाते हैं जैसे कि हमारे यहां लाजपत नगर का ऑफिस है और बाकी विधायक भी अपने-अपने ऑफिसों के बारे में बतायेंगे इतनी बद्तमीजी से अधिकारी उनसे बात करते हैं। अगर विधायक का कोई खत उनको मिल जाये तो वो खत उठाकर साइड में रख देते हैं, कोई उनके मन में संवेदनशीलता नहीं है उन बुजुर्गों के लिये, गरीबों के लिये, बेचारी विधवा औरतों के लिये, अपंग बच्चों के लिये कोई उनके मन में संवेदना नहीं है और ये मामला जो है हमारे पास 22 अक्तूबर को 21 अक्तूबर को आया मुझे याद है शायद 24 या 23 की दिवाली थी अध्यक्ष जी और हमने तुरंत ये मीटिंग इसलिये रखी हमने कहा कि कम से कम ऐसा तो हो कि दिवाली तक इन बुजुर्गों को पेंशन मिल जाये।

और हमने पता किया तो ये पेंशन तीन महीने से रोकी हुई थी अध्यक्ष जी। ये जो खुद डिपार्टमेंट ने हमें बताया समिति के आगे कि तीन महीने से जो है, ये पेंशन कुछ कारणों से रूकी हुई है। अब हमने सोचा कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा कारण होगा सरकार की तरफ से पैसा नहीं आ रहा। सरकार के पास पैसे की कमी है, क्या कारण है। तो अध्यक्ष जी अगर आपको मैं कारण बताऊंगा चूंकि ये कारण बहुत जरूरी है दिल्ली के विधायकों को जानना और दिल्ली की जनता को जानना कि किन कारणों से आपने तीन-तीन महीने तक बुजुर्गों को सताया। दिल्ली सरकार 2,000 रुपये पेंशन देती है 70 साल के बुजुर्ग को और 70 से ऊपर वाले बुजुर्ग को ढ़ाई हजार रुपए पेंशन देती है। अब उस बुजुर्ग को सताने के लिए क्या किया गया। एक नई ऑफिसर आयी इस डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हैं पूजा जोशी। अब उन्होंने 2009 की एक गजट नोटिफिकेशन निकाली 2022 में। देखिये अध्यक्ष जी, दिमाग देखिये कितना दौड़ता

है इनका। इतना दिमाग दौड़ाते हैं 2009 की गजट की नोटिफिकेशन निकाली और बोले कि भाई ये जो सेंक्शनिंग अथॉरिटी है, ये हमारे हैड क्वार्टर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है और हम तो हैड क्वार्टर से सेंक्शन कर रहे हैं गलत है तो ये डिस्ट्रिक्ट से सेंक्शन होनी चाहिए और इसकी फाइल चला दी और इस फाइल को चलाने के बाद बैठ गए। अब डिस्ट्रिक्ट वाले कह रहे जी हम क्यों चलाएंगे। हमारे पास तो ना इसकी सुविधा है, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे ऑफिस के अंदर इसके लिए बाकी चीजें हैं, ना स्टाफ है, हम तो कर ही नहीं सकते। अब ये हैड क्वार्टर वाले और डिस्ट्रिक्ट वाले लड़ रहे हैं। फाइल–फाइल खेल रहे हैं। ये कह रहे हैं तुम दे दो, वो कह रहे हैं तुम दे दो और नीचे जो गरीब बुजुर्ग है, वो जो है वो सोशल वेलपफेयर डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहा है। विधायकों के यहां चक्कर लगा रहा है। ना विधायक को पता, न सोशल वेलपफेयर के डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर बताने को तैयार है कि मामला क्या है। जब उन गरिमा गुप्ता जी से पूछा कि भई 2009 से ये व्यवस्था चल रही थी, वो भी तो ऑफिसर ही थे आपसे पहले। वो भी तो आईएएस अधिकारी थे, जो चला रहे थे। आपसे सीनियर थे। ये व्यवस्था जो है, 15 साल से चल रही थी। ठीक चल रही थी। आप आए, आप इसके अंदर नयी व्यवस्था लाने लगे। चलिये आप नयी व्यवस्था भी ले आइए मगर आपने पुरानी क्यों बंद कर दी। भई जब तक आपकी नयी लागू नहीं होगी, पुरानी कोई ना बंद कर दोगे आप, सेम वही चीज़। जो कल आपने देखा कि अस्पतालों में कि एक नयी व्यवस्था ले आओ और पुरानी को ठप कर दो और जब तक नयी नहीं आयेगी, नयी और पुरानी के बीच में जनता को जो है, परेशान करो और जनता को क्यों परेशान करो ताकि अरविंद केजरीवाल को बदनाम

किया जाए। कहा जाए कि देखो दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने परेशानी कर दी। अब क्या कहेगा कोई बुजुर्ग आदमी, जिसको तीन महीने से पेंशन नहीं मिली अध्यक्ष जी वो क्या जानता पूजा जोशी का नाम। कौन पूजा जोशी। उसको तो नहीं मालूम। वो तो एक जानता है कि जी मेरे विधायक का नाम जो है दिनेश मोहनिया है। मेरे विधायक का नाम तो राजेश गुप्ता है। जरनैल सिंह ने पेंशन लगवाई थी, अब पेंशन नहीं आ रही तीन महीने से और सोशल वेलपफेयर डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर ये भी कह रहे थे कि आपके विधायकों ने रूकवा रखी है। ऐसे भी हैं कि जाओ अपने विधायक से पूछो, यह आप पूछ लो। जितने भी यहां विधायक बैठे हैं, ये सोशल वेलपफेयर के डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिसर बैठे हैं, इन्होंने वो ये कहते हैं यहां मत आओ, विधायक के पास जाओ। अरे विधायक क्या कोई कागज पत्री लेकर बैठा हुआ है क्या। विधायक के पास क्या पता कि तुम क्या खेल खेल रहे हो ऊपर। तो नीचे से जान बुझकर पब्लिक को भगा दिया जाता है कि तुम विधायक के पास जाओ। विधायक उनको समझाते हैं कि जी हां कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं और नीचे ये खेल चलता रहता है, तो हमने इनको बुलाया पूजा जोशी जी को। हमने इनसे सवाल पूछे कि भाई आप नया सिस्टम ला रहे थे बट पुराना क्यों बंद कर दिया तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके साथ एक और ऑफिसर थे नवलिन्दर, उनकी शायद डिप्टी सेक्रेटरी हैं, डिप्टी डायरेक्टर थे। उन्होंने कमेटी को बताया कि हां ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुराना सिस्टम रखना चाहिए था फिर नया लाना चाहिए था तो पूजा जोशी हमारे सामने उस ऑफिसर को आंख दिखा रही थी। हमारे सामने समिति में, उनकी तरफ शक्ल बना रही थी कि तू क्यों बता रहा है। हम हैरान थे और अध्यक्ष जी क्या

किया उसके बाद एलजी साहब ने वो ऑफिसर का तबादला कर दिया वहां से। अगली बार जब समिति की मीटिंग में सोशल वेलपफेयर डिपार्टमेंट आया। हमने कहा वो ऑफिसर कहां हैं नवलिन्दर, वो थे ही नहीं उसमें क्योंकि उनका तबादला कर दिया। ये हाल है, दिल्ली सरकार के अंदर तबादलों का कि जो ऑफिसर काम रोकेगा, वो तो उस पद पर रहेगा। जो प्रोमिस कर देगा कि जी मैं इससे भी अच्छा रोक दूंगा तो कहेगा, तू आ जा अब और जो ऑफिसर थोड़ा भी काम करना चाहता है, उसका तबादला किया जा रहा है। अभी तबादले किसके हाथ में हैं अध्यक्ष जी, एलजी साहब के हाथ में हैं। क्यों इस तरीके से तबादले किये जा रहे हैं कि जो ऑफिसर काम कर रहा है, उसको हटा दो। जो ऑफिसर काम नहीं कर रहा, उसको वहां लगा दो। ये तो षडयंत्र है और दिल्ली के सरकार के खिलाफ किया जा रहा है तो नवलिन्दर साहब को जो है, हटा दिया गया और फिर पूजा जोशी जी से कई सवाल पूछे गए कि भाई आपके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, ये काम नहीं करते तो बोले जी आप लिख कर दे दो तो हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। हमने लिख कर दिया, अभी तक तो कोई कार्यवाही हुई नहीं तो हमने इस समिति के अंदर खैर वो जब हमने दिवाली को उससे पहले मीटिंग की तो वो पैसा उन्होंने दिवाली पर रीलिज़ कर दिया और उसके बाद जो है पैसा एक दो बार तो डीले होकर आया, अब उन्होंने हमारे आगे ये अपनी अंडरटेकिंग दी है कि हर महीने 5 से 8 तारीख के बीच में पिछले महीने की जो है पेंशन आ जाया करेगी। यानी कि इन्होंने इस बार जब आए थे तो इन्होंने कमिट्मेंट दिया था हमें कि जनवरी, 8 से पहले इन्होंने दिसम्बर की पेंशन डिस्बर्स कर दी है। अब फरवरी 8 से पहले ये जनवरी की पेंशन डिस्बर्स करेंगे, कमिटी इनको देख रही है। अगर नहीं

करेंगे तो हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो अध्यक्ष जी एक मामला तो ये पेंशन से संबंधित था, जिसमें एक पूरे षड्यंत्र के तरीके से जो है दिल्ली के बुजुर्ग लोगों को सताया गया, दिल्ली की विधवा औरतों को सताया गया, दिल्ली के विकलांग बच्चों को जो है सताया गया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी अपने राजनैतिक कारणों से इतना गिरेगा या कभी गिरा होगा कि ये काम रोक लो, ये काम रोक लो, ये काम रोक लो। दिवाली, दशहरे, नवरात्रे के समय में लोग तो दान करते हैं कि कोई गरीब मिल जाए या कोई बुजुर्ग मिल जाए, उसका कुछ अच्छा कर दिया जाए, भगवान जो है पुण्य देगा और ये लोग जो है वो षड्यंत्र करे थे, तो इसके अंदर हमने जो सिफारिश की है, वो की है, एक तो कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है मिस्टर पांडे। उनका नाम जो है, हां साउथ वाला, आपको कोई तारीफ करनी है तो कर दो। बहुत बदमाश है और अध्यक्ष जी जब... विकास पांडे नाम है और अध्यक्ष जी देखिये ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑफिसर गड़बड़ी कर रहा है तो हर विधायक जानता है कि वो गड़बड़ ऑफिसर है, तो ये विकास पांडे हैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर (साउथ), विकास पांडे एक तो इनके लिए सिफारिश की है समिति ने कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये। एक पूजा जोशी हैं, जिन्होंने जो है सबकुछ जानते हुए बुजुर्गों को सताया, परेशान किया, सरकार को बदनाम किया, साजिश की, उनके ऊपर शिकायत/सिफारिश की, हमने शिकायत की और तीसरे जो हैं इनके सरगना वो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, नरेश कुमार जी, जिनको सबकुछ मालूम होते हुए भी हैड ऑफ ब्यूरोक्रेसी रहते हुए भी उन्होंने इन तरीके के गड़बड़ करने वाले ऑफिसरों को संरक्षण दिया और आज भी उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनके ऊपर अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस दिन समिति ने उनसे

पूछा कि क्या आपने अब तक कोई कार्रवाई की तो तब तक तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अगर वो कार्रवाई करते हैं तो समिति जो है, उस चीज़ को भी जो है संज्ञान में लेगी, मगर अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो एक तो अध्यक्ष जी ये।

दूसरा मामला जो है, वो मोहल्ला क्लीनिक्स का है। मोहल्ला क्लीनिक अध्यक्ष जी सब लोग जानते हैं। देश विदेश से अगर कोई आदमी दिल्ली के अंदर आता है तो वो मोहल्ला क्लीनिक जरूर एक बार देखता है। तेलंगाना से हों, तमिलनाडु से हों, मधय प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो ऐसे कई राज्य हैं, जहां से अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री मोहल्ला क्लीनिक को देख कर अपने अपने राज्य में उसका अनुसरण कर रहे हैं, जो अच्छी बात है।

मोहल्ला क्लीनिक जो है, वो एक तरीके से पर्याय है आम आदमी पार्टी की दिल्ली मॉडल का। अगर कोई पूछे कि भाई आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल क्या है तो कहेंगे स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लीनिक। मोहल्ला क्लीनिक हमेशा आयेगा और ये मोहल्ला क्लीनिक जो है एक तरीके का पोलिटिकल बदला लेने का एक अखाड़ा बन गया कि जो जांच करानी हो, मोहल्ला क्लीनिक पर कराया जाये। कहीं पर कुछ रूकवाना हो मोहल्ला क्लीनिक के अंदर रूकवाया गया।

अध्यक्ष जी, एमसीडी के चुनाव दिसम्बर में हुए दिल्ली में और इससे दो तीन महीने पहले मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टरों की तनख्वाह देनी बंद कर दी गयी। एमसीडी चुनाव से ऐन पहले मोहल्ला क्लीनिक में जहां पर फ्री टेस्ट होते हैं। जहां पर ज्यादातर लोग इसलिए जाते हैं कि यहां पर फ्री टेस्ट हो जाएंगे।

वो टेस्ट करने बंद कर दिये, उसकी जांच कराई हमने, पता चला कि टैस्ट इसलिए बंद हो गए क्योंकि जो कम्पनी टैस्ट करती है, जो लेबोरेटरी हैं प्राइवेट, उनको सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया। कह रहे हैं कि भई हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट से इजाजत मांगी थी, पैसा मांगा था सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। फाइनेंस ने इंस्टॉलमेंट नहीं दी। डॉक्टरों की तनख्वाह क्यों नहीं दी। डॉक्टरों की तनख्वाह इसलिए नहीं दी क्योंकि फाइनेंस से सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगी थी, वो उन्होंने नहीं दी तो बंद हो गया।

अब अध्यक्ष जी, ये बड़ा साधारण सी बात है। मैं ईएमआई देता हूं मान लिजिए अपने घर की तो मेरी एक कैल्कुलेशन है। मेरे को हर महीने तनख्वाह मिलेगी। मैं हर महीने ईएमआई दूंगा। ऐसे ही हर विभाग की एक कैल्कुलेशन है कि हम एक अपनी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट मांगे, सैकेंड मांगेंगे, थर्ड मांगेंगे, कोई इंस्टॉलमेंट आएगी, आप जो है आगेका खर्चा दोगे।

फाइनांस सेक्रेटरी जो हैं दिल्ली सरकार के मिस्टर आशीष चंद्र वर्मा, उन्होंने इतने बारीकी से षड्यंत्र रचे दिल्ली सरकार के खिलाफ कि जो सैकेंड इंस्टॉलमेंट आयेगी, जो मांग आएगी, जो डिमांड आएगी वो सैकेंड इंस्टॉलमेंट को किसी न किसी बात पर रोक लिया जाए तो यहां पर कैसे रोका। यहां पर उन्होंने कहा कि भई अब आप अध्यक्ष जी समझिए 2015 से मोहल्ला क्लीनिक चल रहे हैं दिल्ली के अंदर। हर बार फाइल इंस्टॉलमेंट के लिए जाती है, फाइनांस से पैसा आ जाता है। मगर 2022 में जब यह फाइल चली और फाइनांस डिपार्टमेंट में पहुंची तो फाइनांस ने ओब्जेक्शन लगाया। पहले तो ये फाइल ही दो महीने में पहुंची। हैल्थ से घूमती-घामती जो है ये फाइनांस सेक्रेटरी के पास पहुंची, आशीष चंद्र वर्मा जी के पास और जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि

अरे मोहल्ला क्लीनिक के लिए पैसा चाहिए तुम्हें, मगर इसके अंदर कैबिनेट नोट नहीं हैं। सोचिये अध्यक्ष जी, 2015 से चल रहा है मोहल्ला क्लीनिक अब इन्हें 2022 में उसका कैबिनेट नोट चाहिए और कैबिनेट नोट है तो डाउनलोड कर लो। वो तो सब वेबसाइट पर है और जितनी भी कैबिनेट होती हैं, उनके अंदर जो भी फैसले होते हैं वो तो बाय डिफॉल्ट फाइनांस डिपार्टमेंट में हर बार जाते हैं। फाइनांस डिपार्टमेंट के बिना तो कैबिनेट में कोई नोट ही नहीं आता और कैबिनेट में पास होने के बाद ही वो फाइनांस डिपार्टमेंट में उसकी कॉपी जाती है, लॉ में जाती है। आप क्यों मांग रहे हो, जो चीज़ आपके पास है तो उन्होंने जो चीज़ उपलब्ध है, वो चीज़ उन्होंने दोबारा मांगी और वो चीज़ भी तुरंत नहीं दी गयी अध्यक्ष जी, वो कैबिनेट नोट मोहल्ला क्लीनिक का हैल्थ सेक्रेटरी के पास पहुंचा फाइल। फिर हैल्थ सेक्रेटरी ने नीचे दी मोहल्ला क्लिनिक तक, मोहल्ला क्लिनिक के लेवल पर वो कैबिनेट नोट लगाया गया, वो फाइल हैल्थ सेक्रेटरी को भेजी गई और फिर वो फाइनांस सेक्रेटरी को भेजी गई, इसके अंदर डेढ़ महीना और लगा दिया। तो सिर्फ एक मामूली सी चीज़ के लिए इन्होंने 3 महीने तक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर पैसा रोक दिया, डॉक्टरों की तनख्वाह रोक दी, टैस्ट रोक दिए, दवाइयां रोक दी। और अध्यक्ष जी इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि जो अस्पतालों की, जो इन मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर डॉक्टरों की तनख्वाह है, जिसकी जरूरत मोहल्ला क्लिनिकों को थी, वो मात्र 11 करोड़ रूपये है, सिर्फ 11 करोड़ रूपये। और हैल्थ डिपार्टमेंट के पास अन्स्पेंट 70 करोड़ रुपये पड़ा था, ऐसा नहीं था कि हैल्थ डिपार्टमेंट को बेहद जरूरत थी उस पैसे की जो फाइनांस से मांग रहे थे। हैल्थ डिपार्टमेंट के पास 70 करोड़ रुपया अन्स्पेंट पड़ा था मगर वो पैसा फाइनांस से मांग रहे थे। हमने

उनसे पूछा भई तुमने अपना पैसा क्यों नहीं खर्च किया, तुम्हारे पास 70 करोड़ पड़ा था तो उन्होंने बोला कि भई इसकी भी जो परमीशन थी वो हमने जो है फाइनांस से मांगी, जोकि मांगने की जरूरत नहीं थी अध्यक्ष जी। उन्होंने जबरदस्ती उसकी परमिशन फाइनांस से मांगी और फाइनांस के अंदर तो आशीष चंद्र वर्मा बैठे है, इन्हीं परमीशनों को रोकने के लिए बैठे है। उन्होंने बोला नहीं–नहीं–नहीं, तुम्हारे पास जो 70 करोड़ रुपया है वो भी तुम नहीं खर्च करोगे जब तक मेरी परमीशन न हो तो अध्यक्ष जी हर लेवल पर ये देखा गया कि ये जो फाइनांस सेक्रेटरी है आशीष चंद्र वर्मा, इन्होंने एक बहुत क्या कहते हैं बहुत दुर्भावना से साजिश रची, षड्यंत्र रचा और किसके खिलाफ रचा, चुनी हुई सरकार के खिलाफ रचा। अब चुनी हुई सरकार का खुद तो बिगाड़ नहीं सकते डायरेक्ट, वो क्या कर लेंगे। उन्होंने सोचा कि जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो विधवायें हैं, जो विकलांग हैं, उनको किसी तरीके से परेशान किया जाए, 3–4 महीने उनको टॉर्चर किया जाए, उनको दुखी किया जाए, जब वो दुखी होंगे तो वो सरकार को गाली देंगे और इसका फायदा हमें, एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, इस उद्देश्य से इतना घिनौना कृत्य जो है दिल्ली के बड़े–बड़े आईएएस अधिकारियों ने रचा।

और ये जो मोहल्ला क्लिनिक की जो रिपोर्ट है इसके अंदर जो है हमने कुछ अधिकारियों को दोषी पाया हैं अध्यक्ष जी, उनके नाम हैं–हैल्थ सेक्रेटरी–अमित सिंगला और प्रिंसिपल सेक्रेटरी–आशीष चंद्र वर्मा, इन दोनों ने भारी गड़बड़ी फैलाई और इनको संरक्षण था दिल्ली के मुख्य सचिव–नरेश कुमार जी का, जिन्होंने सब कुछ होते हुए आंख बंद करके देखा, जैसे धृतराष्ट्र ने द्रौपदी का चीरहरण देखा आंख बंद करके, सब कुछ होने दिया, ऐसे जो है हमारे जो नरेश

कुमार–मुख्य सचिव है, इन्होंने ये सब कुछ होने दिया और इसके ऊपर कोई उनकी जो है प्रक्रिया नहीं थी। उनको हमने 3 दर्जन अखबार की क्लिपिंग्स दिखाई कि ये छप रही हैं अक्टूबर से अब तक, आपने ये नहीं पढ़ी और उन्होंने ऐसे दिखाया कि जैसे ये अखबार में छपी ही नहीं। तो हमने उनको भी इसके अंदर जो है दोषी माना है। और हमने केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जो राष्ट्रपति महोदय हैं, उनसे भी सिफारिश की है कि, इन दोनों मामलों में अध्यक्ष जी, चाहें मोहल्ला क्लिनिक का हो, चाहें पेंशन का हो, जो उप–राज्यपाल महोदय हैं उनकी भूमिका बहुत संदिग्ध पाई गई है। ऑफिसरों ने हमें कमेटी के अंदर, जब हमने वो जो कॉन्फिडेंशियल क्लॉज है उसको इस्तेमाल करते हुए ऑफिसरों से बात की तो उसके अंदर ऑफिसरों ने साफ लफ्ज़ों के अंदर ये बात कही हमें कि ये जो मुख्य सचिव है नरेश कुमार, इन्होंने हमें डराया, धमकाया और उप–राज्यपाल महोदय के नाम से डराया धमकाया गया हमको कि अगर तुमने दिल्ली सरकार के काम नहीं रोके तो एल.जी. साहब के आदेश है, तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। और इस तरीके से चुनी हुई सरकार को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र आपके सामने रचा गया। ये दोनों रिपोर्ट्स आपके सामने हैं अध्यक्ष जी। बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः केवल बाकि माननीय सदस्य जिनको बोलना है, बहुत संक्षेप में, 5–5 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद जो आपने इस विषय पर बोलने का मौका दिया। दिल्ली के अंदर जो एक चुनी हुई सरकार है उस सरकार की मंशा हर उस सरकार की तरह जनता के काम करने की होती है जिसे जनता ने अपनी कुछ इच्छाओं के साथ में चुना। दिल्ली की केजरीवाल जी की

सरकार, जो अपने मैनिफेस्टो को धर्म ग्रंथ मानती है कि जो लिखा है उसे करना है, हमारे लिए वो जुमला नहीं है। लोगों ने चुना, हमने उस पर काम किया। हम कर रहे हैं लोग इसलिए दौबारा हमें चुन रहे हैं। लेकिन उसको कैसे रोकना है उसका ये षड्यंत्र जो इस समिति के सामने आया, जो माननीय चेयरमैन साहब ने, अखिलेश पति त्रिपाठी जी ने और सौरभ जी ने आपके सामने बातें रखी। इतनी अचम्भे की चीजें हमारे सामने उसमें निकलकर आई, सरकार के जो मुख्य मुद्दे रहें काम करने के, एक रहा शिक्षा, एक रहा चिकित्सा, एक रहा सुरक्षा और चौथा है प्रतिष्ठा। शिक्षा पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उसको रोकने के लिए, हमारे टीचर्स को रोका जा रहा है कि बाहर ना जाने दिया जाए, नया कुछ सीख ही नहीं पाएं। चिकित्सा की बात हो रही है तो मोहल्ला क्लिनिक को कैसे रोक दिया जाए। आपने सुना किस तरीके से दवाइयों की पेमेंट के ऊपर रोक दिया गया, डॉक्टर्स की तनख्वाह को रोका गया, हॉस्पिटल के अंदर जो डाटा ऑपरेटर्स हैं उनको हटा दिया गया। सुरक्षा की बात आई तो बस, जो बस के मार्शल्स हैं उनकी तनख्वाह को रोक दिया गया। और प्रतिष्ठा की जब बात आई तो जैसे मैंने 2 दिन पहले रखा कि जो उनके लिए, झुग्गिवासियों के लिए बने हुए शौचालय थे उनको तोड़ दिया गया। डूसिब के सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है क्योंकि ठेकेदारों को तनख्वाह नहीं दी जा रही, ये भी पिटिशन में आगे आयेगा। लगभग 6 महीने, इसमें वक्त सबसे बड़ी धयान देने वाली बात रही अध्यक्ष जी कि सारी चीजें एक ही जगह आकर रूक गई कि ये जो चुनाव आने वाला था, उसके कुछ महीनों पहले एक षड्यंत्र बनाया गया, पहले उसको डिले किया गया कि डिले करना क्यूं किया गया, वो जो 6 महीने बढ़ाये गए तो वो 6 महीने में क्या करना था,

तो तैयारी की गई। पहले तो कुछ वोट काट दो, वो करे। इधर से उधर जोड़ दो, जमा घटा कर दो, वो भी कर लिया, उससे भी ये लगा इनको, इन्होंने सर्वे कराया तब भी हार रहे थे, तो कहा जी काम रोक दो। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसको रोका नहीं गया। जैसे मैंने अभी बताया शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, चारों पर हमले बोले गए। समिति में आने के बाद में जो हमारे ज़मीन पर काम करने वाले अधिकारी हैं, जैसे सौरभ जी ने बताया, डरे हुए थे, सहमे हुए थे और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें बताईं जिसको इन्होंने आपके सामने उल्लेख किया।

मैं दो और बातें इनके एक्स्ट्रा रखना चाहूंगा कि समिति में बुलाने पर अक्सर कह देते है, झूठ बोल देते है कि हम मंत्री जी के पास है, मंत्री जी को फोन लगाया गया तो मंत्री जी ने कहा, नहीं, ठीक है, समिति ने बुलाया है, मैं इनको अभी जल्दी फ्री कर देता हूं। सचिवालय से लेकर विधान सभा के आने का रास्ता सर कितने मिनट का है, हम लोग रोज़ आते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा। डेढ़-डेढ़ घंटे अधिकारी पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। उनको बीच में फोन लगा रहे हैं, आ रहे हैं सर, जाम है। डेढ़-डेढ़, दो-दो घंटे यहां तक नहीं पहुंचे। फाइल कांख में दबा रखी है, कहते है फाइल लेने के लिए जा रहे है, भूल गए। और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब कहते है कि मैं किस-किस के ऊपर एक्शन लूं। बताइये दिल्ली की जनता अगर ये बात सुन ले कि विधायक तो ये कह रहा है कि भई एल.जी. साहब काम रोक रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब ये कह रहे हैं कि मैं किस-किस पर एक्शन लूं, तो ऐसे प्रजातंत्र का क्या करना है? मैंने कहा उनसे, अरे लोग तो हाथों के अंदर हथियार उठा लेंगे, अगर प्रजातंत्र की ये हालत रही कि विधायक ये कह

रहा है कि मैं आपको पेंशन नहीं दिलवा सकता, डॉक्टरों को सैलरी नहीं दिलवा सकता, दवाइयां नहीं दिलवा सकता और चीफ सेक्रेटरी ये कह रहे है कि ऐसे अधिकारियों पर मैं एक्शन नहीं ले सकता जिन्होंने कुछ नहीं करा या कुछ गलत करा, तो प्रजातंत्र किसलिए है? और ऊपर से झूठ बोलते है, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, ऊपर से झूठ बोलते हैं, समिति के अंदर बैठकर कहते है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं एक्शन नहीं ले सकता। और उसके बाद में जब हमारे सदस्य ने इस पर ये कहा कि आपने कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, हम रिकॉर्डिंग दिखाते हैं और हमारे सदस्यों ने सबने कहा कि हां, आपने कहा है, तो कहते है शायद कहा होगा। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, जिनकी, 35 साल का उन्होंने कहा है कि उन्हें तजुर्बा है, हमारे कुछ साथियों की इतनी उम्र नहीं है। बाद में माफी मांगी उन्होंने। बताइये क्या मजाक बना रखा है आपने, कहते है मैंने कहा होगा।...

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए। राजेश जी, प्लीज कन्क्लूड करिए।

श्री राजेश गुप्ताः इसके बाद में फाइनांस सेक्रेटरी साहब, अखबार में आया है और मैं आपके संज्ञान में इस बात को जरूर लाना चाहता हूं, ये बहुत इम्पोर्टेन्ट है कि उन्होंने कहा कि मुझे पिटिशन कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिली, कंप्लेंट, कंप्लेंट नहीं मिली और अखबार में उन्होंने बयान दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर छपा है, जिसके लिए मैंने कंप्लेंट आपको भेजी है पिटिशन कमेटी के, सॉरी, प्रिविलेज कमेटी के लिए, आप इस पर संज्ञान लें।

और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए इस बात पर आना चाहता हूं कि ये दिल्ली की विधान सभा का मखौल है,

क्योंकि समिति आपके अंडर में काम करती हैं, विधान सभा के अंडर में काम करती हैं। अधिकारी टाइम पर आते नहीं हैं, जवाब ढंग से देते नहीं हैं, कोई कहता है मैं भूल गया, कोई कहता है मुझे याद नहीं, कोई कहता है मैंने कहा होगा, तो आपको अखबारों को भी एक ब्रीफ करना होगा, उनको भी बुलाना होगा, उनसे भी कहना होगा कि भई विधान सभा से जो भी बात वो लिखे, वो यहां से किसी तरीके से ली जाए, आपकी तरफ से जाए। journalist यहां पर मौजूद थे उसके बावजूद भी गलत लिखा जा रहा है, तो ये तो आपकी तरफ से हो। ऐसे कोई भी कुछ भी बोल देगा, छाप दिया जाएगा तो प्रिविलेज सब पर बनना चाहिए, तो इसको सीरियस्ली लिया जाए। जो बातें आपके सामने आई हैं, माननीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने रखी हैं, समिति के अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने, जिनके खिलाफ जो एक्शंस की बात हुई है और साथ में, इसके साथ में कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं, मेरा मानना है कि इन रिकमेंडेशंस को तो इनकी रूल बुक में डाल देना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है कि हैल्थ सेक्रेटरी साहब को कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स की मीटिंग्स को minuterize करना चाहिए, हमें बताना चाहिए, आरकेएस बनी हुई है हॉस्पिटल्स में, हमारे विधायकों को बताना चाहिए, ये रिकमेंडेशंस उनको माननी चाहिए, इस पर काम हो, क्योंकि दिल्ली की सरकार ऐसी सरकार नहीं है जो हिंदुस्तान भर में चल रही है कि बस जीत गए और 5 साल भूल गए। हम लोगों के लिए काम करने के लिए कटिबद्ध है, हम करेंगे और जो उसे रोकेगा उसको हम कैसे भी करके, क्योंकि कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज है। भाजपा और एल.जी. साहब दिल्ली से जंग कर रहे हैं और केजरीवाल और उसके विधायक दिल्ली से इश्क कर रहे हैं, हम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। कुलदीप जी।

श्री कुलदीप कुमारः धन्यवाद अध्यक्ष जी, ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो आज याचिका समिति के अध्यक्ष अखिलेश जी ने यहां रखी है। ये मुझे लगता है कि दिल्ली के इतिहास में और दिल्ली के लोगों के लिए और देश भर के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में जब इस रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा और लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ अधिकारियों ने उप-राज्यपाल महोदय के कहने पर किस प्रकार से दिल्ली के कामों को रोकने का काम किया। अध्यक्ष जी, मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल मेरे विधानसभा में है उसका मैं चेयरमेन भी हूं और उस हॉस्पिटल के अंदर अध्यक्ष जी मुझे कॉल आया है कि यहां पर पर्ची नहीं बन रही है। मैंने कहा पर्ची नहीं बन रही है मुझे लगा कोई रूटीन वर्क होगा मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा जी हमारे जो कंप्यूटर में पर्ची बनती थी वो कंप्यूटर कोई उठा के ले गया जिसका कॉन्ट्रेक्ट था तो मैंने कहा यार उसको टैंडर दे दो दौबारा। कह रहे हैं जी टैंडर तो दे देंगे लेकिन उसका टैंडर रिन्यू नहीं हो रहा है। मुझे लगा सरकार में पैसे वैसे नहीं होंगे। पैसे की कमी होगी तो मैंने उस बात का जिक्र पिटिशन कमेटी में किया। मैं उसकी पिटिशन ले के पिटिशन कमेटी के अंदर आया और अध्यक्ष जी, पिछले दो ढाई महीने में जो भी अधिकारी उस कमेटी के अंदर आए उन्हें देख के ये अनुभव हुआ कि दिल्ली की सरकार जो हर बार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली की सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है अगर यहां कमी है तो कुछ अधिकारियों की नीयत की कमी है अध्यक्ष जी। आप ये मानिए कि उन डाटा एंट्री ऑपरेटर बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है अध्यक्ष

जी। 15-17 हजार रूपये मिलते होंगे उनको लेकिन उन 5-7 डाटा एंट्री ऑपरेटर के ना होने से अध्यक्ष जी जहां ओपीडी 2 हजार की थी वो ओपीडी 1200 पर रह गई। आठ-आठ सौ लोगों ने प्रतिदिन सफर किया अध्यक्ष जी, लंबी-लंबी लाइनों में लगे, हमें गाली दी, सरकार को गाली दी लेकिन अधिकारी को किसी ने गाली नहीं दी क्योंकि उन्होंने जनता ने हमें चुन के भेजा है, उन्होंने वोट हमें दिया अपना लेकिन अध्यक्ष जी मतलब आठ-आठ सौ लोगों ने सफर किया और मुझे तो ऐसा भी ज्ञात होता है कि शायद कुछ लोगों का इलाज भी ना हो पाया हो और शायद उनकी मृत्यु भी हो गई हो। तो अध्यक्ष जी, जब हमने कमेटी के अंदर देखा कि किस प्रकार से अधिकारियों ने केवल फाइल को इधर से उधर, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कभी ये लेके आ जाओ, कभी नोट लेके आ जाओ, कभी इसका काम कर दो, कभी एआर स्टडी करा लो। हमें तो पता भी नहीं अध्यक्ष जी एआर स्टडी क्या होती है और उनकी जो रिपोर्ट में आया है अभी जो रिपोर्ट में आया है अभी रिपोर्ट जो मैं पढ़ रहा था एआर स्टडी जिन हॉस्पिटल में कराई अध्यक्ष जी ऐसा नहीं कि वहां वो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जहां पर 10 डाटा एंट्री ऑपरेटर थे वहां पे 9 हो गए उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ लेकिन क्या हुआ? दिल्ली के लोग ईलाज के लिए परेशान हुए। तो मैं तो ये भी कहता हूं अध्यक्ष जी, सदन में कि जिन अधिकारियों की वजह से वो लोग परेशान हुए, जिन लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसे अधिकारियों के उपर तो मैं कहता हूं तीन सौ दो का मुकद्मा भी रजिस्टर कराना चाहिए, जिन्होंने दिल्ली के लोगों की जान लेने का काम किया अध्यक्ष जी। तो अध्यक्ष जी, हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था बहुत चरमर्रा गई लेकिन याचिका समिति ने उसका संज्ञान लिया और उस पर कार्यवाही करने

का काम किया तो जब उसमें निकल के आया कि हैल्थ सैक्रेट्री ने उसके अंदर अपनी प्रथम भूमिका निभाई। अमित सिंगला जी जो थे उनकी भूमिका से वो काम रूका और दिल्ली के लोग परेशान हुए तो सबसे पहले तो अध्यक्ष जी ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव में सस्पेंड किया जाना चाहिए और मैं इनकी पिटिशन से सहमत भी हूं। दूसरी बात अध्यक्ष जी, मोहल्ला क्लीनिक, दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक अध्यक्ष जी मैं कहता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। आज एक-एक मोहल्ला क्लीनिक के अंदर अध्यक्ष जी तीन-तीन सौ चार-चार सौ लोग अपना इलाज कराते हैं। अपने टैस्ट कराते हैं जहां बिना टैस्ट के लोगों की जान चली जाती थी उन्हें बीमारी का नहीं पता लगता था अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने वो मोहल्ला क्लीनिक की व्यवस्था उनके घर के पास दी जहां आज वो अपना इलाज करा पाते हैं अध्यक्ष जी। जहां पर उनकी बीमारी का पहले पता लग जाता है किसी को क्या बीमारी है वो हायर सैन्टर में जाता है उसका इलाज कराता है पहले से पहले उसको पता लग जाता है तो अध्यक्ष जी वो रीढ की हड्डी हैं उन मोहल्ला क्लीनिक के अंदर अध्यक्ष जी टैस्टों को रोक दिया गया। टैस्ट रोक दिए गए। डॉक्टर की सैलरी रोक दी गई और जब ये पूरी बात निकल के सामने आई तो उसके अंदर भी वही फाइनांस सैक्रेट्री जिनका बार बार इसके अंदर जिक्र हो रहा है डॉक्टर आशीष वर्मा जिन्होंने ये समझा कि पैसा उनका पैसा है। ये पैसा उनके घर का पैसा है अध्यक्ष जी, मैं उनको बताना चाहता हूं सदन को बताना चाहता हूं ये पैसा दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा है और दिल्ली की जनता ये पैसा सरकार के माधयम से खर्च होता है इसलिए होता है क्योंकि सरकार जनता के लिए काम करती है। जनता के स्वास्थ्य के लिए काम करती

है लेकिन अध्यक्ष जी, उन्होंने उस मौहल्ला क्लीनिक के काम को रोकने का भी काम किया। अध्यक्ष जी बुजुर्गों की पेंशन का मामला, बुजुर्गो ने हमारे बुजुर्ग मेरे यहां कल्याणपुरी में झुग्गी–झोपड़ियां हैं वहां पर लोगों की पेंशन बनी हुई हैं बहुत सारे वैसे इलाके भी हैं जहां वो दवाई उससे लेते हैं पूरा परिवार उस पेंशन पर चलता है क्योंकि अध्यक्ष जी पूरे देश में, पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली की सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो बुजुर्गों को 25 सौ रूपये पेंशन देने का काम करती है। वर्ना कहीं पर हजार रुपये, कहीं पर 5 सौ रुपये, कहीं पर 7 सौ रुपये और वो भी मिले या नहीं मिले लेकिन अध्यक्ष जी उन बुजुर्गों की पेंशन 6–6 महीने तक रोकने का काम किया गया। उसको रोकने का काम किया गया और वो सच बात है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस थे वहां पर वो लोग जाते थे उनको ऐसे भगाया जाता था, ऐसे बर्ताव किया जाता था कहते थे जा के एमएलए से बात कर लो। वो हमारे पास आते थे, हम उनको बता नहीं पाते थे लेकिन जब ये पिटिशन आयी अध्यक्ष जी कमेटी के अंदर तो हमने देखा कि किस प्रकार से अधिकारियों ने एक 2009 का ऑर्डर सौरभ भाई ने बताया 2009 का ऑर्डर आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया वो कहते हैं चीफ सैक्रेट्री आकर कहते हैं कि जी वो हर तीन साल में analysis करना पड़ता है कि कौन जीवित है कौन नहीं है। आपको 2009 से ये बात याद नहीं आई और अगर नहीं किया तो उस अधिकारी पर आप कार्रवाई करो। हमने कहा उस अधिकारी पर आप कार्रवाई करो, तो उन्होंने कहा जी मैं किस किस पर कार्रवाई करूंगा। मैं क्या सबको हटा दूंगा। अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि इस प्रजातंत्र के अंदर इस प्रकार का वक्तव्य एक चीफ सैक्रेट्री के द्वारा देना, तो मैं कह सकता हूं कि लोगों का अपमान है। तो अध्यक्ष

जी मैं इस सदन के माधयम से यही कहना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है इन तीन अधिकारियों के ऊपर दिल्ली के चीफ सैक्रेट्री जिनके पास सारी जिम्मेदारी थी जिन्होंने सब कुछ आंखें बंद करके देखा कि दिल्ली में लोग इलाज के लिए परेशान हो रहे थे, दिल्ली के अंदर लोग मोहल्ला क्लीनिक के अंदर परेशान हो रहे थे, बुजुर्ग पेंशन के लिए परेशान हो रहे थे, उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी और किससे कहने पर बांधी अध्यक्ष जी अधिकारियों से हमने भी बात की। अधिकारियों ने एक ही बात कही कि हमें उपर से धमकाया जाता है, कहा जाता है उपराज्यपाल के द्वारा।

माननीय अध्यक्षः कुलदीप जी कंक्ल्यूड करिए प्लीज़।

श्री कुलदीप कुमारः नीचे कहा जाता है। अध्यक्ष जी, बस एक मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः कंक्लूड करिए अब प्लीज़।

श्री कुलदीप कुमारः ये कहा जाता है कि अगर आपने इस फाइल को आगे बढाया या इसको परस्यू किया तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष जी, इस प्रकार से ऑफिसर्स को डराया गया तो मैं आपके माधयम से कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों, चीफ सैक्रेट्री, हैल्थ सैक्रेट्री और फाइनेंस सैक्रेट्री इन तीनों अधिकारियों के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो तभी दिल्ली के लोगों को न्याय मिल पायेगा और ये एक मिसाल साबित करे विधानसभा, आने वाले समय के लिए कि अगर कोई भी अधिकारी दिल्ली के लोगों के काम रोकने की कोशिश करेगा तो उसे गददी पर बैठने का अधिकार नहीं है अध्यक्ष जी, जिस कुर्सी पर वो बैठा हुआ है। उसको उस कुर्सी पर

रहने का अधिकार नहीं है, तो ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान बी.एस.जून जी।

श्री बी.एस.जूनः सर जब ये deliberations Petitions Committee में चल रही थी मोहल्ला क्लीनिक पर, हॉस्पिटल्स पर और ओल्ड एज़ पेंशन पर तो फाइनांस सैक्रेट्री मीटिंग में आए। मैंने उनसे स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन पूछा कि आपकी priority क्या है, आपकी priority लोगों का वेलपफेयर है या कुछ और है तो उन्होंने कहा मेरी priority है fiscal discipline maintain करना और मेरा वेलपफेयर से कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सर हम सब एक वेलपफेयर स्टेट का हिस्सा है। इंडिया एक वेलपफेयर स्टेट है यहां लोगों के fundamental rights हैं यहां लोगों को जितनी भी स्कीम बनाई जाती हैं जो भी पैसा खर्च किया जाता है लोगों के वेलपफेयर के लिए किया जाता है अगर हम fundamental rights को देखें तो right to life जीवन जीने का अधिकार और right to get proper medical facility दोनों के दोनों fundamental right हैं अगर आप मोहल्ला क्लीनिक को ठप्प कर देंगे अगर आप हॉस्पिटल्स को ठप्प कर देंगे तो फिर लोगों के दो मौलिक अधिकारों का हनन होता है यहां उसके लिए कौन जिम्मेवार है ब्यूरोक्रेसी जिम्मेवार है या Lt. Governor जिम्मेवार है। ये कमेटी या ये विधानसभा या ये सदन इन मौलिक अधिकारों के हनन के लिए जिम्मेवार हनन होते हुए नहीं देख सकती। पीटिशन कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने इनको रिस्पोंसिबल बनाया और इनको रिक्मन्ड किया कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए क्योंकि इन्सैंसेटिविटी इतनी है इन लोगों के दिमाग में कि हमें वेलपफेयर नहीं चाहिए लोगों का।

हमें तो अपनी नौकरी करनी है और जैसे ऊपर से इंस्ट्रक्शन आयेंगी डायरेक्शन्स आयेंगी हमने उनको फॉलो करना है तो इस वजह से अगर हम इनसे ये एस्पेक्ट करें और आगे भी एस्पेक्ट करें कि ये लोग वेलपफेयर के लिए काम करेंगे शायद नहीं पॉसिबल है। ये तो ऊपरवाला हमारी मदद करे सुप्रीम कोर्ट में कल ऑर्डर रिजर्व हो गया सर्विसिज़ डिपार्टमेंट जो है दिल्ली सरकार को मिले ताकि इन लोगों के ऊपर कुछ नकेल कसी जाए और इनसे प्रापर्ली काम लिया जाए। अब सर देखिए? पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर पर इन्होंने कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू नहीं होने दिया एआर स्टडी के नाम पर अगर मान लिया आपने एआर स्टडी करानी है तो आपको stop gap arrangement तो करना चाहिए था ना या पुराने वाले कॉन्ट्रेक्ट को एक्सटैंड कर दो वो भी नहीं किया। जब फाइल दोबारा से गई फाइनांस डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा एआर स्टडी कराओ मोहल्ला क्लीनिक डॉक्टर्स को सैलरी नहीं, मैडिसन नहीं। मैंने मीटिंग की उसमें कमेटी की मीटिंग में कहा कि मोहल्ला क्लीनिक्स में सिवाय कफ सिरप के और दूसरी कोई दवाई नहीं है। अब वो मानने के लिए तैयार नहीं तो मोहल्ला क्लीनिक चलेंगे कैसे वहां आज मोहल्ला क्लीनिक दिल्ली में इतने पापुलर हैं इतने लोग आते है इलाज कराते हैं टैस्ट कराते हैं जब दवाइयां ही नहीं होगी तो लोग किसलिए आएंगे तो एक साजिश हो रही थी कि किसी ना किसी तरीके से इलैक्शन से पहले पार्टी को सरकार को बदनाम किया जाए और इन चीजों को ठप्प कर दिया जाए। अब तीसरा इश्यू सर ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन आप कोई ग्रेच्यूटी नहीं दे रहे उनको आपका अधिकार है उन लोगों को तपहीज जव सपमि है उनका सरवाइव करना उनके ऊपर सरवाइव कराना और उनकी जिम्मदारी उठाना आपका सरकार का फर्ज है। ब्यूरोक्रेसी का फर्ज है लेकिन आप ओल्ड ऐज पेंशन भी

रोक दी आपने। अभी हमारे बीजेपी वाले रोज स्टेटमेंट देते हैं कि जी ओल्ड एज पेंशन बंद है अरे भई जिनकी ओल्ड एज पेंशन बनी हुई है उनको तो दे दो। वो भी रोक ली। नये की बात करते हैं। तीसरा सर डीटीसी की बात करें मार्शल्स को सैलरी नहीं, सीधा सीधा वीमन की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। रिटायर्ड इम्पलॉइज की पेंशन के लिए पैसा नहीं, एएमसी गाड़ियों की होती है मेंटेनेंस के लिए उसके लिए पैसा नहीं तो ये कैसे काम चलेगा जल बोर्ड है सर जलबोर्ड में ना तो कोई सीवर का काम हो रहा ना कोई वाटर पाइप लाइन डालने का काम हो रहा ना जो है कोई एसटीपी एसपीसी बनने का काम हो रहा है क्योंकि फंड्स नहीं है तो ऐसा एटीट्यूड अगर फाइनांस डिपार्टमेंट का, चीफ सैक्रेट्री का, एलजी का होगा तो, मतलब लोगों का काम कैसे चलेगा, प्रोग्रेस तो छोड़ दीजिए आप, लोगों का वैलफेयर कैसा होगा। पैरामांउट वैलफेयर है लोगों का की लोगों का वैलफेयर हो। योगा कलास बंद कर दी सर पैसे की वजह से, पीडब्ल्यूडी के सारे प्रोजेक्ट रूके हुए हैं। अब डूसिब डिपार्टमेंट है सर, कितने सारे झूग्गी कैंपस है दिल्ली में, उन कैंपों में कोई डव्लपमैंट वर्क नहीं हो रहा। रीजन की पैसा नहीं है, पैसा क्यों नहीं है, फाइनांस से क्लीयर नहीं आती। तो कोई ना कोई हर डिपार्टमेंट आज सफर कर रहा है और उसके रिस्पोंसिबल कौन है। डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज एंड importantly सबसे ज्यादा फाइनांस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और ये किसके instance पर कर रहे हैं किसके instance पर काम नहीं कर रहे हैं, वो भी क्लीयर है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के instance पर ये लोग काम कर रहे है। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर की अगर आपको लोगों का वैलफेयर करना है और कराना है, तो जब तक किसी के खिलाफ स्ट्रीक्ट एक्शन नहीं होगा, तब तक ये गाड़ी आगे बढ़ेगी

नहीं। अब मान लिया जैसे कुलदीप कुमार जी ने कहा कि मैडीकल फैसलिटी या ट्रीटमैंट ना मिलने की वजह से हो सकता है किसी की डैथ हो गई हो। अगर वो आदमी, उस आदमी की फैमिली के लोग फंडामेंटल राइट का हनन होने पर, डैमेजिज क्लेम करने चले गये तो सरकार क्यों दे ये अधिकारी दें, जिन्होंने फाइल रोकी तो और होना चाहिये ऐसा सिस्टम में की अगर कोई अधिकारी जानबूझकर फाइल को रोकता है, डीले करता है और जिससे लोग प्रभावित होते हैं तो उस आदमी की सैलरी से या उस आदमी के एसैस्ट से वो रिकवरी होनी चाहिये। तो जो सर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें बहुत अच्छी accountability, responsibility fix की है और उम्मीद करते हैं कि सरकार जागेगी, चीफ सेक्रेटरी जागेंगे, एलजी साहब जागेंगे और इन लोगों के खिलाफ strict disciplinary action लेंगे और ताकि आगे से ऐसी डिफिकल्टी ना आ पाए। at least स्वास्थ्य सेवाएं, ओल्ड एज पेंशन इनको तो ना रोकें, समय देने के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक्यू वैरी मच।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद जून साहब, विनय मिश्रा जी।

श्री विनय मिश्राः बहुत-बहुत धन्यवाद, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे यहां दादादेव अस्पताल है, जहां पर महिलाओं और बच्चों का इलाज होता है। और स्पीकर साहब लगभग वहां पर डेली 700 से साढ़े आठ सौ ओपीडी पेशेन्ट्स आते थे। पीछे मुझे बहुत ज्यादा शिकायत मिलने लगी की बहुत ज्यादा chaos हो रहा है वहां पर, भीड़ सम्भल नहीं रही है और गार्ड जो है वो पर्ची काट करे हैं। मैं थोड़ा पता करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि जो हमारे डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स थे, वो वहां से हटा दिये गये हैं और मैं तो धन्यवाद करूंगा पिटिशन कमेटी का, इन्होंने संज्ञान लेकर

जो वो हमारे वहां पर जो 8 की संख्या थी वो आज फिलहाल तो 6 है लेकिन हम लोग उससे काम चला रहे हैं और अध्यक्ष जी आपको, जानकारी देना चाहूंगा की पूरी पश्चिमी दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर डिलीवरी कहीं होती है तो दादादेव अस्पताल में होती है। और कई बार आरकेएस की मीटिंग में भी ये बात उठी। और आरकेएस की मीटिंग में भी जब हमने पूछा फाइल कहाँ है तो उन्होंने बताया कि हैल्थ डिपार्टमेंट में है, कई बार हमने हैल्थ डिपार्टमेंट में बात की। लेकिन अंत में मामला समझ में आया की ये मामला फाइनांस सेक्रेटरी के यहां रूका हुआ है और जो पिटिशन कमेटी ने रिपोर्ट दी। जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी कल रात को हमारी, मुझे बड़ी हैरानी है कि हमारी जो विधान सभा की कमेटी है उसके प्रति इन ऑफिसरों का क्या रवैया है। मैं तो आपसे गुजारिश करना चाहूंगा। मुझे याद है इसी विधान सभा के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट से हम लोग फेसबुक जैसी एनटिटी के खिलाफ, जो फेसबुक एक प्राइवेट एनटिटी है, पूरी दुनिया में नामी कम्पनी है। उसको जब कमेटी ने विधान सभा में बुलाया था तो वो सुप्रीम कोर्ट गए थे उसके खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया था कि कमेटी जिसको बुलाएगी उसको कमेटी में आना पड़ेगा और कमेटी कुछ भी है, ंज चंत है पार्लियामेंट के, तो जो हमारा ऑर्डर आया था मैं आपसे गुजारिश करूंगा की उस ऑर्डर को जितने ये ऑफिसर हैं, इन ऑफिसरों के पास भेजा जाए ताकि वो उसको पढ़ें और उसको पढ़कर विधान सभा की कमेटियों को सिरियस्ली लेना शुरू करे और जो सिरियस्ली ना ले उसपर एक्शन हो। अब मैं तो एक बात और कहूंगा कि जैसे कोई अच्छा काम करता है तो उसको मोटिवेट करने के लिये अस्पतालों में हम जाते हैं राउंड लेने के लिये या स्कूल में जाते हैं राउंड लेने के लिये, तो जो टीचर या स्टाफ जो अच्छा काम करता

है उसकी फोटो वहां पर लगाये जाते हैं, मोटिवेट करने के लिये, इसने इस महीने में अच्छा काम किया, इम्पलोई ऑफ दा मंथ की फोटो लगाई जाती है। अस्पताल जाते हैं, तो एनओ ऑफ दा मंथ फोटो लगाई जाती है। मैं तो आपसे कहूंगा ऐसे ऑफिसर जो काम रोकते हैं, इनकी फोटो भी वहां लगाया जाए और साथ में लिखा जाए की ये वो नालायक हैं जिनकी वजह से काम नहीं हो रहा है अस्पतालों में या स्कूल के अंदर। नालायक ऑफ दा ईयर, नालायक ऑफ दा मंथ एक उपाधि दी जाए ताकि लोगों को पता चले की अगर ये अच्छा काम करने वाले हैं तो नालायक भी है हमारे पास। एलजी को उसके लिए ऑस्कर मिल जाएगा बता रहे हैं राजेश जी। साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कमेटी की रिपोर्ट बहुत जैनवन है और मैंने जो पढ़ा पूरी रिपोर्ट को, मैं कमेटी को बहुत बधाई देना चाहूंगा जिस शिद्दत के साथ इन्होंने इसपर काम किया और पूरी एक-एक जानकारी ली और जैसे-जैसे इन्होंने ऑफिसरों को बुलाकर उनसे बात की। फाइलें चुराने की बात का बताओ, फाइल लेकर आये हैं, मीटिंग में फाइल लेकर आए और कहते हैं कि जी फाइल नहीं और वही फाइल उठाकर। इतनी हिम्मत है कि वही फाइल उठाकर ले जाने की बात भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो शाबासी देनी चाहिये विधान सभा बुला के। आप समय-समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं, इस बधाइयों का ऐसा कार्यक्रम भी करो, इनको भी बुलाकर बधाई दो आप। ताकि वहां के एमएलएज को पता चले देखो ये भी ऐसे-ऐसे नालायक ऑफिसर भी हैं हमारे पास। अंत में, एक बात कहकर बात खत्म करना चाहूंगा, फिनलैंड में टीचर्स को भेजने का बड़ा विरोध हो रहा है। हमारे भाजपा के साथ नहीं है, नहीं तो मैं बताता की जब सबसे बड़ा, दूसरा विश्वयुद्ध जब हुआ तो सबसे बड़ा वार उसको कहा जाता है और उस

विश्वयुद्ध के दौरान जब इंग्लैंड के अंदर बजट पेश किया जा रहा था, तो उस समय के प्रधानमंत्री ने सभी मदों में कटौती की, चाहे वो हैल्थ हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सुरक्षा हो। पर उन्होंने एजुकेशन पर कटौती नहीं की थी। विपक्ष ने बहुत हंगामा किया, की इतनी बिल्डिंगे टूट गई हैं, आप उसको रिपेयर कराओ, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना टूट गया उसको रिपेयर कराओ। तो प्रधानमंत्री ने तर्क दिया था कि भइया बिल्डिंग तो बन जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर एक पीढ़ी खराब हो गई तो वो पीढ़ी कभी ठीक नहीं होगी। ये भाजपा वाले और कांग्रेस वाले 70 साल से पीढ़ी को इन्होंने खराब करके रखा और ये चाहते नहीं है कि कोई भी पीढ़ी ठीक हो और इनसे सवाल करे। आज मैं बहुत बधाई देता हूं आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को। आज हम लोग जाते हैं, विधान सभा में। नये-नये नौजवान, पढ़े-लिखे नौजवान, जब हम स्कूलों में जाते हैं तो हमसे सवाल करते हैं कि ये काम नहीं हो रहा है, ये विकास नहीं हो रहा है। आज हमारे जवाबदेही तय हुई है। तो ये जवाबदेही तय हुई है तो एजुकेशन की वजह से हुई है और उस एजुकेशन की वजह से आज हम लोग बाधय हो गए हैं अपनी-अपनी विधान सभा में ईमानदारी से काम करने के लिये और पूरे 24 घंटे देने के लिये क्योंकि अब जवाबदेही तय हो गई। सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। तो मैं बधाई दूंगा हमारे उप-मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी को, जो एजुकेशन पर, इन्होंने इतना काम किया और एजुकेशन को मुख्यधारा में लाकर, सरकार की मुख्यधारा में लाकर जो काम किया उसके लिये बहुत बधाई और पिटिशन कमेटी को भी बहुत-बहुत बधाई और मैं इनके सारे रिक्मन्डेशन के साथ शामिल हूं और मैं एक बात कहना चाहता हूं जब तक इनपर एक्शन ना हो इनको इमीडेटली उस पद से हटाना

चाहिये और कोशिश करनी चाहिये की जब तक इंक्वायरी कम्पलीट ना हो, ऐसे अफसरों को कोई सैंसिटिव पोस्ट ना दी जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। अब श्री अखिलेश पति त्रिपाठी, सौरभ भारद्वाज जी प्रस्ताव करेंगे की ये सदन दिनांक 18 जनवरी, 2023 को सदन में प्रस्तुत याचिका समिति के प्रथम अंतरिम प्रतिवेदन से सहमत है। श्री अखिलेश पति त्रिपाठी।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 18 जनवरी, 2023

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी ये जो सुझाव है ना, इनका हमारे एक मैंबर का सुझाव है इसको अगर हम रिक्मन्डेशन में शामिल कर लें कि 'वॉल ऑफ शेम' एक विधान सभा में बनाई जाए, 'शर्म की दीवार'। जिसमें जो ऑफिसर इस तरीके का कर रह हैं तो कम से कम उनकी तस्वीर एक महीने के लिये लगा कर हम लोग रख लें।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः ये प्रस्ताव है।

माननीय अध्यक्षः 'वॉल ऑफ शे' की बजाय 'वॉल ऑफ फेम', 'फेम' करिए 'शेम' ना करें।

श्री सौरभ भारद्वाजः ठीक है। सर एक फेम की भी बना दें, एक शेम की भी बना दें, दोनों बना लें सर।

श्री राजेश गुप्ताः पक्ष और विपक्ष तो वहां भी होगा ना जी।

माननीय अध्यक्षः आप दीजिए देखेंगे क्या हो सकता है, कानून क्या कहता है।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः माननीय सदस्य श्री सौरभ जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया मैं चाहता हूं कि आप उसको भी स्वीकार करें ये सदन। साथ में मैं माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 18 जनवरी, 2023 को सदन में प्रस्तुत याचिका समिति के प्रथम अंतरिम प्रतिवेदन से सहमत है, ऐसा मैं प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें,

जो इसके विरोध में है, ना कहे,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता प्रस्ताव पारित हुआ।

अब श्री अखिलेश पति त्रिपाठी, श्री सौरभ भारद्वाज प्रस्ताव करेंगे की यह सदन दिनांक 19 जनवरी, 2023 को सदन में प्रस्तुत याचिका समिति के द्वितीय अंतरिम प्रतिवेदन से सहमत हैं।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 19 जनवरी, 2023 को सदन में प्रस्तुत याचिका समिति के द्वितीय अंतरिम प्रतिवेदन से सहमत है।[1]

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें,

जो इसके विरोध में है, ना कहे,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता प्रस्ताव पारित हुआ।

अब श्री अखिलेश पति त्रिपाठी जी व सौरभ भारद्वाज जी प्रस्ताव करेंगे की यह सदन दिनांक 19 जनवरी, 2023 को सदन में प्रस्तुत याचिका समिति के तृतीय अंतरिम प्रतिवेदन से सहमत है।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 19 जनवरी, 2023 को सदन में प्रस्तुत याचिका समिति के तृतीय अंतरिम प्रतिवेदन से सहमत है।[2]

माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें,

जो इसके विरोध में है, ना कहे,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता प्रस्ताव पारित हुआ।

---

1. दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23137 पर उपलब्ध

2. दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23138 पर उपलब्ध।

अब श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय उप मुख्यमंत्री कार्यसूची में दर्शाए गए अपने विभाग से संबंधित दस्तावेज की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

उप मुख्यमंत्री: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिंदु क्रमांक-2 में दर्शाए गए दस्तावेजों की हिंदी और अंग्रेजी की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तूत करता हूं।

''31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली जल बोर्ड के लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के पृथक लेखा प्रतिवेदन'' की प्रतियां (हिंदी एवं अंग्रेजी)[3]

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय उप मुख्यमंत्री वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सप्लीमेंटरी डिमांड पेश करेंगे।

उप मुख्यमंत्री: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की पूरक मांगे प्रस्तुत करते वक्त उनको इंटरड्यूज़ करने के लिये आपकी अनुमति से कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। अभी मैं पूरा डिस्कशन सुन रहा था और किस तरह से हमारे पिटिशन कमेटी के साथियों ने एक-एक ऑफिसर से बात करके, ये देखा कि किस तरह से इस सदन से पास बजट के बावजूद चीजों को रोकने की कोशिश की गई और रोका गया। उन्होंने कई फैक्ट्स भी रखे सबने पिटिशन कमेटी के रूप में भी और कई सारे साथियों ने पिछले दो तीन दिन से मैं देख रहा हूं।

3. दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में सदर्भ संख्या आर-23139 पर उपलब्ध।

एक विधायक के रूप में भी अपने जहां जनता पेंशन की बात कर रही है, जल बोर्ड की बात कर रही है, काम रूक रहे हैं। जनता पीछे पड़ती है तो अल्टीमेट्ली जवाबदेही तो विधान सभा है ये। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि तमाम तरह की रोकने की कोशिश के बाद भी और ऑफिसर्स पर तमाम तरह के दबाव के बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को सरकार पर आगे बढाया गया है। यह अलग बात है कि अगर ये साजिशें नहीं होती तो शायद सौ की स्पीड से चल रहे होते। फिर 50 की स्पीड से चले हैं लेकिन लड़-लड़कर भी चलें हैं तो चले हैं। काम रूकने नहीं दिये हैं। शायद ये केजरीवाल जी के मुख्यमंत्रीत्व की और साथ-साथ हम सब लोगों की पूरी ओवरआल zeal की ताकत हैं कि काम रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद पिछले सात साल में काम कराए गए है और काम हुए है और काम हो रहे हैं। जनता के काम नहीं रूके। हमें लड़ना पड़ा उसकी हीट हमने छेलनी पड़ी अलग बात है लेकिन जनता के काम पेंशन दो महीने रोकी गई तो रोकी गई लेकिन फिर मिलीं। डॉक्टर्स की सेलरी दो महीने रोकी गई तो रोकी गई लेकिन फिर मिली। अल्टीमेट्ली चीजें आगे बढ़ी और काम हुए। तनख्वाहें भी मिलीं। बस ये है कि काम रूकता है तो जनता दर्द में आती है और जब जनता दर्द में आती है तो फिर वो सीधा अपने विधायक के पास ही आकर बात रखती है। लेकिन अच्छी बात है कि काम रूके नहीं हैं। मैं इस अनुपूरक अनुदानों की पूरक मांग में आपके समक्ष इस हाउस के समक्ष कुछ चीज़ें रख रहा हूं। उसमें काफी विधायकों के डिमांड रहती है, मुख्यमंत्री सड़क योजना में उनके प्रपोजल्स आये हुए हैं। तो सौ करोड़ मुख्यमंत्री सड़क योजना में एडिशनल फंड के रूप में और रख रहे हैं, सौ करोड रूपये। तीन सौ था तो चार सौ हो

गया। ट्रांस यमुना एरिया वर्क के कई सारे काम चल रहे हैं, उसका 49 करोड़ रुपये उसमें एडिशनल लगाया है। पीडब्ल्यूडी के रोड़ मैंटेनेंस के काम हैं कोर्ट की बिल्डिंग्स बनाने के काम है, एडिशनल क्लास रूम के काम हैं, re-modelling of hospitals के काम हैं, इसके लिए कुल करीब 800 करोड़ रुपये की राशि है जिसमें से 290 करोड़ रुपये रोड्स के बनाने पर, ब्रिजेज पर, मैंटेनेंस पर, इन सब पर खर्च करने के लिए एडिशनल फंड है। अठ्ठाईस करोड़ (28 करोड) रुपये कोर्ट की बिल्डिंग्स पर एडिशनल फंड है, 250 करोड़ रुपये एडिशनल क्लास रूम के बनाने पर फंड है और 28 करोड़ रुपये re-modelling of hospitals पर एडिशनल फंड है। जिसकी मैं डिमांड इस सदन के समक्ष लेकर आया हूं। सबसे महत्वपूर्ण डिमांड इस में है अध्यक्ष महोदय कई सदस्यों ने भी उसका जिक्र किया है जल बोर्ड के सम्बन्ध में। जल बोर्ड के पैसा रोककर इस सदन से बजट होने के बावजूद पैसा रोककर काम रोके गए और उसमें से कुछ ऐसी तकनीकी चीजें निकाली गई जो पिछले 20-20, 25-25 साल से जिस तरह से परम्परागत रूप से चीजें चल रही थी, प्रैक्टिस में आई थी, फाईनेन्शियल प्रैक्टिसेस में थी लेकिन उसके बावजूद नए नए बहाने बनाकर उनको रोका गया था। तो उन सारी चीज़ों को भी क्लीयर करते हुए जो ऑब्जर्वेशन्स रहे, ऑब्जेक्शन्स रहे और उन सब चीज़ों को ठीक करते हुए, क्योंकि बात जल बोर्ड की नहीं है, बात यमुना की सफाई की है। कल यहां पर तेजाब और काले स्याही मिलाकर पानी लेकर आये हुए थे बीजेपी के लोग कि साहब यमुना साफ नहीं हो रही, यमुना साफ नहीं हो रही। उससे पहले काली पगड़ी बांध कर आये हुए थे। असल में तो काले कारनामे इनके हैं कि ये विधान सभा बजट पास करके देती है फिर इनके एलजी साहब कहते हैं कि ये वाला पास

बजट अगर अधिकारियों को दे दिया ना काम करने के लिए तो तुमको सस्पैंड कर देंगे। तो उसमें कुछ ना कुछ तकनीकी बहाने, तकनीकी चीज़ें निकाल-निकालकर उसको रोका गया। तो उन चीज़ों को भी दूर करते हुए, क्योंकि यमुना की सफाई का काम रूकना नहीं है और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने अगर कहा है कि अगले चुनाव से पहले यमुना साफ होगी तो होकर रहेगी। उसके लिए जो भी करना पड़े जैसे भी करना पड़े और मुख्यमंत्री जी चौबीस घंटे वो बाकी चीजों में भी बिज़ी रहते हैं लेकिन लगातार वॉट्सअप पर फोन पर हर छोटी-छोटी चीज़ की प्रोग्रेस की रिपोर्ट लेते हैं कि कौन सा नाला साफ हो रहा है। कौन से नाले में गिरने वाला कौन सा नाला साफ हो रहा है। कहां पर पानी की प्रोब्लम हैं कहां पर एसटीपी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहां पर और साफ पानी ट्रिटिड पानी कहां जा रहा है। इस सबकी लगातार वो लेते रहते हैं तो यमुना को साफ करने के काम को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए और इसमें कोई अडंगा ना अड़ाये इस तरह की टैक्निकल चीजें फंसाकर तो इसको लेकर 600 करोड़ रुपये डीजेबी को अलग से दिये जा रहे हैं और कुल मिलाकर ऐसे देंखे तो 1028 करोड़ रुपये हैं जिसमें कुछ लोन का भी है, कुछ ग्रांट्स का भी है और एडिशनल फंड भी है तो 1028 करोड़ रुपये एडिशनल फंड के रूप में डीजेबी को दिये जा रहे हैं। साथ-साथ में irrigation & flood जो बड़े नालों की सफाई का काम करता है उसको भी 74 करोड़ 91 लाख रुपये करीब 75 करोड़ रुपये एडिशनल फंड के रूप में दिये जा रहे हैं। तो ये यमुना की सफाई के काम को आगे बढ़ाना मुख्यमंत्री जी का कमिट्मेंट है। मुख्यमंत्री जी की रेगूलर विजिट में चल रहा है। मुख्यमंत्री जी की रेगूलर मॉनिटरिंग में चल रहा है और यमुना की सफाई को आगे बढ़ाने के ही

इन अनुपूरक जो अनुदान की पूरक मांगे है इसमें महत्वपूर्ण कम्पोनेंट मैं मानता हूं इसको इससे ये काम और seamless तरीके से निर्बाध तरीके से आगे बढ़ेगा यमुना की सफाई का। तो यमुना की सफाई के लिए इस पैसे को मैं इस सदन के समक्ष रखता हूं इस डिमांड को। आठ करोड़ रुपये छठ घाटों के लिए एडिशनल खर्चा है, छठ घाटों के निर्माण के लिए मैं उसके लिए भी डिमांड रखता हूं। शहीद परिवारों के लिए देश की अब तो दूसरी सरकार है एक मात्र नहीं कह सकते। पहले हम कहते थे एकमात्र है पर इन सबने मेहनत करके पंजाब में भी सरकार बनवा दी जरनैल सिंह जी वहां के इंचार्ज रहे, तो अब दो सरकारें हैं देश में जो शहीद परिवारों को एक–एक करोड़ रुपये की सहायता राशि देते हैं इमिडिऐड उसमें पंजाब की सरकार भी देती है और दिल्ली सरकार भी देती है। वो चाहे दिल्ली के डिफेंस के पर्सनल्स हों या पुलिस के पर्सनल्स हों, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लोग हों, सिविल डिफेंस हो, कोरोना वारियर्स भी हों, उनको भी सरकार लगातार उनके परिवार को भी एक–एक करोड़ की मदद दे रही है। तो उस मद में 25 करोड़ रुपये की एक्ट्रा राशि मैं सदन के समक्ष मांगने के लिए आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सदन की अनुमति उसको मिलेगी। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा के लिए 50 करोड़ रुपये की एक्ट्रा राशि मैं इस सदन में डिमांड के रूप के रूप में लेकर आया हूं। एससी, एसटी, ओबीसी फंड्स में 75 करोड़ रुपये की एक्ट्रा फंड की जरूरत है। जिसमें स्कूल के जो प्राईवेट स्कूलों के बच्चे हैं उनकी भी फीस दी जानी है और post metric scholarship का भी काम होना है। जो सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी हैं पेंशन मिलती है जिनको वो पैंशनर्स कर्मचारी हैं जो है उनके डीजीएचएस उनका इलाज का भी सरकार डीजीएचएस में देती है तो 50 करोड़ रुपये वहां जरूरत है।

हॉस्पिटल्स के लिए अब क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी रोका पैसा रोका था तो एक ये आया था कि भई हॉस्पिटल के फंड में पैसे की कमी होती है और वहां हॉस्पिटल में अपने-अपने फंड पास फंड की कमी होती है हॉस्पिटल्स के पास में। तो 364 करोड़ रुपये हॉस्पिटल्स के लिए अलग से डिमांड मैं लेकर आया हूं। हायर एजुकेशन में युनिवर्सिटीज को सैलरी के लिए और अपने कार्यो के लिए अलग पैसा चाहिए। इसमें डीयू के भी कुछ कॉलेजिज हैं जो ठीक से चल रहे हैं जो नियम कायदे कानूनों को फॉलो करते हुए चल रहे हैं उनकी भी सैलरी और उनकी जितनी डिमांड थी उस सबको भी मिलाकर हायर एजुकेशन के लिए 78 करोड़ रुपये की एक्ट्रा डिमांड मैं लेकर आया हूं। समग्र शिक्षा अभियान 199 करोड़ रुपये, बच्चों की युनिफार्म की सब्सिडी में 130 करोड़ रुपये और मिड-डे मील में 114 करोड़ रुपये की एक्ट्रा डिमांड को लेकर आया हूं। लॉ डिपार्टमेंट various crime victims के लिए मदद करता है अलग-अलग crime victims के लिए तो 60 करोड़ उसमें और जो वकीलों के लिए सीएम मुख्यमंत्री जी की योजना है वकीलों के सहयोग के लिए उसमें 10 करोड़ रुपये की एडिशनल डिमांड की जरूरत है। साथ-साथ Hon'ble Delhi High Court और Civil और Session Courts में अलग-अलग कार्यो के लिए जिसमें सैलरीज में भी क्योंकि सरकार स्पीडी जस्टिस के लिए जितने नम्बर ऑफ कोर्टस आगे बढाना पड़े, जितना अप्वाइंट करना पड़े लॉ डिपार्टमेंट है सरकार का उस दिशा में काम करता है और कर रहा है तो सैलरीज वेजिज और ईवन कुछ मैडिकल के ईशूज भी हैं। मैडिकल में फंड में उनके ट्रीटमेंट के फंड में भी इस तरह से 311 करोड़ रुपये की पूरक मांग कोर्टस के लिए दोनों हाई कोर्ट और सिविल एंड सेशन कोर्ट के लिए मैं सदन के समक्ष लेकर आया हूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण

पूरक मांगें हैं लेकिन जैसा मैने इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग शिक्षा और स्वास्थ्य और इन सब पर तो जो है ही कैपिटल वर्क पर, यमुना को साफ करने का काम नहीं रूकने दिया जाएगा। इस विधान सभा ने पहले भी बजट पास करके दिया है। ये विधान सभा अभी बजट देगी और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इसी स्पीड पर हम और तेजी से इस स्पीड को बढाते हुए यमुना को साफ करने का काम करते रहेंगे। इस सब्मिशन के साथ ऑनरेबल स्पीकर सर I present first batch of supplementary demands for grants for the financial year 2022-2023 before this House, Thank you.

माननीय अध्यक्ष: DEMAND NO. 1 (Legislative Assembly)

जिसमें Revenue में 1 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 1 पास हुई।

DEMAND NO. 2 (General Administration)

जिसमें Revenue में 7 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 2 पास हुई।

DEMAND NO. 3 (Administration of Justice)

जिसमें Revenue में 3 अरब 31 करोड़ 21 लाख 22 हज़ार रुपये तथा Capital में 7 करोड़ रुपये, कुल राशि 3 अरब 38 करोड़ 21 लाख 22 हज़ार रुपये हैं, सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 3 पास हुई।

DEMAND NO. 4 (Finance)

जिसमें Revenue में 4 लाख रुपये हैं, सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 4 पास हुई।

DEMAND NO. 5 (Home)

जिसमें Revenue में 46 करोड़ 50 लाख 73 हज़ार रुपये तथा Capital में 1 लाख रुपये, कुल राशि 46 करोड़ 51 लाख 73 हज़ार रुपये हैं, सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 5 पास हुई।

DEMAND NO. 6 (Education)

जिसमें Revenue में 2 अरब 20 करोड़ 81 लाख 79 हज़ार रुपये, तथा Capital में 2 लाख रुपये, कुल राशि 2 अरब 20 करोड़ 83 लाख 79 हज़ार रुपये सदन के सामने है -

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 6 पास हुई।

DEMAND NO. 7 (Medical & Public Health)

जिसमें Revenue में 95 करोड़ 7 लाख 2 हज़ार रुपये तथा Capital में 2 लाख रूपये हैं, कुल राशि 95 करोड़ 9 लाख 2 हज़ार रुपये रुपये सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 7 पास हुई।

DEMAND NO. 8 (Social Welfare)

जिसमें Revenue में 49 लाख 40 हज़ार रुपये तथा Capital में 12 अरब 11 करोड़ 47 लाख रूपये हैं, कुल राशि 12 अरब 11 करोड़ 96 लाख 40 हज़ार रुपये सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 8 पास हुई।

DEMAND NO. 9 (Industries)

जिसमें Revenue में 36 करोड़ 52 लाख रुपये तथा Capital में 48 करोड़ 11 लाख रूपये हैं, कुल राशि 84 करोड़ 63 लाख रुपये सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 9 पास हुई।

DEMAND NO. 10 (Development)

जिसमें Revenue में 7 अरब 6 करोड़ 14 लाख 77 हज़ार रुपये तथा Capital में 4 लाख रूपये, कुल राशि 7 अरब 6 करोड़ 18 लाख 77 हज़ार रुपये है, सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 10 पास हुई।

DEMAND NO. 11 (Urban Development & Public Works)

जिसमें Revenue में 3 अरब 77 करोड़ 63 लाख 50 हज़ार रुपये तथा Capital में 21 लाख रूपये, कुल राशि 3 अरब 77 करोड़ 84 लाख 50 हज़ार रुपये, सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

Supplementary Demand No. 11 पास हुई।

हाउस ने कुल मिलाकर Revenue में 18 अरब 14 करोड़ 52 लाख 43 हज़ार रुपये तथा Capital में 12 अरब 66 करोड़ 88 लाख रुपये, कुल राशि 30 अरब 81 करोड़ 40 लाख 43 हज़ार रुपयों की Supplementary Demands को मंजूरी दे दी है।

The Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2023

(Bill No. 02 of 2023)

अध्यक्ष महोदयः- अब माननीय उप मुख्यमंत्री The Delhi Appropriation (No. 1)

Bill, 2023 को House में Introduce करने की permission मांगेंगे।

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः Hon'ble Speaker Sir, I seek permission of the House to introduce The Delhi Appropriation (No. 1)

Bill, 2023 to the House.[4]

माननीय अध्यक्षः- माननीय उप मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ।

---

4. दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23135 पर उपलब्ध।

माननीय अध्यक्षः- अब माननीय उप मुख्यमंत्री Bill को सदन में Introduce करेंगे।

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः Hon'ble Speaker Sir, I introduce The Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2023 to the House.

माननीय अध्यक्षः- अब Bill पर Clause-wise विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड-2, खण्ड-3 व Schedule बिल का अंग बनें-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

खण्ड-2, खण्ड-3 एवं Schedule बिल का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खण्ड-1, Preamble और Title Bill का अंग बनें-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

खण्ड-1, Preamble और Title Bill का अंग बन गये।

माननीय अध्यक्षः- अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि The Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2023 को पास किया जाए।

माननीय उप-मुख्यमंत्रीः Hon’ble Speaker, Sir, the House may now please pass the The Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2023

माननीय अध्यक्षः- माननीय उप मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

The Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2023 पास हुआ।

माननीय अध्यक्षः अब लंच ब्रेक पौने तीन बजे तक के लिए। पौने तीन बजे हाउस दोबारा बैठेगा। धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 2.45 बजे पुनः संवेत हुआ

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए

माननीय अध्यक्षः मैं माननीय सदस्यों से एक नम्र निवेदन कर रहा हूं ये वेल का, कोरम का, सदन की मर्यादा का हम धयान नहीं रख रहे हैं और ये उचित नहीं है किसी भी सदन के लिए, मैक्सिमम 30-40 दिन सदन लगता है और उसमें भी हम अनुशासनहीनता रखते हैं, ये उचित नहीं? प्लीज आगे इसका धयान रखें। इसे लाइट कर दीजिए, ऑन करिये।

महेंद्र गोयलः कल एक मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल का, जिसके अंदर कल एक राजनीतिकरण किया गया। एक डिपार्टमेंट की तरफ से बोला गया है कि महेंद्र गोयल ने कभी भी एसीबी के अंदर शिकायत नहीं दी।

माननीय अध्यक्षः कौन से डिपार्टमेंट से बोला गया।

महेन्द्र गोयलः एन्टी करप्शन ब्यूरो। एसीबी, जो आज के पेपरों के अंदर ये हैड लाइन के तौर पर ऊपर में आया हुआ है। एक पेपर में नहीं है, सभी पेपरों के अंदर में आया हुआ है।

माननीय अध्यक्षः आपने दी है कि।

महेन्द्र गोयलः जबकि मैंने आरटीआई के जरिये वो लेटर दिए हुए हैं, उसके बाद एन्टी करप्शन ब्यूरो से इनके जवाब आए हुए हैं। ये एन्टी करप्शन ब्यूरो का ही तो लेटर होगा, मैं ये कहूंगा कि जूम करके एक बार इसको दिखाया जाए।

माननीय अध्यक्षः चलिये ठीक है।

महेन्द्र गोयलः ये डीसीपी ऑफिस से ये आरटीआई के लेटर है। ये घूम के मतलब सारे के सारे जो लेटर आ रहे हैं, ये एन्टी करप्शन ब्यूरो से है। ये जो चीजें हम।

माननीय अध्यक्षः मैं सदन को जानकारी दे दूं इस विषय में, समय आगे कम है, चर्चाएं ज्यादा हैं प्लीज़। बैठिए-बैठिए-बैठिए। ये अखबार की कॉपी, आप सदन को दे दें।

महेन्द्र गोयलः मैं सदन को ये अखबार की कॉपी भी भेज रहा हूं और जिस डिपार्टमेंट ने इस प्रकार से अपना बयान दिया है। वो आज एक प्रैस रिलीज भी जारी करें कि ये शिकायत हमारे पास में आयी हुई थी। डीसीपी के यहां से भी और आरटीआई के जरिये जो मैंने पिछली और उन्होंने मेरे पास भी लेटर भेजा है। ये किसी की छवि को खराब करना, कहीं तक उचित नहीं है। एलजी साहब के यहां से भी मैंने टाईम मांगा था, उनको लेटर देकर आया था। मैं परसों भी एसीबी गया था, बल्कि उन्होंने डायरी नंबर तक नहीं दिया एक डेट डाल के दे दी क्योंकि जो अभी नये टेंडर के बारे में मैंने खुलासा किया था कि वहां पर इस समय के अंदर ये नर्सिंग अर्दली का एक टेंडर हुआ है, जिसके अंदर वहां पर पैसों का लेन देन हो रहा है, जिसकी मैं खुद रिटन के अंदर शिकायत देकर आया हूं और इस प्रकार के।

माननीय अध्यक्षः महेन्द्र जी मैं सदन को जानकारी देंगे।

महेन्द्र गोयलः बचकानी बयानबाजी होगी तो, ये किसी की छवि को खराब करने के लिए मैं सभी व्यक्तियों से, सभी सदस्यों से एक ही आग्रह करना चाहूंगा या कोई भी पार्टी है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसका

स्पष्टीकरण होना चाहिए और सही रुप के अंदर होना चाहिए ताकि जनता का न्याय जनता की इस अदालत के द्वारा वो मिल सके, ये मैं आपके समक्ष में रख रहा हूं और ये अखबार की कॉपी आपके पास में रख रहा हूं और ये मैं पूरा का पूरा एक बंच आपको टेबल कर रहा हूं। पैसे जो मेरे पास में आए थे, एसीबी के आदमी आपके द्वारा जो बुलाये गये हैं वो आपके ऑफिस के अंदर उनको मैं हैंड ओवर कर रहा हूं। जो तीन लाख रुपए की राशि मेरे पास में आयी थी।

माननीय अध्यक्षः मैं सदन को जानकारी में दे दूं। कल जो महेन्द्र गोयल जी ने ये घटना, बैठिये आप महेन्द्र जी। इस घटना का सदन पटल पर उस राशि के साथ जिक्र किया था। एसीबी के अधिकारियों के यहां कॉल कर लिया था, एसीबी के इंस्पेक्टर, एसीपी आये हुए हैं, वो पैसा उनकी कस्टडी में दे दिया विद कंप्लेंट। वो पैसा गिन रहे हैं और आगे की कार्यवाही, मैं उसमें देखूंगा कैसे करना है, क्या करना है। श्रीमान राजेन्द्रपाल गौतम जी, धयानाकर्षण नियम 54 के अंतर्गत नशे की तस्करी तथा यौन व नशे की बढ़ती लत के कारण दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री का धयान आकर्षित करेंगे।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इतनी महवपूर्ण विषय पर सदन का और दिल्ली के गृह मंत्री जी का धयान आकर्षित करने के लिए मुझे मौका दिया। ये जो मुद्दा है नशे का, ये दिल्ली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक मुद्दा है। नशे की वजह से दिल्ली के युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। अवैध शराब, चरस, गांजा, अफीम, स्मैक, हीरोइन, कोकिन और नाना प्रकार के नशे खास तौर पर रिसेटलमेंट कॉलोनी के अंदर बहुत ही

आसानी से उपलब्ध है और बहुत ज्यादा मात्रा में अवैध नशे का कारोबार जोर-शोर से बढ़ रहा है और नशे की वजह से दिल्ली के युवाओं का भविष्य अंधकार की तरफ तेजी से जा रहा है। हमने पंजाब के अंदर देखा कि किस तरह से पंजाब के युवाओं की जिंदगी को नशे ने बर्बाद किया तो पंजाब की जनता ने अपने वोट का इस्तेमाल करके वहां की सरकार को बदलने का काम किया। जो दूसरी सरकार आयी 2017 में, उसने भी नशे पर कोई रोक नहीं लगाई तो पंजाब की जनता ने वहां की उस सरकार को भी बदलकर हमें मौका दिया। लेकिन दिल्ली में समस्या दूसरी है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस ये दोनों माननीय एलजी साहब के पास है। तो अगर हमारे पास होता दिल्ली की सरकार के पास और हम अगर इस नशे को नहीं रोक पाते तो दिल्ली की जनता चुनावों के माधयम से, वोट के माधयम से हमको हटा देती लेकिन चूंकि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर दोनों उपराज्यपाल महोदय के पास है तो अफसोस दिल्ली की जनता के पास ये विकल्प नहीं है कि वो उपराज्यपाल को हटा पाए और मैं कुछ ऐसे डाटा आपके सामने रख रहा हूं।

एम्स में एक स्टडी करवाई ऑल इंडिया मेडिकल ऑफ साइंसेस ने मेडिकल साइंसेस ने और इस रिपोर्ट में पूरा सर्वे करने के बाद उन्होंने 46 हज़ार 410 बच्चों का सर्वे किया। सर्वे से ये निकल कर आया 91.14 परसेंट स्ट्रीट चिल्ड्रन वो नशे के गिरफ्त में हैं 91.14 परसेंट, मतलब इतनी बड़ी मात्रा में अगर बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं और नशा आसानी से उपलब्ध हो रहा है और नशे को रोकने के लिए, नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए मुझे ये सदन को बताते हुए यह सोचकर दु:ख पैदा हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर मैंने पुलिस को भी लिखा, मैंने पुलिस कमिश्नर को भी लिखा, मैंने राज्यपाल जी

को भी लिखा उपराज्यपाल जी को और इनसे पहले उपराज्यपाल थे, मैं उनसे पर्सनली जाकर मिला। यहां तक कि मैंने कुछ जगह का वो डाटा दिया कि इन इन जगह पर नशा बिकता है। अनफोर्चुनेट्ली उपराज्यपाल महोदय ने जो प्रोमिस किया था, उस प्रोमिस के बावजूद वो नशा बिकना बंद नहीं हुआ। नशा आसानी से आज भी उपलब्ध है।

मैं सदन के माधयम से और माननीय दिल्ली के गृह मंत्री जी के माध्यम से चाहता हूं कि ये लिखित में यहां से जाना चाहिए होम मिनिस्ट्री को कि हमने जब पुलिस के नोटिस में ला दिया, हमने डीसीपी की नोटिस में ला दिया, हमने कमिश्नर के नोटिस में ला दिया, हमने उपराज्यपाल जी के पर्सनली मिलकर नोटिस में ला दिया, उसके बाद नशा बंद क्यों नहीं हो रहा, आसानी से उपलब्ध क्यों है। ये जो बच्चे आये दिन नशे की गिरफ्त में कोई "लूड सूंघ रहा है, कोई छोटा सा 15 साल का बच्चा स्मैक ले रहा है और पार्कों के अंदर कहीं भी चले जायें, पार्कों के अंदर लोग पार्क इसलिए डेव्लप किये कि लोग अपने परिवार के साथ सुबह-शाम पार्क में घूमने जायें लेकिन आज अफसोस की बात ये है कि पार्कों के अंदर बैठ कर बच्चे इंजेक्शन से ड्रग्स ले रहे हैं और वो जो सिगरेट की जो वो होती है, उसके ऊपर रखकर स्मैक पी ले रहे हैं खुलेआम, तो क्या वो सब दिख नहीं रहा। क्या मतलब दिल्ली को नशे का हब बनाना चाहते हैं उपराज्यपाल महोदय। आखिर नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए दिल्ली की पुलिस और उपराज्यपाल गंभीर क्यों नहीं दिखते।

ये जो घटना घटी है, जिसमें सुल्तानपुरी से लेकर कंझावला तक 12 किलोमीटर तक एक युवती को गाड़ी में जिस तरह मतलब उसको घसीट कर ले जाया गया, ऐसा नहीं हो सकता कि चलाने वाले को पता नहीं चले कि

गाड़ी के नीचे कोई आया है, आपने किसी को मार दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो क्लीयरकट मर्डर है चलो देर आये दुरूस्त आये, उसमें मर्डर चार्जेज का परसों लगा दिये लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो रिजल्ट आए ये भी आए कि वो चलाने वाले थे और जो अंदर बैठे थे वो सब नशे में थे। यानी की ये नशा कई प्रकार के अपराधों को जन्म दे रहा है, कई प्रकार के अपराधों को। देखने में ये आ रहा है कि जो बच्चे नशे के आदी हो जाते हैं वो फिर नशे की पूर्ति के लिए पहले अपने घर में चोरी करते हैं और उसके बाद वो आस-पास में चोरी करते हैं फिर रोबरी करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। एनसीआरबी का एक डाटा है, जो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। प्रस्तुत करना चाहता है। इस एनसीआबी के डाटा में सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है कि रेप के केसिज़ बाकी केसिज़ की तुलना में सबसे ज्यादा दिल्ली में रेप के केस बढ़ गये हैं, जिसमें एक साल में 1250 रेप केसिज़ हैं और इसमें से चाइल्ड रेप 841 हैं चाइल्ड रेप और sexual assault on children वो 497 हैं। ये डाटा बड़ा भयावह कर देने वाला है। ये डाटा बताता है, एनसीआरबी का डाटा, ये अपराध करने वालों में 47.7 परसेंट तो इसमें जुवैनाइल है, जो 18 साल से भी कम के बच्चे हैं। इन बच्चों का क्या भविष्य बनेगा। दिल्ली के बच्चे लगातार नशे की तरफ जा रहे हैं। जब बच्चे को बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा तो दिल्ली का भविष्य अंधकार में होगा। यानी पूरे भारत का भविष्य अंधकार में होगा। ये मुद्दा कोई सीमापुरी विधान सभा का नहीं है। ये मुद्दा पूरे दिल्ली का है। पूरे दिल्ली के अंदर खासतौर पर रिसैटलमेंट कॉलोनी हैं, जो झुग्गी बस्ती हैं, जो गरीब बस्ती हैं, वहां बहुत ज्यादा मात्रा में अवैध नशा बिक रहा है और

नशे की ही वजह से ये अपराध बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली में अगर अपराध को रोकना है, तो नशे को रोकना बेहद जरूरी है।

तो मैं माननीय मनीष सिसोदिया जी के माधयम से और सदन का माधयम से, आपके माधयम से चाहता हूं कि इसपर एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर या तो ये मैटर कमेटी को सुपूर्द कर दिया जाए और कमेटी पुलिस को बुलाए या जो नार्कोटिक विभाग को देखते हैं, उनको बुलाए। यदि एक्साइज को दखते हैं, उनको बुलाएं। उनसे बुलाने के बाद इसपर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर ये भारत सरकार के पास जानी चाहिए कि ये मसला देश के युवाओं का है। दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ बाकी राज्यों में भी धीरे धीरे इसी तरह नशा बढ़ेगा तो इसका नशे का रुकना जरूरी है। अगर नशा नहीं रूका तो देश का भविष्य खतरे होगा। मैं चाहता हूं आपके माधयम से इस गंभीर मुद्दे का संज्ञान लिया जाना चाहिए और नशे का यह कारोबार पूरी तरीके से बंद होने चाहिए अन्यथा और डाटा तो ये भी बताता है कि इस नशे की वजह से जो क्राइम बढ़ा, उस क्राइम में भी सबसे ज्यादा जो केसिज हैं, वो कमिट किये हुए हैं, वो rape, outrage of modesty of women, robbery, theft and murder बाकी टाइप के केसिज की तुलना में ये केसिज ज्यादा बढ़े हैं और इसी की वजह से दिल्ली के अंदर रात को कहीं भी आप अगर ट्रेन से, मैट्रो से उतरते हैं और उसके बाद आप को थोड़ा भी पैदल अपने घर जाना पड़ जाए तो रास्ते में या तो आप मोबाईल और आपकी जेब सब कुछ छीन ली जायेगी। तो इस तरीके से दिल्ली में इस अपराध को रोकने के लिए, इस अवैध नशे के कारोबार को रोकना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं इसके ऊपर विस्तार से चर्चा भी करवायी जानी चाहिए और इसपर कुछ न कुछ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः मेहरोलिया जी।

श्री रोहित कुमारः धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी आपने इतने गंभीर और महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया है। जो चर्चा की शुरूआत हमारे वरिष्ठ साथी माननीय सदस्य हमारे गौतम जी ने बात रखी है कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं जितना ड्रग्स अन्य जितना भी नशीले पदार्थ जो खुलेआम बिक रहे हैं तकरीबन सभी विधान सभा क्षेत्रों के अंदर ये हालात हैं। अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। निश्चित तौर से अगर मैं अपनी त्रिलोकपुरी विधान सभा का उदाहरण इस सदन के सामने रखूं, आपको जानकर हैरानी होगी। मैं शुरूआत एक ऐसे वाक्ये से करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे एक मित्र ने मुझे व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजा। मुझे फोन पर बोला कि रोहित भाई मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। अब तो त्रिलोकपुरी में हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। ये देखिये बच्चे खुलेआम किस प्रकार से अपना बर्थ डे मनाते हैं। बीच चौक के ऊपर टेबल सजाकर, चौराहे के ऊपर और साथ में बड़े-बड़े चाकू रखे हुए हैं, तलवार रखी हुई हैं, यहां तक कि पिस्टल रखी है, उसका मैगजीन रखी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, वो फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब मैंने वो केक के साथ में ये पिस्टल और ये सारे चाकू और ये सब चीजें देखी तो मैं हिल गया कि निश्चित रूप से हमारे यहां बहुत ज्यादा अपराध बढ़ रहा है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पैरो के नीचे से जमीन निकल गयी जब मैंने अगली फोटो पर नज़र डाली कि बैकग्राउंड में मेरा घर नजर आ रहा था। ये पिक्चर के बैकग्राउंड को मैंने जूम किया तो मैंने पाया कि बैक ग्राउंड में मेरा घर नजर आ रहा है, सामने तो

बच्चे भी मेरे आस-पड़ोस के ही थे। इन बच्चों को जिनको मैंने पहचाना, मैंने तुरंत उनके माता पिता को अपने घर पर बुलाया एक-एक करके। उनको समझाया कि आपका बच्चा देखो बुरी संगत में है और कहीं भी इस प्रकार के जो है एक-दो बच्चे पहले से इस तरह की विसंगतियों में पड़े हुए हैं, गलत संगत में पड़े हुए हैं, किसी भी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो आपके बच्चे का भी नाम उसमें आयेगा तो उसमें दो-चार लोगों ने तो उनको समझा लिया लेकिन जहां तक कि पुलिस की बात करूं मैं कि कितने हालात ये बद्तर होते जा रहे हैं, मैं लगातार पुलिस के अंदर शिकायत कर रहा हूं। एसएचओ, एसीपी, डीसीपी, एल जी साहब को भी मैंने इसके लिए पत्र लिखा था, ये तमाम शिकायत पत्र मेरे सामने उनकी कॉपी है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर अपने यहीं से शुरूआत करता हूं। मेरे घर जहां मैं रहता हूं ब्लॉक नंबर 17, त्रिलोकपुरी में।

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले एक साल में मेरे घर की परिधि के अंदर मात्र 50 मीटर, 50 मीटर इतना होता है, जितनी दूर हमारी गाड़ी भी खड़ी होगी, शायद वो भी दूर होगा। जितनी दूर हमारी गाड़ी खड़ी होंगे, वो भी शायद दूर होगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक साल के अंदर 50 मीटर की परिधि में दो-दो मर्डर हो जाते हैं। एक के बाद एक और वो भी दिन के ऐसे समय में जिस समय बच्चे वहां पर खेल रहे होते हैं, महिलाएं बैठी होती हैं, दुकानें खुली हुई हैं, भीड़-भाड़ का इलाका है, शाम को 4 बजे वहां पर एक 20 साल के लड़के का मर्डर हो जाता है,ये 8 अगस्त, 2022 को 20 साल के एक युवक की चाकू से गोद कर बिल्कुल मेरे घर के नजदीक, वहां पर चाकू से उसकी हत्या कर दी गयी। उसी से ठीक लगभग 6 महीने पहले रात के ग्यारह-बारह

बजे कुछ लोगों ने शराब पी, नशा किया और एक को चाकू मार दिया। उस लड़के को मार दिया गया। ब्लॉक नंबर, मैं अभी आपको पूरी विधान सभा की बताऊं, मेरे अपने तो एक साल में दर्जनों मर्डर किया और हत्याओं जैसे प्रयासों के वारदातें पचासों वहां पर हो गयी हैं। लेकिन, मैं अभी आपको केवल 500 मीटर में भी गिनवा दूं, जहां मैं रहता हूं तो आप पाएंगे कि दर्जनों वारदातें एक साल के अंदर यहां पर हो चुकी है। ब्लॉक नंबर 29 के अंदर एक लड़के को चाकू से गोदकर मार दिया गया। ब्लॉक नंबर 9 में एक कारोबारी युवक को 4-7-2022 को दिन दहाड़े चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गयी। 27 ब्लॉक के अंदर एक लड़के की हत्या कर दी गयी। ब्लॉक नंबर 15 का चौराहा जो अग्रवाल स्वीट की दुकान है, वहां बहुत भीड़ भाड़ रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, 4 महीने के अंतराल पर दो लोगों की हत्या दिन दहाड़े उसी चौराहे के ऊपर कर दी गयी। आज ये तमाम लिस्ट मैं आपके सामने करके बताऊं ब्लॉक नंबर 6 की बात है, ब्लॉक नंबर 9 के अंदर एक लड़के को शाम को आठ बजे करीब मार दिया गया। ये एक साल के अंदर दर्जनों, ये लिस्ट है मेरे पास सारी। ये बहुत बड़ा कारण है कि जितने अपराधी हैं, वो बिल्कुल बेखौफ हो, बेखौफ होकर घूम रहे हैं। बिल्कुल पुलिस का, कानून का डर, खौफ उनकी नजर में बिल्कुल नहीं आता है। लगता नहीं है कि उनको किसी प्रकार का डर है। मेरे इलाके के अंदर छोटे छोटे बच्चों के नाबालिग लड़कों के गैंग बने हुए हैं, जिनमें गैंगवार हो रही है। वो एक दूसरे को चाकू से मार कर हत्या कर देते हैं। कितने ही लोगों की हत्या इसमें हो गयी है, गैंगवार में लोग मर गये हैं। इनकी शिकायत मैंने की हैं। अलग अलग नाम के गैंग बने हुए हैं। इनको संचालित करते हैं उम्र दराज लोग। बच्चों से वो अपराध करवाते हैं क्योंकि

उन्हें पता है कि जुवेनाइल कोर्ट में जाएंगे तो उनको कोई सजा होगी नहीं। पहले से उन बच्चों का इस प्रकार से ब्रैनवाश किया हुआ है। उन्हीं से वो नशे का कारोबार भी करवाते हैं। उन्हीं बच्चों से वो अपराध करवाते हैं क्योंकि हमारा कानून ऐसा बना हुआ है कि वो उन्हीं को पकड़ता है। उनके जो मुख्य आका है, उन तक वो चीजें वो नहीं पहुंचती हैं। हमारे अपने त्रिलोकपुरी की मैं बताऊं, ब्लॉक नंबर 32 के अंदर खुलेआम वहां पर नशे बिक रहे हैं। चरस, गांजा, स्मैक तमाम तरह के जितने नाम हमारे माननीय सदस्य गौतम जी ने अभी बताए, ये तमाम तरह के नशे खुलेआम वहां पर बिकते हैं। 19 ब्लॉक की मैंने शिकायत रिसेंट्ली अभी की है, इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। नशे बिक रहे हैं, तमाम तरह के नशे बिक रहे हैं। मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं यहां पर, मैंने जब पुलिस में शिकायत की। मेरे कार्यकर्ता साथी मेरे पास आए कि रोहित भाई हमारे यहां ब्लॉक नंबर 32 में बहुत ज्यादा नशा बिक रहा है और ये सब पुलिस की छत्रछाया में हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तुम इसका कोई एविडेंस लेकर आओ । वो लड़का अपनी जान पर खेलकर उनकी विडियो बनाकर लेकर आता है मेरे पास में, वो विडियो अब मैंने पुलिस के अंदर दी। मैंने एसीपी को पहले वो विडियो भेजी कि देखिए खुलेआम ये नशे बिक रहे हैं, ये आदमी किस प्रकार नशे लेकर, खरीद कर जा रहे हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं हैं।

पुलिस की कार्यवाही अपने आप में चौंकाने वाली है कि पुलिस ने क्या किया। हमारा जो कार्यकर्ता है, पुलिस उसके घर पर पहुंची, चलो भाई बाहर निकल, कहां-कहां नशा बिक रहा है, हमारे साथ चल हमें बता। आप यहां से अंदाजा लगा लिजिए कि एक शरीफ आदमी क्या वो बताने जाएगा इस घर

में बिक रहा था, ये ये आदमी बेच रहा था, वो बेच रहा था। अगर पुलिस को ऐविडेंस के साथ में शिकायत दे दी गयी है, पुलिस का क्या ये बनता है कि उस आदमी को, शिकायतकर्ता को, घर से लेकर जायें कि बता कहां-कहां बिक रहा है। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि लोग डरे रहे, सहमे रहे और जितने भी इस प्रकार के धंधों में लिप्त जो लोग हैं, इस गोरखधंधे में जो भी अवैध नशे का जो कारोबार चल रहा है, ये पूरा का पूरा पुलिस की छत्रछाया में, उनकी सरपरस्ती में चल रहा है और माननीय एलजी साहब जो कि दिल्ली के अंदर कोरी राजनीति करने में लगे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेन्टेन करें और नशे के ऊपर काबू करें और दिल्ली पुलिस आप अरविंद केजरीवाल को देकर देख लिजिए। एक हफ्ते के अंदर, मैं गारंटी देता हूं इसके ऊपर रोक भी लगेगी और अपराधी जेलों की सलाखों के पीछे भी आपको नजर आयेंगे, ये बहुत दिल की बात मैं आपको ये बता रहा हूं, ये गहराई की बात है। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य, पूरी दिल्ली का दुर्भाग्य है कि ऐसे एल.जी. साहब जोअपने आपको दिल्ली का रहनुमा बताते हैं, अपने आपको जो एडमिनिस्ट्रेटर बताते हैं, अपने आपको अभिभावक बताते हैं, आज उनकी सरपरस्ती के अंदर देखिए किस प्रकार आज, खुलेआम में छोटी-छोटी उम्र के लड़के आज नशे के आदि होकर तमाम तरह के, इस प्रकार के गोरख धंधों में न केवल लिप्त हैं बल्कि अपराधों में शामिल हो रहे हैं। आज न केवल मेरी त्रिलोकपुरी विधान सभा बल्कि हर विधान सभा में लोग, हर शरीफ आदमी खौफ के साये में जीने को मजबूर है और सिर्फ इसलिए कि हमारी पुलिस पूरी तरीके से निकम्मेपन पर, पूरी तरीके से अपना जो उसको काम करना है उसको सही ढंग से अंजाम

नहीं दे पा रही है और आज पुलिस अगर ढंग की होती तो जितने अपराध ी हैं, जितने इस प्रकार के गोरख धंधों में लिप्त लोग हैं उनको...

(समय की घंटी)

श्री रोहित कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जितने भी इस प्रकार के धंधो में लिप्त लोग हैं उनको पुलिस का डर होता, कानून का डर होता, लेकिन जब कानून ही उनका सरपरस्त बनकर ये तमाम तरह के धंधों में लिप्त होकर काम कराता है तो उनको किसी प्रकार का डर नहीं है। और मैं हमारे माननीय साथी गौतम जी को मैं धन्यवाद करूंगा कि जो चर्चा इन्होंने यहां पर शुरू की है, आपको भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने अहम चर्चा के लिए यहां पर समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद-धन्यवाद। जय भगवान जी।

श्री जय भगवान: आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी के अंदर सभी लोग अपने बच्चों के पालन पोषण करने के लिए यहां पर आए हैं कि बच्चों का विकास हो। और जो मां-बाप हैं वो दिन-रात मेहतन करके बच्चों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए लगातार लगा रहता है। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी में तो कुछ और ही हो रहा है। गली-गली, कूचे-कूचे के अंदर सट्टा, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, धड़ल्ले से बिक रही है। आप जहां पर भी देखेंगे, किसी भी, जैसे कि माननीय राजेंद्र

पाल गौतम जी अभी बोल रहे थे बीच में कि रिसेटलमेंट कॉलोनियों के अंदर सबसे ज्यादा दारू, चरस, अफीम, सट्टा, गांजा, स्मैक बिक रही है। ये आप किसी भी कॉलोनी, दिल्ली की किसी भी कॉलोनी के अंदर जाकर देख सकते हैं। हर कॉलोनी के अंदर बहुत ही ज्यादा धड़ल्ले से और पुलिस की शह में दारू, चरस, अफीम, सट्टा, गांजा, खूब बिक रहा है सर। बार-बार कंप्लेंटें दी जाती हैं, मैंने खुद कई बार अपने लेटर-हेड से, जब मैं काउंसलर था तब भी, जब मैं एम.एल.ए. बना तब भी, कई लगातार मैंने कंप्लेंटें एसएचओ, एसीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी, जॉइंट सीपी और होम मिनिस्ट्री और एल.जी. साहब, सभी को दी है सर। मेरी तो इतनी मोटी फाइल है दिल्ली पुलिस के खिलाफ। और अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी ये जो युवा पीढ़ी है, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो 16-16 साल, 18-18 साल, 21 साल के बच्चे हैं, ये हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारा आने वाला भविष्य है, अगर इनका ही भविष्य अंधकारमय हो जाएगा तो हमारा जो भविष्य है वो क्या होगा, ये हम सभी को सोचने की आज जरूरत है। क्योंकि, क्योंकि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनका हम पालन पोषण कर रहे हैं वो नशे के आदि हो जाएंगे, उनको नशे की लतें लग जाएगी। अभी जैसे ये सिनपक की बात कर रहे हैं हम, इंजेक्शन की बात कर रहे हैं हम, अलग-अलग चीजें लेकर के बच्चे अलग-अलग तरह के, नए-नए नशे आ गए हैं और दिल्ली पुलिस का इस पर कोई धयान नहीं है। दिल्ली पुलिस तो अच्छा ये चाहती है कि उनको पैसा मिलता रहे। अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि अब दिल्ली के जो थाने हैं वो उगाही के अड्डे बन गए हैं क्योंकि वहां पर समाज के लिए, सुरक्षा के लिए कोई, कोई मुद्दा नहीं है। जो स्लोगन है, जो दिल्ली पुलिस का स्लोगन है, वो आपने देखा

होगा, शांति-सेवा-न्याय, लेकिन मैं जो देख रहा हूं, नातो किसी को शांति मिल पा रही है, न किसी की सेवा हो रही है और न ही किसी को न्याय मिल पा रहा है। क्योंकि बेकसूर लोगों को, जिन लोगों ने कसूर किया है उनकी जगह बेकसूर लागों को उसमें भेज दिया जाता है और वो बेचारे परेशान होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों।

आज बहन-बेटियों के साथ हत्या, बलात्कार, छीना झपटी लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ती जा रही है। लगातार रेप के कांड हो रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे आज का जो मुद्दा है, कंझावला के अंदर जिस बहन के साथ में ये घिनौना अपराध हुआ, एक तो शर्मनाक है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जिस प्रकार से ये कांड हुआ है और पहले भी दिल्ली के अंदर कईऐसी चीजें हो चुकी हैं तो दिल्ली पुलिस को तो पहले ही संभल जाना चाहिए था लेकिन लगातार, दिल्ली पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके कानों पर कोई जूं नहीं रेंगती, वो लोग लगातार यही सोचते हैं कि बस हमारी जेब में पैसा कैसे आए।

मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। चाहे मैं इनकी ट्रैफिक पुलिस की बात करूं, ट्रैफिक पुलिस प्वाइंटों पर खड़ी नहीं होगी, वो साइड में जाकर अपनी जेबें भर रही होगी, साइड में रोकते हैं, चाहे वो किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कोई घंटों जाम में फंसा रहे, चाहे कोई बीमार रहे, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस को कोई मतलब नहीं है।

दूसरा मैं बात करूं 100 नंबर कॉल की, तो जब गरीब लोग फोन करते हैं तो 100 नंबर की गाड़ी भी नहीं आती उनके पास। पुलिस का जो आईओ है वो भी उनके घर नहीं पहुंचता जबकि उसकी जिम्मेदारी है।

अध्यक्ष महोदय, लगातार दिल्ली पुलिस और डीडीए की शह से जो हमारे मास्टर प्लान रोड़ हैं, जो हमारे अर्बन एक्सटेंशन रोड हैं उन पर लगातार अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस की शह से हो रहा है सारा काम। दिल्ली पुलिस पैसा लेकर के और वहां पर कब्जे कराती है। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अगर अपना 25 गज का, 15 गज का या 50 गज का प्लॉट बनाता है तो उनके घर पर भी दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है, फटाफट उनको पता लग जाता है ये घर बना रहा है, तो ये दिल्ली पुलिस के काम हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय एल.जी. साहब को जो उनके काम हैं, जैसे डीडीए उनके पास है तो वो रोकें कि डीडीए की जमीन पर जो अवैध कब्जे हो रहे हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा कराए जा रह हैं, जो माफिया लगातार कब्जे कर रहा है उसको वो रोके, ये एलजी साहब के काम हैं। और एलजी साहब को लॉ एंड ऑर्डर पर दिल्ली पुलिस को बड़े टाइट तरीके से लेना चाहिए।

एक चीज़ और बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि कई बार, जैसे लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं वो अपराध की, जब बढ़ने के बाद में ये दिल्ली पुलिस को भी सहना पड़ता है। आपने पेपरों में भी पढ़ा होगा कई पुलिस, जैसे अभी पांच-छः दिन पहले, दस दिन पहले एक वारदात हुई, एक स्मैकिये ने दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को चाकू मार दिया। ऐसे कई हत्याएं दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल हैं, एएसआई हैं या दूसरे लोग हैं उनकी हत्या हो गई हैं। ये किस ने की है, सारे नशेबाजों ने की है, क्योंकि इन्होंने नशे को बढ़ावा दिया है।

तो मेरा आपके, सदन के माधयम से ये कहना है कि नशे को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार जो नशा बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से जो हमारा जो समाज है वो बिल्कुल, बहुत ज्यादा परेशान, जैसे कि अभी हमारे रोहित महरौलिया जी ने बताया कि मेरे इलाके अंदर लगातार हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो मैं भी बता दूं कि बवाना के इलाके में आपको सभी को पता ही है और नशे का कारोबार इतना बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि जो फैक्ट्री एरिया है, मुझे लगता है कम से कम बीस पच्चीस शराब, अवैध शराब की गाडियां आती होंगी पर-डे, इतनी अवैध शराब वहां पर बिकती है। अलग-अलग कॉलोनियों के अंदर अवैध शराब बिकती है। अलग-अलग सट्टे के, चाहें मैं सैक्टर-24 की बात करूं, चाहें मैं सैक्टर-25 की बात करूं...

(समय की घंटी)

श्री जय भगवान: चाहें मैं शाहबाद डेयरी की बात करूं, चाहे मैं बवाना जे.जे. कॉलोनी की बात करूं, बहुत ही भारी तादात में वहां पर स्मैक भी बिक रही हैं, सट्टा भी चल रहा है। तो अध्यक्ष महोदय मैं यही चाहता हूं कि यहां पर इन चीजों पर अच्छी तरीके से लगाम लगाई जाए और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय दिल्ली पुलिस के द्वारा पीडब्लूडी के रोड़ों पर भी घेराबंदी की जाती है, दादागिरी दिखाई जाती है। दो जगह पीडब्लूडी के रोड़ पर, जबकि मैंने कोशिश की है, प्रयास किया है लगातार, मैंने उनके जो सीपी साहब है उनको भी और जॉइंट सीपी साहब को भी लेटर दिया और डीसीपी को भी बोला। हमारे दो, बवाना रोड़ पर दो जगह, कंझावला चौक पर और शाहबाद डेरी के आगे, जबकि हम उस रोड़ को चौड़ा कर रहे हैं और वहां

पर बूथ बना दिया गया जबरदस्ती। तो मेरा निवेदन है ये बूथ भी हटाये जायें और जो दिल्ली पुलिस के द्वारा लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कि अभी बहन-बेटियों के साथ में स्नैचिंग, स्नैचिंग की वारदातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। हमारी बहन-बेटियों के साथ स्नैचिंग, चोरी-चकारी, छीना-झपटी ये भी बहुत ज्यादा वारदातें हो रही हैं। जबकि थानों के अंदर जो रिकार्ड जो दिखाए जाते हैं वो आधे और अधूरे दिखाए जाते हैं। तो मेरा आपसे ये ही निवेदन है...

माननीय अध्यक्षः कंक्ल्यूड करिए, अब कंक्ल्यूड करिए जय भगवान जी प्लीज।

श्री जय भगवानः सदन के माधयम से कि इस पर ज्यादा से ज्यादा और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस को लाँ एंड ऑर्डर मजबूत करना चाहिए। एल.जी. साहब को लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करना चाहिए, क्योंकि एल.जी. साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने काम को अच्छी तरीके से करें, लेकिन एल.जी. साहब तो मुझे लग रहा है कहीं और ही भटक रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द। जय भारत। नमस्कार।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद-धन्यवाद। अब माननीय सामाजिक कल्याण मंत्री-राज कुमार आनन्द जी चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय समाज कल्याण मंत्री (श्री राजकुमार आनन्द): धन्यवाद अध्यक्ष जी, पूरा देश जानता है कि दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की है। आज दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था कायम

करने में दिल्ली पुलिस और केन्द्र शासित बीजेपी के गृह मंत्रालय अपनी जिम्मेदारियां निभाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली में जुवेनाइल क्राइम बाकि राज्यों से बहुत ज्यादा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राजेंद्र पाल गौतम जी का, जिन्होंने इतने अच्छे गंभीर मुद्दे पर चर्चा चालू की। दिल्ली में जुवेनाइल क्राइम बाकि राज्यों से कई गुणा ज्यादा है। दिल्ली में 15-15, 17-17 साल के बच्चों के लिए चाकूबाजी और मर्डर करना बहुत आम बात हो गई है। स्नैचिंग और लूटपाट करना बहुत आम हो चली है। चाकू-छुरी छोटी उम्र के बच्चों की जेब में ऐसे डालकर चलते हैं जैसे कंघे डालकर चलते हों। ऑनलाइन साइट, अमेजन जैसी प्रतिष्ठित ऑनलाइन साइट पर ऐसे-ऐसे चाकू आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, फ्री होम डिलीवरी मंगा सकते हैं, जिससे आदमी का, वो अगर कोई चाकू मार दे तो कुछ भी नहीं बचेगा और ये इस सबकी मुख्य वजह है छोटी उम्र के बच्चों में बढ़ती हुई नशाखोरी। दिल्ली सरकार इस सारे मुद्दे पर बहुत गंभीरता से संज्ञान लेने को तैयार है लेकिन हमारे हाथ में दिल्ली पुलिस नहीं है। जय भगवान जी ने ठीक कहा कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में दे दो। गृह मंत्रालय और एल.जी. साहब दिल्ली को सुरक्षा देने में नाकामयाब है। तो दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एक बार अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में देकर देखें तो पता लगेगा कि दिल्ली कैसे ठीक होगी। बाकि हम इसको संज्ञान में लेकर इस पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई कराने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः अल्पकालिक चर्चा नियम-55 के अंतर्गत, श्री मदन लाल जी, हाल ही में कंझावला में एक लड़की की दर्दनाक मौत होने के परिपेक्ष्य में कानून व्यवस्था पर चर्चा आरंभ करेंगे।

श्री मदन लालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया है। 16, 17, 18, 19, पिछले 4 दिनों से हम केवल यहां एल. जी. साहब के कुकृत्य और उनकी एजेंसिस, चाहें वो दिल्ली पुलिस हो, चाहें वो डीडीए हो, चाहें उनके सरकारी ऑफिसर हों, उनके ही बारे में लगातार चर्चा करते रहे हैं। आलम ये है कि दिल्ली सरकार के हर काम को ठप्प करने के लिए, रोड़ा अटकाने के लिए एल.जी. साहब ने पूरी जान लगा रखी है। पूरे ऑफिसर्स को इस तरह तैनात किया है कि कोई भी काम जो दिल्ली में अब तक सुचारू रूप से चल रहे थे वो होने बंद हो जायें। यही कारण है कि चाहें शिक्षा के क्षेत्र में, चाहें चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहें वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहें सिविल डिफेंस का मामला हो, चाहें सैलरी हो, कहीं भी देखो, हर जगह से केवल एक शिकायत आ रही है कि दिल्ली सरकार के वो डिपार्टमेंट्स जो एल.जी. साहब के कंट्रोल में नहीं है, सेंटर के कानून के मुताबिक, इस देश के कानून के मुताबिक अब तक लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, इनको छोड़कर सारे सब्जेक्ट्स दिल्ली सरकार की चुनी हुई सरकार पर हैं। तो हर संभव कोशिश की जा रही है इन कामों को रोकने की। पर कहीं-कहीं हम देखते हैं कि दिल्ली सरकार के अलावा जो सब्जेक्ट एल.जी. साहब के पास हैं वहां भी वो सही तरीके से काम नहीं करवा पा रहे हैं। वो पुलिस को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं या पुलिस को जानबूझकर ऐसा करने की छुट उन्होंने दे रखी है। वो चाहें सर्विस का मेटर हो, सर्विस के ऑफिसर्स ने जिस तरीके

से आज सुबह से चर्चा रही कि चाहे वो हैल्थ सेक्रेटरी हो, चाहें वो फाइनांस सेक्रेटरी हो, चाहें चीफ सेक्रेटरी हों, हर फाइल को, हर काम को रोकने की हर संभव कोशिश की है। अब तो ऐसे लगता है जैसे एल.जी. साहब ने कसम खा ली है कि दिल्ली सरकार को कैसे फेल किया जाये, उसके लिए कैसे प्रयत्न किए जायें, वो लगातर सुबह से शाम तक इसी पर चिंता करते हैं। पुलिस का डिपार्टमेंट उनके पास डायरेक्ट है, पर क्या पुलिस सही तरीके से काम कर रही है?

31 तारीख दिसंबर को दिल्ली में एक दुर्घटना हुई, एक कार का एक्सीडेंट हुआ, कार से एक लड़की को टक्कर लगी और वो लड़की उस कार के पहिये के बीच में फंस गई, शुरूआती तौर पर ये देखने में एक्सीडेंट लगता था, पर उन लोगों ने सुल्तानपुरी से लेकर कंझावला तक उस लड़की को 12 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी में फंसे हुए जानबूझकर, देखने के बावजूद भी घसीटे रखा। इस दौरान बहुत सारे पुलिस-कर्मी भी रास्ते में दिखे, 3-3 पीसीआर की गाड़ियां भी नजर आई, पुलिस को कॉल भी हुई, उस लड़की के साथ वाली दूसरी लड़की निधि ने भी कॉल की, वहां एक विनोद नाम का शॉपकीपर था उसने भी कॉल की और उसने लगातार कई बार कॉल की परंतु ना उस लड़की को किसी ने देखा, ना उस रात को गाड़ी को किसी ने नहीं देखा और वो गाड़ी को पार करके वो अपराधी सारे अपने-अपने घर चले गये। जब सुबह पता चला, शोर मचा तो पुलिस ने आनन-फानन में एक 304-ए का मुकद्मा दर्ज कर लिया। 304-ए है, गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की जान ले लेना, पर क्या ये गफलत और लापरवाही थी? किसी लड़की को एक्सीडेंट मारने के बाद 12 किलोमीटर तक आप सड़क पर घसीटते रहे, ये तो एक्सीडेंट के बाद

का जो कृत्य है वो तो सीधा-सीधा मर्डर है क्योंकि जब उस लड़की को आप घायल अवस्था में घसीट रहे हो तो आपको पता है कि वो मरेगी और आप उसको मारना चाहते थे, आपके मारने की इच्छा भी हो गई और आपको मारने का मोटिव भी हो गया कि किसी तरह ये लड़की मरे तो हमारे खिलाफ कोई गवाह न होगा। अगले दिन लोगों ने शोर मचाया। 304-ए बहुत छोटी धारा है, दो साल की सजा और ज्यादातर केसों में थाने से बेल तो होती है, ज्यादातर केसिस में प्रोबेशन पर छुट जाते हैं, भई आगे मत करना ये अपराध। मैं क्रिमिनल लॉयर रहा हूं, मैंने जिदंगी में इक्का-दुक्का केस में सजा होते देखी है जहां गाड़ी कमर्शियल न हो, ये गाड़ी कमर्शियल नहीं थी, ऐसे केस में कोर्ट बहुत ज्यादा सख्त नहीं होती। परंतु 304-ए का केस, जब शोर मचाया, 2 तारीख को हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत बड़ा डेमोस्ट्रेशन एल.जी. हाउस पर किया, वो बताना चाहते थे कि पुलिस इसमें अच्छा एक्शन नहीं ले रही है। तीन तारीख को हमारे बहुत सारे एम.एल.ए. दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिले और गुहार लगाई कि ये 304-ए का केस नहीं है बल्कि ये हत्या है और इसके लिए 302 का केस होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जब कभी भी एक्सीडेंट होता है, तो हमने बहुत सारे केसिज़ में देखे हैं कि एक्सीडेंट करने वाला आदमी गाड़ी से एक्सीडेंट करने के बाद भाग जाता है और घायल पड़ा हुआ आदमी अपनी मदद के लिए गुहार लगाता रहता है और अगर समय पर उसकी जान, उसकी मदद कर दी जाए तो उसकी जान बच जाती है। पर ये लगातार ऐसा रहा कि लोग सड़क पर तड़पते रहे, मरते रहे पर किसी ने परवाह नहीं की। बहुत सारे हालतों में लोग डरते रहें कि कहीं पुलिस तंग करेगी।

परंतु ये दिल्ली की पहली सरकार है माननीय केजरीवाल जी की कि उन्होंने एक नई स्कीम लागू की दिल्ली में, जो 'फरिश्ता' नाम से जानी जाती है। वो 'फरिश्ता' स्कीम क्या थी कि जो कोई भी घायल अवस्था में पड़े हुए किसी घायल व्यक्ति को, एक्सीडेंट के विक्टिम को अस्पताल पहुंचायेगा तो पहला काम तो होगा उस अस्पताल की जिम्मेवारी कि वो अस्पताल उसका पूरा खर्चा, चाहे वो लाखों में हो, 10-20-30-40-50 लाख भी हो, तब भी वो अस्पताल प्राइवेट भी दिल्ली सरकार के माननीय केजरीवाल जी के खर्चे पर उस घायल व्यक्ति की मदद करेंगे, इलाज करेंगे, ये पहला काम था। दूसरा था, जो उस घायल व्यक्ति को अस्पताल लेकर गया हो उसको 2 हजार रूपये देंगे कि उसका समय खराब हुआ, उसके कपड़े शायद खराब हुए और एक सर्टिफिकेट देंगे कि वाह क्या फरिश्ता था, किसी की जान बचा दी।

परंतु ये दरिन्दे ना तो उस लड़की को घायल हालत में देखने के बाद गाड़ी रोककर निकालने की कोशिश करते हैं, न उस लड़की को कोई मेडिकल-एड तक दिलवाने की कोशिश करते हैं बल्कि लगातार घसीटते रहते हैं। और ये बात पुलिस अच्छी तरह जानती है जब कोई ऐसा कृत्य करता है तो वो 304-ए का अपराधी नहीं है, वो 304 का भी नहीं है, जो शोर मचाने के बाद, जब हमारे MLAs ने एल.जी. हाउस पर डेमोस्ट्रेशन किया तो उनका स्वागत वॉटर कैनन से किया गया। एल.जी. साहब के यहां गुहार लगाने के बाद कमिश्नर साहब के पास गए, कमिश्नर साहब ने सुना, वो भी अनसुना हुआ। उसके बाद कैंडल मार्च किया 4 तारीख को, तब भी नींद नहीं खुली। स्वाति मालीवाल जी ने शोर मचाया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बातें कही, उसके बाद 304 धारा में उस मुकद्मे को तब्दील किया गया। 304 क्या है, 304 है culpable

homicide not amounting to murder कि मारने की इच्छा हो सकती है पर उद्देश्य कोई नहीं है और सजा है आजीवन, पर ये तो बात नहीं बन रही थी। उनके पीछे तो उनका उद्देश्य सीधा-सीधा था कि किसी तरह ये मर जाए और मर कब जाए, जब आप इसको घसीटते रहेंगे तो मारने की इच्छा पैदा हुई, मारने का मोटिव हो गया, तो 302 में परिवर्तित होना था परंतु इसके बाद भी पुलिस लास्ट के 16 दिन तक केवल उस मुकद्मे को लंबा लटकाए रखी जानबूझकर क्योंकि उनमें से एक अपराधी बीजेपी का लीडर था। मनोज गोयल नाम का एक व्यक्ति, मित्तल, मनोज मित्तल, उस गाड़ी में सवार था जो बीजेपी का लीडर था, बीजेपी का उसको बचाना जरूरी है, ये पहले भी करते आए हैं। बहुत सारे मुकद्मे, मैं धाराएं नहीं एक्सप्लेन करूंगा पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के बड़े अपराधी, किसी बड़े नेता के खिलाफ ईवन किसी एम. पी. के खिलाफ और तो और बहुत बड़े के खिलाफ रेप के चार्जिज आए, वो बाद में रेप के चार्जिज हनीट्रैप में कंप्लेनेंट को ही पकड़वाने में साबित हुए। हमें सोचकर, सुनकर, देखकर अचरज होता है कि जो लड़की कंप्लेनेंट हो इन केसिज़ मे उसी पर हनीट्रैप का मुकद्मा और अपराधी बार-बार बचते रहें क्योंकि बीजेपी के थे। यहां भी यही था। मनोज मित्तल नाम के आदमी को बचाने के चक्कर में पुलिस लगातार कोशिश करती रही कि 304-ए, गफलत-लापरवाही से केस में जो एक्सीडेंट हुआ है उससे आगे न बढ़ने दे पर 17 तारीख को लास्ट के दिन अब जब इतना ज्यादा शोर मचा है तो पुलिस को वो कार्रवाई करनी पड़ी और 302 में इस मुकद्मे को तब्दील करना पड़ा।

माननीय अध्यक्षः मदन लाल जी कंक्लूड करिए प्लीज।

श्री मदन लालः महोदय, ऐसे अपराधियों को जब तक सख्त से सख्त सजा का डर न होगा, नहीं होगा तब तक ये अपराधी लगातार अपराध करते रहेंगे इसलिए जरूरी है कि ऐसे मामले में जो पुलिस की कार्यवाई है जिसके अंतर्गत 10-11 पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन की अनुशंसा की है कार्रवाई नहीं की है, ये कार्रवाई नहीं है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चहिए। ऐसे अपराधियों से निबटने के लिए special court establish करनी चाहिए और उनको एक time bound, framed time में ऐसे मुकद्मों को सुनाने के लिए बाधय किया जाना चाहिए जिससे ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सजा मिले और जिस तरह का ये जघन्य अपराध है ऐसे लोगों को केवल एक सजा है और वो है मौत की सजा। उस लड़की को जिस तरीके से तड़पा के मारा गया है। ये एक example create करना चाहिए परंतु अब बहरी सरकार जो केन्द्र में बैठी है उनका नुमांयदगी जो आंखों पर पट्‌टी बांध ` बैठे हैं वो लगातार केवल इस कोशिश में हैं कि दिल्ली को किस तरह बदनाम किया जाए फिर चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो। फिर चाहे डीडीए ही क्यों ना हो, चाहे वो सर्विसिज़ के अधिकारी क्यों ना हों उन्होंने तो कसम खा ली है कि किसी भी डिपार्टमेंट के किसी आदमी की डिपार्टमेंट की बढाई ना हो जाए, हर तरफ हाहाकार मचे कि दिल्ली अपराधियों का अड्‌डा हो गई है। महोदय, मैं आपके माधयम से इस केस में पुलिस की लीपापोती एलजी का मूल दर्शक बना रहना, पुलिस कमिश्नर का मूक दर्शक बनकर कोई एक्शन ना लेना की भर्त्सना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में लोग इनको सबक सिखाएंगे और एक एग्जाम्पल क्रियेट करेंगे कि इस तरह की जो हरकत लोग कर रहे हैं लोग उनको बर्दाशत नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं आपके

माधयम से ये बात उन बहरे और अंधे लोगों तक भी पहुंचे जो इन बातों की अनदेखी और अनसुना करते हैं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान दुर्गेश पाठक जी।

श्री दुर्गेश पाठकः बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। पिछले कुछ दिन कहें या पिछले कई साल कहें मुझे लगता है कि सदन में भी इस तरह की घटनाओं पर कई बार चर्चा हुई है। मीडिया के माधयम से टीवी डिबेट में भी कई बार हम लोग गए हैं दिल्ली पुलिस की कि किस तरह से वो दिल्ली को चला रहे हैं इसके उपर कई बार चर्चा होती रहती है। मेरा जो आपका धयान इसके मूल में ले जाना चाहता हूं कि जो ये सारी चीजें हो रही हैं उसका एक कारण क्या है और उसका एक समाधान क्या हो सकता है। मैं देख रहा था कि कल से हाउस में अखिलेश जी के नेतृत्व में पिटिशन कमेटी की रिपोर्ट आई, राजेन्द्र गौतम जी ने एक अपना प्रस्ताव रखा, अगर मूल में जाएं तो एक ही चीज़ निकल के आता है कि चाहे वो दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो दिल्ली की पुलिस हो ये जनता के प्रति रिस्पोंसिबल नहीं हैं। इनका कोई कमांड नहीं है। हम लोकतंत्र के अंदर हैं लोकतंत्र में ये कहा गया था भई लोग इंसाफ देंगे लोग सारी चीजें डिसाइड करेंगे लेकिन दिल्ली की जनता का इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। किसी भी तरह से ये दिल्ली की जनता के प्रति रिस्पोंसिबल नहीं है। मैं एक अपने ऊपर हुए, बीते हुए एक एग्जेम्पल से मैं आपको एग्जेम्पल देना चाहता हूं। यहां पर सारे लोग बैठे हैं अभी मैं पांच-छः महीने पहले ही विधायक बना हूं नया-नया विधायक बना और आप सब लोगों ने राजेंद्र नगर

के अंदर खूब काम किया। जब चुनाव का रिजल्ट आया, चुनाव से जब हम लोग बाहर निकले तो आप सभी लोगों ने चाहें वो पक्ष रहे हो, चाहें वो विपक्ष के रहे साथी यहां पर नहीं है। आप सब लोगों ने मुझे बधाई दी लेकिन साथ में एक चीज़ और भी कहा कि यार तुम्हारे यहां पानी की बड़ी समस्या है इसको ठीक करना है। मैं तो अपना एग्जेम्पल देता हूं कि जून के आखिरी महीने में रिजल्ट आया जुलाई में पानी के ऊपर हम लोगों ने काम शुरू किया सौरभ भाई यहां पर है नहीं लेकिन उन्होंने बड़ी मदद की। जलबोर्ड के अधिकारियों को भी सलाम करता हूं जेई जैडआरओ, एक्सईन लेवल तक के हमने एक महीने के अंदर कॉलोनी वाईज की ये इस कॉलोनी में इतनी पानी आता है इतने पानी की जरूरत है। ये तीन चीजें अगर कर दी जायें तो इस कॉलोनी के अंदर पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। हमने एक से सवा महीना लगाया और हर कॉलोनी की कैसे पानी की समस्या खत्म होगी ये हमने रिपोर्ट ले के जमा करा दी जलबोर्ड के अंदर। हमने कहा जी अब इसके उपर काम शुरू किया जाए। पिछले पांच महीने से मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। कभी जलबोर्ड जाता हूं, कभी जैडआरओ जाता हूं, कभी फलां जाता हूं, कभी डिमाक जाता हूं, कभी इनके पास जाता हूं, पता क्या चलता है कि जलबोर्ड को फंड ही नहीं दिया है फाइनांस सैक्रेट्री ने और ये मुझे लगता है मेरी समस्या नहीं है मुझे लगता है पहले तो मुझे लगा हो सकता है मेरी ही समस्या है बाद में मैंने अपने साथियों को फोन किया यार तुम्हारे यहां पैसा आ रहा है क्या? तो इन्होंने कहा जी हमारे यहां भी नहीं आ रहा तो ये लगभग-लगभग पूरी दिल्ली के अंदर ये समस्या है। आप सोचिए, कि पानी जैसी मूलभूत समस्या के ऊपर भी ये जो नौकरशाह हैं ये जो आईएएस ऑफिसर हैं जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं ये सीरियस नहीं हैं और इनका

ये भी लक्ष्य है कि दिल्ली के लोगों को पानी ना मिले। हमारे यहां कई सारे बोर रिबोर हुए 10-12 रिबोर कराए गए। रिबोर हो गए उसमें4-4 हजार रूपये, 3-3 हजार रूपये का मोटर लगता है कि वो मोटर लग जाए और मोटर से वो रिबोर स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा दुर्भाग्य स्थिति है कि जलबोर्ड के पास आज एक लाख रूपये भी नहीं है कि मोटर लगाया जा सके। इससे ज्यादा संगीन स्थिति क्या हो सकती है। इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या हो सकती है। आज मदनलाल जी ने जो बात कही राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो बात कही, सच्चाई तो ये है कि जिस दिन एसएचओ हमारा फोन उठा लेता है हम बड़े खुश होते हैं ये वाला एसएचओ ठीक है, ये वाला डीसीपी बड़ा ठीक है, ये वाला एसीपी तो फोन उठा लेता है। इसको तो मैसेज भेज दो ओके भी लिख के दे देता है। आप सोचिए कि दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों की ये स्थिति हो गई है कि अगर हमारा फोन भी एसएचओ उठा लेता है तो हमें होता है चलो आज तो ये वाला एसएचओ ठीक है इस स्थिति में है जब आप सोचिए कि चुने हुए प्रतिनिधियों की ये हालत हो गई है तो दिल्ली की जनता कि क्या स्थिति है। मैं मानता हूं यहां पर जितने लोग बैठे हैं अगर सौ कॉल करते होंगे महीने के अंदर एसएचओ को, एसीपी को, डीसीपी को एक आध काम हो सकता है पर्सनल हो, 99 काम जो होते हैं वो पब्लिक के काम होते हैं और पब्लिक के काम में भी कोई सहयोग नहीं मिलता। जो केस बताया कंझावला के अंदर मैं तो उस घर में भी गया उस परिवार के साथ मिला। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी भी साथ में गए, आतिष्ठी जी भी थीं, ऋतुराज भाई वहीं बैठे थे। चार से 5 दिन परिवार के साथ लगातार थे। स्थिति ये है अध्यक्ष जी, कि आज के समय में इस व्यवस्था के साथ आप न्याय की उम्मीद नहीं कर

सकते। हो सकता है कि भई बहुत ज्यादा कोई टाइट हो गया तो आंकड़ा ये आएगा कि भई प्वाईंट 5 परसेंट इस बार रेप केसिज़ कम हुए हैं एक परसेंट ये वाला केस कम हो गया, 2 परसेंट ये वाला केस हो गया लेकिन इस व्यवस्था के अंदर कोई न्याय नहीं मिल सकता। जब भी हम कहते हैं कि भई दिल्ली पुलिस को दिल्ली की जनता के अधीन लाया जाए। दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स को दिल्ली के जनता के अधीन लाया जाए। जब भी हम ऐसा आरग्यूमेंट देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथी मीडिया के साथी, बहुत बड़े बड़े विद्वान भी ये कहते हैं ये हो नहीं सकता? क्यों नहीं हो सकता क्योंकि दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए इसके ऊपर तो केन्द्र का ही शासन होगा। सच्चाई तो ये है कि ये भी झूठ आरग्यूमेंट है। आप दुनिया के जो सबसे डव्ल्प नेशन है फोर एग्जाम्पल जर्मनी ले लीजिए, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जैसे दिल्ली सरकार हमारी एनसीटी बोलते हैं नेशनल कैपिटल टेरेट्री, उसी तरह से जर्मनी के अंदर जो बर्लिन के अंदर जो सरकार चलती है उसको भी बोलते हैं Senate of Burllin, Senate of Burllin के अंदर पुलिस भी आती है Senate of Burllin के अंदर सारे के सारे अधिकारी भी आते हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है आप लंदन ले लीजिए Greater Authority London उसको बोलते हैं उस लंदन की administration को जिसका मेयर हेड होता है। उसके अंदर भी सारी पुलिस आती है सारी जांच एजेंसी आती हैं और सबसे बड़ी बात कि लंदन की पुलिस के अंदर जो कि वहां के मेयर के अंदर आता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि रॉयल फैमिली की भी सुरक्षा वही प्रदान करेगा। तो जो यहां कह देते हैं ना कि भई ये कई सारे एमपी एमएलए रहते हैं, यहां पर कई सारे मंत्री रहते हैं

तो अगर दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर आ गई तो इनकी सुरक्षा कैसे करेंगे। लंदन के अंदर जो लंदन के मेयर के अंदर जो पुलिस आती है वो लंदन के राजशाही की भी सुरक्षा करती है, वहां के कैबिनेट मंत्रियों की सुरक्षा करती है। वहां के प्रधानमंत्री की भी सुरक्षा करती है और लोकतंत्र में मुझे नहीं लगता रशिया कोई एग्जेम्पल है। रशिया तो सबसे खराब एग्जेम्पल है लेकिन जो मास्को शहर की जो राजधानी की जो सरकार है मेरे ख्याल है ड्यूमा बोलते हैं वहां की सरकार को। संसद को ड्यूमा बोलते हैं जो शहर की जो सरकार है उस सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस भी आती है, इंटेलीजेंस भी आती है, गृह मंत्रालय उससे रिपोर्ट तो मांग सकता है लेकिन गृह मंत्रालय पुलिस को हटा नहीं सकता और उनकी जिम्मेदारी है कि मास्को को सुरक्षा देना। अध्यक्ष जी, आज राजनीति में नफरत बहुत ज्यादा हावी हो गई है। मैं देख रहा था कल विजेंद्र गुप्ता जी को मैंने देखा बड़े सीनियर साथी हैं आज हैं नहीं, मैं तो सबसे जूनियर साथी हूं। मैं देख रहा था कल चर्चा हो रही थी कि भई एमसीडी में Pro tem Speaker कैसे appoint हुए Alderman कैसे appoint हुए फलां ढिमका इसके उपर चर्चा हो रही थी वो खड़े हुए और वो उस चीज़ को डिफेंड कर रहे थे। जब वो डिफेंड कर रहे थे तो उनकी body language देखने लायक थी, वो आंख नहीं मिला पा रहे थे किसी से, उनकी जुबान में वो ताकत नहीं थी क्योंकि उनको भी पता है कि वो गलत चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। जब तक हमारी राजनीति, जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर चल रही है, नफ़रत के बेस पर होगी, मुझे नहीं लगता हम सिस्टम ठीक कर पाएंगे। आज दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया और अंत में लोकतंत्र का मूल ये है कि जनता जनार्दन होती है कहा जाता है तो चाहे वो हो सकता है किसी

एक्ट में ना लिखा हो लेकिन सैंटीमेंट यही है कि जनता सुप्रीम है तो जब तक जनता की नहीं चलेगी चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी हो। आप सोचिए? फाइनांस सैक्रेट्री की औकात पानी रोक रखा है उसने पूरी दिल्ली का। इतनी औकात उसकी, इतनी हिम्मत उसकी, एक दिन अगर उसके घर का पानी काट दिया जाए तो उसकी नानी याद आ जाएगी। उसकी औकात इतनी देखिए? चीफ सैक्रेट्री की औकात देखिए कि मतलब पूरे के पूरे हॉस्पिटल बंद कराने में लगा हुआ है। पेंशन 4-4, साढे चार- चार लोगों की राजनीति हो रही। इस तरह की घटियापन, इस तरह की क्ररत की राजनीति दिल्ली के अंदर चल रही है जो कि ठीक नहीं है। लंबे समय के लिए ठीक नहीं है हो सकता है कि दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी लोकतंत्र पर भरोसा ना रखती हो, हो सकता है दिल्ली की पुलिस लोकतंत्र के अंदर भरोसा ना रखती हो, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के अंदर नहीं भरोसा रखती है लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि ये हम में तो कई सारे लोग थे जो कभी सोच भी नहीं सकते थे एमएलए बनेंगे, हो सकता है स्थितियां बदलती रहती हैं। चेयर बदलते रहते हैं, लोकतंत्र की परिपाटी लोकतंत्र के अंदर जो सिस्टम है हर सरकार और हर पार्टी की कोशिश यही होनी चाहिए कि वो सिस्टम मजबूत हो क्योंकि अगर सिस्टम मजबूत होगा तभी लोकतंत्र के अंदर जनता की पूछ होगी, जनता की बात मजबूती से रखी जाएगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। श्री ऋतुराज।

श्री ऋतुराज गोविंदः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही सीरियस इश्यू पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये केस अंजलि का है जो कि किराड़ी

के कर्ण विहार पांच में रहती थी। एक ऐसी बच्ची जिसके पिताजी चार साल पहले उनका देहांत हो गया था। एक ऐसी बच्ची जो अकेले पूरे परिवार को चलाती थी उसके पिताजी का देहांत हो गया था उसके घर में माताजी हैं जो कि बीमार हैं क्रिटीकली इल हैं दो छोट-छोटे भाई हैं जिसका पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। एक छोटी बहन है उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। बीमार मां के इलाज का खर्च उठाती थी। पूरे परिवार को चलाती थी, किस तरीके से brutely उसका मर्डर किया गया। उसको सारे देश ने देखा अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद जब थोड़ी सी जांच हुई तो पता चला कि जो आरोपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उसके बाद पूरी कवायद उसको बचाने में लग गई। आपने देखा होगा कि छोटी-छोटी बातों पर एलजी साहब नाव में घूमते हैं काला हैट लगा कर के। क्या तो नाला का निरीक्षण कर रहे हैं। उसी नाला के बगल में अंजलि का घर है वहां पर एक बार झांकने भी नहीं गए कि इतनी बुरी तरीके से इतनी बड़ी घटना घटी है, क्या उस परिवार को किसी मदद की जरूरत है क्या कोई मदद करने वाला है, नहीं है इतना हाईलाइटिड मामला है, इतना क्रिटिकल मामला है, एक बार झांकने भी नहीं गए। जबकि ये तो अधिकार है उनका, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और ये सब तो संविधान ने दिया है उनको अधिकार दिया है। मदद किसने की? हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार को इलाज के लिए हो, फाइनेंशियल असिस्टेंट हो, लीगल मदद हो, हर तरीके का मदद करेंगे। अभी बहुत सारे साथी दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर बात कर रहे थे। एनसीआरबी भी कहता है कि Delhi is the most unsafe place for a woman एक बार नहीं पिछले 10-15 साल का रिकार्ड उठा के देखिए हर साल एक ही रिपोर्ट, हर साल एक ही रिपोर्ट, हर साल एक ही

रिपोर्ट और बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि हर रोज दो माइनर का रेप होता है दिल्ली के अंदर। इतनी खराब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है यहां पर। ये स्थिति पैदा कैसे हुई। इसको समझने की जरूरत है। आजादी के दीवानों ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी ताकि देश के अंदर में लोकतंत्र स्थापित हो। लोकतंत्र स्थापित भी हुआ। जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी कि भारत का संविधान कैसा हो federal structure कैसा हो, संघीय ढांचा कैसा हो? तो संविधान सभा के अंदर में बहुत बड़ी संख्या में लोग थे जो कि इस बात को लेकर चिंतित थे कि देश में अंदर राज्यों के अंदर में गर्वनर की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए क्योंकि federal structure के अंदर में सबसे बड़ा रोड़ा कोई बनेगा तो ये गर्वनर का सिस्टम बनेगा। यानि कि there should be no intervention of center इसके लिए गवर्नर की व्यवस्था ही ना हो और इसके लिए संविधान सभा की आप प्रोसिडिंग्स को पढेंगें तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग उस चीज के खिलाफ थे, तो उस वक्त के सत्ताधीन लोगों ने क्या कहा? कि नहीं इसको यूनियन आफ स्टेट बनाना है साढे सात सौ से ज्यादा रियासतें हैं, उन रियासतों को इक्टठा करना है। इक्टठा तब रह पाएंगे राज्यों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं इसलिए proper communication बना रहे coordination बना रहे। संघीय ढांचा मजबूत रहे इसके लिए there should be a representation from the central government into the state government और उसको बोला गया गवर्नर वॉयसराय। ये इसका इतिहास है। अब मान लीजिए 1947 में आपको संघीय ढांचा को मेन्टेन रखने के लिए यूनियन आफ स्टेट को मेन्टेन रखने के लिए आपको एक गवर्नर की व्यवस्था को बनाने की जरूरत पड़ी, पर आजादी

के 75 साल के बाद आज कौन सी रियासत को आपको इक्ट्ठा करना है और गवर्नर्स का इतिहास क्या है? इतिहास उठाकर देखिए बूटा सिंह ने बिहार में क्या किया? इतिहास उठाकर देखिए उत्तर प्रदेश में गवर्नर्स ने क्या किया। आज तक जितने भी गवनर्स हुए हैं भारत के इतिहास में 75 सालों में इनका इतिहास उठाकर देखो एक गवर्नर नहीं मिलेगा जिसने कोई तमवितउ किया हो, कोई अच्छा काम किया हो, केवल और केवल या तो सरकार को बर्खास्त किया या सरकार के काम में रोड़ा अटकाया या सैन्टर के इशारे पे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ un-constitutional काम ही करने का काम किया है और Lt. Governor तो उससे भी एक कदम आगे है क्योंकि पावर दे दिया उसको कुछ और extra power दे दिया। गवर्नर जिसको कम पावर है वो तो इतना अडंगा अड़ा रहा था Lt. Governor क्या करेगा? देश की मूलभावना जनतंत्र है और जनतंत्र के अंदर में दिल्ली के अंदर में Lt. Governor को क्या पावर है नहीं है constitution bench ने ऑलरेडी उसको कर चुका है और करेगा लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं दिल्ली के अंदर में भी दिल्ली पुलिस की कुछ ना कुछ accountability थी वो कैसे थी मैं आपको बताता हूं। पहले थाना लेवल कमेटी होता था। थाना लेवल कमेटी के अंदर में विधायक चेयरमैन होते थे तो उसके अंदर में जितने भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस होती थीं जो भी प्रॉब्लम्स होती थीं। नशे की प्रॉब्लम है और भी प्रॉब्लम है उसको लोग डिस्कस किया करते थे और अभी ये जो दुर्गेश भाई कहते थे कि एसएचओ फोन नहीं उठाता है तो उसके ऊपर एक इतना दबाव होता था उसका convener होता था एसडीएम। एसएचओ विधायक चेयरमैन होता था तो कम से कम उसकी इतनी सुनते थे कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करते थे। कम

से कम इतना प्रेशर होता था। आज पुलिस की कोई accountability नहीं है कोई accountability नहीं है और ऐसी हालत हो गई है Lt. Governor की कि पीएमओ से फोन आता है अरे ओ सक्सेना क्या काम किए? बोलता है सरदार मोहल्ला क्लीनिक रोक दिए। सरदार फिनलैंड का फाइल रोक दिए। कच्ची कॉलोनियों के विकास के लिए पैसा भी रोक दिए। सरदार दिल्ली जलबोर्ड का पेमेंट रोक दिए। सरदार, बोले शाबाश-दिल्ली सरकार का डंका पूरा दुनिया में नहीं बजना चाहिए तो बोलता है सरदार मैंने आपका नमक खाया है। तो सरदार कहता है याद रखना तुमको सीधा शाखा से उठाकर के राजभवन में बैठाए हैं अपनी औकात को याद रखना और इसी तरीके से पालन करते रहना। ये Lt. Governor की औकात है। ये पावर है ऐसे गरिया रहे हैं आप तो Lt. Governor को औकात क्या है इनकी? सवाल सिस्टम का है क्यों चाहिए Lt. Governor क्यों चाहिए गवर्नर। अरे आप उठाकर देखिए constitutional assembly में क्या डिस्कशन हुआ आधे लोग क्यों नाराज थे, क्यों परेशान थे, क्यों नहीं चाहते थे कि गवर्नर की व्यवस्था हो। ये सवाल पूरे देश का है। आज ये अंजलि जैसे बच्ची का साथ में brutal murder होता है बारह-बारह किलोमीटर तक घसीटा जाता है उसका 6-6 थाना पड़ता है 13-13 पीसीआर का बीट पड़ता है और उस बच्ची के लिए न्याय के लिए देश खड़ा है यहां पर क्यों? क्योंकि पुलिस की accountability नहीं है यहां पर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है। दिल्ली देश में रेप कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अरे आप को कॉम्पटीशन करना है तो काम के नाम पर करो। आप को पावर दिया है ना पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की पावर दी है ना, लैंड की व्यवस्था की है ना। रिफार्म करके दिखाओ? और दिखाओ कि ये मोदी माडल

आफ गवर्नेंस है और ये केजरीवाल माडल आफ गवर्नेंस है। lets there be a competitive governance का जो है तरीका अपनाएं जिससे की लोगों को तय करने दीजिए। काम रोकने से कुछ होता है। तो अध्यक्ष जी, ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, दिल्ली के अंदर में लॉ एंड ओर्डर की जो स्थिति है ये दिन पर दिन बदत्तर से बदत्तर होती जा रही है। अंजलि जैसी बच्ची के साथ में फिर कोई, किसी बहन के साथ, किसी बेटी के साथ घटना ना घटे, इसके लिये दिल्ली पुलिस की अकाउंटिबिल्टी होनी चाहिये, इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, इसकी मैं पूरी तरीके से जो है सो निंदा करता हूं और मैं इस चर्चा में यही कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय की आपके माधयम से, इस सदन के माधयम से एक मैसेज जाना चाहिये की अगर आपको नई दिल्ली की बहुत चिंता है तो जैसे एनडीएमसी होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था, ऐसे ही नई दिल्ली पुलिस बना लीजिए, कर लीजिए सांसदों की रक्षा, कर लीजिए प्रधानमंत्री की रक्षा। दिल्ली की दो करोड़ जनता आपके लिये क्यों भुगते, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नई दिल्ली में नहीं है। लॉ एंड ओर्डर की स्थिति दिल्ली में है। नई दिल्ली पुलिस अलग कर लीजिए, दिल्ली पुलिस अलग कर लीजिए। दिल्ली पुलिस दिल्ली की सरकार के अंडर में होता की दिल्ली के दो करोड़ जो जनता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार उठाए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। राजकुमारी ढिल्लों जी।

श्रीमती राजकुमारी ढिल्लोः अध्यक्ष महोदय जी, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा भी नहीं होती। वो कैसे बनाएंगे भारत को विश्वशक्ति, जब सुरक्षित ही नहीं देश की नारी शक्ति।

अध्यक्ष जी, जिस देश में नारी को पूजा जाता था, जिस देश में नारी की गाथाएं गाई जाती थी आज उसी देश की राजधानी दिल्ली के कंझावला में नववर्ष की रात को, तकरीबन 13 घंटे तक एक 20 साल की बेटी अंजलि जिसको की कुछ अपराधी और कार में बैठे एक बीजेपी के नेता जिससे की अपराधियों का मनोबल ऊंचा होता गया और वो बेटी को 12 घंटे तक कंझावला की सड़कों पर घसीटते रहे। हाँ, 12–13 तकरीबन, उसको घसीटते रहे, लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसा दिन जो की वर्ष में एक बार आता है और सभी को पता है इस दिन के बारे में की ये रात कैसी रात बच्चों के लिये होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी जब कि there should be more vigilance than negligence specially on occasions like new years जहां सभी को पता था कि इस रात को पुलिस को अलर्ट रहना चाहिये, लेकिन मैं दिल्ली के उप–राज्यपाल वी.के. सक्सेना जी से आपके माधयम से मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आपकी दिल्ली पुलिस सोई हुई थी, क्या आपकी कानून व्यवस्था आपकी सोई हुई थी। तो मैं अध्यक्ष महोदय, आज पूरा विश्व कंझावला में नए साल की रात हुई शर्मनाक घटना पर बात कर रहा है। मैंने 3 जनवरी को बीबीसी न्यूज चैनल पर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। जिसमें मैंने पढ़ा हैडलाइनस थी उसकी अध्यक्ष जी, young woman’s horrific death shocks India बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। क्या एलजी साहब आपको यह दिखाई नहीं देता कि आज देश की राजधानी विश्वभर में बदनाम हो रही है। आज दिल्ली को देश में ही नहीं विश्वभर में अपराध की दृष्टि से क्राइम नम्बर वन सिटी बना दिया गया है। अध्यक्ष जी, क्या नये साल की रात पुलिस 13 घंटे जब बेटी को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, उनका उस दिन यही काम था कि आज आप भी शराब पीकर सोयें।

एलजी साहब देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था से पूरा दिल्ली, हर नारी, हर महिला बहुत ही डरी हुई है, बहुत ही भयभीत है। क्या एलजी साहब आपके पास इस प्रश्न का उत्तर है कि यदि हमारे परिवार की महिलाएं, बेटियाँ यदि कोई पारिवारिक या सामाजिक फंक्शनस में जाती हैं क्या वे वहां से महिलाएं, बेटियाँ सकुशल वापिस लोटेंगी मैं इस प्रश्न का उत्तर मैं एलजी साहब से मांगना चाहती हूं। बीजेपी दिल्ली पुलिस को, अपोजिशन को हैराश करने के लिये इस्तेमाल करती है। क्या बस यही है दिल्ली का लॉ एंड ओर्डर, एलजी साहब से मेरा निवेदन है कि वो संविधान द्वारा दी गई अपनी जिम्मेवारियां निभायें और पुलिस को दुरूस्त करें, ना की आप अपना कीमती समय दिल्ली की जनता द्वारा तीन बार चुने गए दिल्ली के मुख्यमंत्री जो की आज देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री में उनकी गिनती है, पढ़े-लिखे हैं, काम करना जानते हैं, हम दिल्ली की जनता आपसे एक निवेदन करती है कि आप अपना काम करें और दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप अपना उनको काम करने दें। उनके काम में आप परेशानियां, अड़ंगे आप ना लगाएं, क्योंकि हम भी बैठे-बैठे 4 दिन से हम देख रहे थे कि किस प्रकार हमारे हाउस का वातावरण सिर्फ तो सिर्फ एलजी साहब की वजह से ये बनता गया है। मैं आपको एक बताना चाह रही थी कि अध्यक्ष जी, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिये दिल्ली में तकरीबन सवा 4 लाख सीसीटीवी कैमरे दूसरे चरण में भी लगाने की प्रक्रिया को अंजाम दे दिया है। हर विधान सभा में सैकंड चरण में जो हमारे कैमरेज लगाए जा रहे हैं वो महिलाओं की सुरक्षा के लिये लगाए जा रहे हैं। बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिये, जीपीएस वहां पर मार्शल्स तैनात किए गए हैं और सड़कों पर, गलियों में लाइटें लगाई गई हैं लेकिन मैं आज एलजी साहब से ये पूछना

चाहूंगी की आप कहते हैं कि हमारे पास डीडीए का विभाग है, लेकिन डीडीए के जो बड़े-बड़े पार्क हैं, जहां पर की महिलाएं दिन छिपे या सुबह early in the morning सैर करने के लिये जाती हैं, अपनी शारीरिक और मानसिक संतुलन को अच्छा मजबूत बनाने के लिये क्या एलजी साहब आपने दिल्ली के जो सांसद हैं क्या आपने उनसे पूछा है कि डीडीए के पार्कों में वहां पर रोशनी है या नहीं। डीडीए के पार्कों में सीसीटीवी कैमरेज लगाए हैं कि नहीं। तो मेरा एक ये भी आपके माधयम से एलजी साहब से मेरा प्रश्न है।

महोदय, जो निर्भया फंड हमारा बुनियादी ढ़ांचे की जरूरत के लिये इस्तेमाल होना चाहिये था जो वर्तमान में नहीं हो रहा। महिलाओं की सुरक्षा के लिये 24/7 हैल्पलाइन एप्स, जीपीएस, स्पीडी जस्टिस, स्पेशल इंवैस्टिगेशन्स यूनिटस आदि-आदि होने चाहिये। इसके साथ-साथ अध्यक्ष जी posh and pasco infrastructure to ensure the safety of woman in public spaces और हमारे जितने भी पीडब्ल्यूडी के रोड्स हैं वहां पर स्थानीय शिकायत केंद्र होने चाहिये, प्रतिक्षालय होने चाहिये, सीसीटीवीज़, बस स्टैंड्स, पब्लिक टॉयलेट्स खासतौर से महिलाओं के लिये स्ट्रीट्स लाइट्स सार्वजनिक परिवहन में जीपीएस। एलजी साहब मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहूंगी की आप मुझे माफ करना, एलजी साहब नारी शक्ति आज समझ चुकी है इस देश के अंदर भाजपा का महिलाओं और नारियों के प्रति असली चेहरा क्या है। जिस पार्टी का नेता अपने परिवार में न्याय नहीं कर सका, उसके चाहने वाले दिल्ली की महिलाओं और नारियों के लिए क्या न्याय करेंगे।

अध्यक्ष महोदय जी, अरविंद केजरीवाल जी के विकास मॉडल का डंका।

माननीय अध्यक्षः कंक्ल्यूड करिये।

श्रीमती राजकुमारी ढिल्लोः देश में ही नहीं विदेशों में बज रहा है।

माननीय अध्यक्षः राजकुमारी जी कंक्ल्यूड करिये प्लीज़।

श्रीमती राजकुमारी ढिल्लोः और दूसरी तरफ एलजी साहब का कानून व्यवस्था का जो चरमराई हुई कानून व्यवस्था है इसका दिल्ली में नहीं विदेशों में भी इनका डंका बज रहा है तो मैं ये कहते हुए परहेज नहीं करूंगी और इसके कहने में भी मेरी कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी की एलजी साहब आप दिल्ली की जनता के द्वारा चुने गए 3 बार के सर्वश्रेष्ठ देश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से आप सलाह लें, उनका तजुर्बा है, बार-बार वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं कि किस प्रकार आपको दिल्ली की कानून व्यवस्था को आपको सुदृढ़ करना है, आपको मजबूत करना है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, दिल्ली की जनता का फायदा होगा। आपका अध्यक्ष जी बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद आपने मुझे एक गम्भीर मुद्दे पर बोलने का समय दिया, धन्यवाद, जयहिंद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद प्रमिला जी, प्रमिला टोकस।

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकसः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस दर्दनाक घटना पर बोलने का मौका दिया। अभी दिल्ली में जिस प्रकार से ये कंझावला में घटना घटी, ये बड़ी दुखद है और बड़ी चिंताजनक भी है। क्योंकि आए दिन हमारी बहन-बेटियों के साथ कहीं ना कहीं ऐसा कंझावले जैसा, कहीं ना कहीं हमारी दिल्ली में हमारे देश में कहीं ना कहीं होता रहता है। तो मुझे बड़ा दुख भी है और गुस्सा इतना है कि अगर मैं दो मिनट चुप हो जाऊं

तो आप समझ लेना की गुस्सा क्या है और मैं क्या कहना चाह रही हूं की इस सदन से मैं वो बोल नहीं सकती की उन दरिंदों के प्रति मेरे अंदर क्या है, क्या मैं उनको बोलूं। ये गुस्सा बस हद से पार है क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली को एक ऐसी शहर बना दिया जिसमें ना कोई रहना चाहता है, ना कोई नौकरी करना चाहता है क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी है। आपने देखा भी होगा, परसों भी वो किस प्रकार से काले कपड़े पहनकर आए जो भगवा का वो नारा देते हैं क्योंकि आप थोड़ी सी देर बैठिये अगर किसी को समझना है तो उसकी बातों से समझिये, उसके अंदर क्या है। जो उसके अंदर होगा वही बाहर आयेगा। तो वो उन्होंने, भाजपा ने पूरा परसों दिखा ही दिया था कि उनके अंदर भगवा नहीं है बिल्कुल काला है और जिस प्रकार से दिल्ली में, दिल्ली पुलिस है जो उसका रवैया है वो तो पता नहीं क्या करना चाहते हैं हमारे एलजी साहब इस दिल्ली को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, क्यों हमारे एलजी साहब या हमारे जो भाजपा के नेता हैं उनकी मानसिकता क्यों ऐसी है कि वो महिलाओं को देखना नहीं चाहते, शायद मुझे ये लगता है, क्योंकि हमारी जब एक बार वूमैन कॉफ्रैंस हुई थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे, कि हमारी महिलाओं को पता है कि यहां किचन है, होना चाहिये, मतलब किचन से बाहर ही निकालेंगे, घर में ही बांध के रखेंगे कि उनको अच्छे से पता है यहां किचन होना चाहिये, यहां पर वॉशरूम होना चाहिये, वाह क्या बात है। तो उनकी मानसिकता ऐसी है और आप देखेंगे अध्यक्ष जी, जब भी हम किसी भगवान का नाम लेते हैं, अगर हम कृष्ण का पहले नाम लेते राधा-कृष्ण बोलते हैं। और हमारा पूरा देश, सभी सीताराम बोलते हैं, जयश्रीराम कोई नहीं बोलता है, अगर बोलेंगे तो नारा लगाएंगे

बोलो जय सियापति रामचंद्र की जय और जो भाजपा वाले हैं वो उसमें भी माँ को भी साथ में नहीं ले रहे हैं तो और किसको लेंगे। सीतामाता को भी वो राम के साथ में नहीं ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की महिलाओं को या दिल्ली की बेटियों को कैसे साथ में ले सकते हैं, उनकी ये मानसिकता है और पूरे भाजपा और सबसे ज्यादा अध्यक्ष जी मैं थोड़ा सा डाटा भी लेकर आई हूं क्योंकि अभी 22 का तो डाटा आया नहीं है पिछले लगभग 8 सालों से दिल्ली वालों पर एलजी की हुकूमत चल रही थी, जिनके अंदर पुलिस प्रशासन आती है। तो मैं आज सदन के सामने 7 साल का ब्यौरा रखती हूं कि किस प्रकार से जब से हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, जब से एलजी साहब भारत सरकार ने बैठाये हैं जब से हमारी दिल्ली में कितने रेप केस बढ़े हैं। अध्यक्ष जी, 2008 से 2014 का मैं थोड़ा सा ब्यौरा देती हूं। महिलाओं के साथ हुए कुल अपराध 52,268, एसिड अटैक हुए 2016 से डाटा नहीं है। किडनैपिंग के 16,612 केस, बलात्कार के 6,458 केस, पॉक्सो के मामले 39,006, बलात्कार एंव हत्या के 2017 से कोई डाटा नहीं है। छेड़छाड़ के 11,043, साइबर क्राइम का कोई डाटा नहीं है। 2015 से 21 का। महिलाओं के साथ हुए कुल अपराध 8 हजार 11 सौ 49, एसिड अटैक 54, किडनैपिंग 22,719, बलात्कार 8,066, पॉक्सो के मामले 8,238, बलात्कार व हत्या के मामले 17, छेड़छाड़ के मामले 16,080, साइबर क्राइम के 171 और अध्यक्ष जी, 2021 में जो सबसे ज्यादा 41 प्रतिशत बढ़े हैं मामले दिल्ली में। 2021 के, क्योंकि 22 का अभी डाटा नहीं है। एसिड अटैक के 8 मामले, किडनैपिंग के 4,171, बलात्कार के 1,251, पोक्सो के मामले 1,377, बलात्कार एंव हत्या के 2, छेड़छाड़ के 2,080, साइबर क्राइम के 105 कुल 14,508 हैं। जो 21 में सबसे

ज्यादा 41 प्रतिशत हुए हैं। अध्यक्ष जी, और इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा भाजपा का ही नेता इनमें शामिल हैं और जिस प्रकार से अभी मैं कहूं की हमारे देश का गौरव, हमारे देश की शान, अभी ये तो हाल ही में सभी के सामने आया है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किस प्रकार से जो हरियाणा के खेल मंत्री हैं। अध्यक्ष जी 2 मिनट आप बोलने नहीं देते हैं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः अब कंक्ल्यूड करिये प्लीज।

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकसः जिस प्रकार से हमारी हरियाणा की बेटी के साथ, जो हरियाणा का खेल मंत्री है, उन्होंने किस प्रकार से सैक्शुअल हरास्मैंट का उन्होंने उसपर केस लगाया है। तो ये भापजा मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही महिला।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः प्रमिला जी कंक्ल्यूड करिये। भई अजय जी वो बोल रही हैं ना उनको लिखकर दे दो।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्षः भई जो वक्ता मेरे पास नाम हैं उनको लिखकर दे दीजिए। प्रमिला जी कन्टीन्यू करिये प्लीज।

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकसः अध्यक्ष जी, 2019 में भाजपा ने अपना घोषणा-पत्र निकाला था कि ऐसा कानून लाएंगे जिसमें, शायद मुझे लगता है ऐसा ही उनका जो चुनावी घोषणा-पत्र था शायद वो ऐसा ही होगा मुझे ऐसा

लगता है। क्योंकि जितने भी अपराधी हुए हैं और दिल्ली पुलिस ये देखो अध्यक्ष जी किस प्रकार से उस बच्ची के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है कि 12 घंटे तक उसको सड़कों पर घसीटते रहे। लेकिन हमारी पुलिस उस अपराधी को बचाने में लगी रही। किस प्रकार से अपराधी को बचाया जाए। दिल्ली पुलिस किस प्रकार से उस अपराधी को बचाया जाए उसमें लगी रही।

माननीय अध्यक्षः चलिये, चलिये।

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकसः अध्यक्ष जी, मेरा आपसे ये, आपके माधयम से ये एक निवेदन है कि ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा दी जाये ताकि कोई और ऐसा न करें। जबऐसा कुछ होता तभी हम आवाज़ उठाते हैं और तभी हम बोलते हैं। अध्यक्ष जी एक मिनट।

माननीय अध्यक्षः अब धन्यवाद प्लीज़, बहुत बहुत धन्यवाद, अभी समय देखो।

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकसः अध्यक्ष जी, देखिये अभी हमारे आम आदमी पार्टी।

माननीय अध्यक्षः अभी चार वक्ता बाकी हैं, प्रमिला जी प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। राखी बिरला जी।

...व्यवधान...

श्रीमती राखी बिरलाः बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी अजय दत्त जी बैठिये सारी बात होगी प्लीज़। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इतने गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय पर।

माननीय अध्यक्षः संक्षेप रखिये, संक्षेप में बहुत।

श्रीमती राखी बिरलाः हाँ बहुत संक्षेप में रखूंगी और ये विषय ऐसा नहीं है कि संक्षेप में रखा जाए या फिर ये विषय ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ब्रीफली रखा जाए। ये विषय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, मानवीयता के साथ जुड़ा हुआ है। इस देश की आधी आबादी के भविष्य, इस देश की आधी आबादी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इसको शोर्ट करना या फिर इसको लैंदी करने का विषय नहीं है, विषय ये है कि इस देश की आधी आबादी को सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले लोग जब चर्चा करते हैं तो उनकी गम्भीरता भी दिखनी चाहिये। जब इन विषयों पर चर्चा होती है, तो चर्चा महज सदन तक चर्चा होकर ना रह जाए। उसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकलकर, उस चर्चा को सार्थक किया जाए।

आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। बेटी होने के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते, इस सदन की सदस्य होने के नाते मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं। सुरक्षित हों सड़कें, सुरक्षित हों पर्वत और चोटियां, ताकि निडर होकर जी सकें दिल्ली की बेटियाँ। ये सिर्फ शब्द नहीं है अध्यक्ष जी, ये एक पीड़ा है। जब सुरक्षित सडकों की बात कही जाती है तो याद आती है 16 दिसम्बर, 2013 की वो रात जब एक बेटी निर्भया अपनी जान और सुरक्षा के लिये गुहार लगा रही थी, लड़ रही थी बदमाशों के साथ, उन दरिंदों के साथ जिन्होंने उसके साथ ना सिर्फ हैवानियत की और उसको मौत के घाट उतार दिया।

वो 2013 दिसम्बर की रात थी। उसके ठीक 10 साल बाद एक जनवरी 2023 की रात आती है, उस रात भी दिल्ली की एक बेटी अंजलि सड़क के

ऊपर दरिंदो से अपनी जान की गुहार लगाती है, अपनी सुरक्षा की पुलिस और सरकार से उम्मीद करती है, लेकिन 10 सालों के अंदर ना तो निर्भया को सुरक्षा मिली 2013 के अंदर और जो उसके बनाए हुए फंड का सदुपयोग हो सका और आज ठीक एक दशक के बाद अंजलि हमारी दिल्ली की बेटी उस रात को जिस रात को जश्न की रात कहा जाता है, पूरा देश पूरी दुनिया जश्न के माहौल में डूबी होती है ठीक एक दिन पहले 31 दिसम्बर को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एक प्रैस कांफ्रेस करके ये कहते हैं 21 दिसम्बर जो है 31 दिसम्बर की रात को दिल्ली की सुरक्षा इतनी चाक-चौबंद होगी कि 16 हजार से भी ज्यादा पुलिसकर्मी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में रात को उतारे जायेंगे। लेकिन वही घटना जब 31 तारीख और एक तारीख की रात को घटित होती है तो दिल्ली पुलिस और सुरक्षा के सारे के सारे जो ढकोसले हैं उनके परखचे उड़ा देती है। अध्यक्ष ही साल 2013 की घटना हो या एक जनवरी साल 2023 की घटना हो, इन 10 सालों के अंदर दिल्ली मे कुछ भी नही बदला। तब भी दिल्ली की सड़कों पर बेटियां आधी रात को निकलती हुए डरती थी घबराती थी, आज भी आधी रात को दिल्ली की सड़कों पर उतरते हुए बेटियां डरती हैं और घबराती हैं लेकिन इस एक दशक के अंदर अध्यक्ष महोदय दिल्ली के अंदर दो महत्वपूर्ण चीज़ों में बदलाव आया। एक आया राज्य की सरकार में और एक आया केन्द्र की सरकार में। साल 2013 में जब राज्य के अंदर एक ऐसी सरकार चुनकर आई जिनका कोई राजनैतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, जिनकी कोई सत्ता में आने की ललक नहीं थी, सिर्फ देश को बदलने की एक चिंगारी थी। माननीय अरविन्द केजरीवाल जी सरकार सत्ता में आई। वो सरकार जिसने महज 7 सालों के अंदर दिल्ली में डीडीसी बसों के अंदर मार्शल लगाने का काम

हो। चौक-चौराहे, गली-मोहल्लों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात हो, बसों में पैनिक बटन लगाने की बात हो। हर एक गली-मोहल्ले पर लाइटों के प्रबन्ध करने की बात हो या फिर दिल्ली महिला सुरक्षा के लिए 20 से ज्यादा इन्फोर्समेंट की वैन डिप्यूट करने की बात हो। महिला मोहल्ला क्लीनिक का शुभारम्भ करने की बात हो। एक ऐसी सरकार जो महज 7 साल के अंदर महिलाओं को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, मजबूत किया जाए। उनको मानसिक और शारीरिक तौर पर सक्षम करके देश की आधी आबादी को सम्मान दिया जाए दिन-रात काम करती है। उसके उल्ट साल 2014 के अंदर एक ऐसी सरकार चुनकर आती है जिसका नारा होता है बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अबकी बार मोदी सरकार। देश की आधी आबादी को लगता है कि कांग्रेस के समय में निर्भया का कांड हुआ। किसी प्रकार का ऐसा कोई फैसला नहीं आया जो आध ी आबादी को विश्वास दिला सके कि इसी सरकार को अगली बार आप केन्द्र में दोहराये। तो उन्होंने उस कांग्रेस की सरकार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केन्द्र में स्थापित किया। महज 5-7 महीने का फर्क रहा इन दोनों सरकारों में जब 2013 के अंदर दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल जी की सरकार आती है वो दिन-रात चौबीस घंटे स्कूल हो, सड़कें हो, अस्पताल हों, बस हो किस प्रकार से आधी आबादी को इस बात को महसूस कराए कि जिस मुख्यमंत्री को बड़े भाई के रूप में आपने चुनकर भेजा है वो बड़ा भाई हर जगह अपने डिपार्टमेंट के माधयम से तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। वहीं 2014 में जो सरकार इस नारे के साथ आई, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अबकी बार मोदी सरकार। हर उनके हर वादे जो जुमले साबित हुए उनकी महिला सुरक्षा की ये महत्वपूर्ण बात भी महज जुमला साबित होकर

रह गई और अध्यक्ष जी ये मैं इस लिए कह रही हूं कि ऑन रिकार्ड है भारतीय जनता पार्टी का टॉप मोस्ट नेता नरेन्द्र दामोदर दास मोदी हो, चाहे बहुत ही निम्न स्तर का छोटे दर्जे का गली, नुक्कड, चौक–चौराहे छोटा छुट भैया नेता मनोज मित्तल हो। चाहे वो देश का प्रधानमंत्री है और दूसरा एक छोटे वार्ड का सह–संयोजक है। इत्तेफाक देखिये, ये सबके सब महिला उत्पीड़न में संलिप्त पाये जाते हैं। नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो महिला जासूसी का प्रकरण किसी से छिपा नहीं है। अब ये कल की नई घटना कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर महिला शोषण का आरोप लगाया गया। इसमें भी कौन संलिप्त है। इसमें भी बृजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष जो है Wrestling Federation of India है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इसी प्रकार से सैयद शहनवाज हुसैन जी जो पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, परसों परले दिन ही हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनके ऊपर रेप का केस एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसी तरह से एमजे अकबर पूर्व राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। दिल्ली के बड़े नेता विजय जोली जी जो पूर्व विधायक रहे हैं उनके ऊपर महिला उत्पीड़न का केस दर्ज है। कुलदीप कुमार सेंगर किसी से भी छिपी नहीं हैं किस प्रकार से उस बेटी के पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा और पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उनके हित के लिए खड़ी थी उनके संरक्षण के लिए खड़ी थी। चिन्मयआनन्द जो स्वामी है किस प्रकार से एक छात्रा को उत्पीड़न कर रहा था किसी से नहीं छुपा। उत्तर प्रदेश का पूर्व राज्य गृह राज्यमंत्री रहा है। उमेष्ठा अग्रवाल विधायक है हरियाणा का महिला उत्पीड़न में नाम आता है। श्री राघव पूर्व बीजेपी नेता है। साक्षी महाराज जी सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, श्री परमिन्दर कटारिया जी पूर्व उप–महापौर

हैं, श्री शान्ति लाल सोलंकी व गोविन्दा जो है, रूपाणी जी बीजेपी के गुजरात के नेता हैं। एनडी विजयराज जी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, श्री अशोक नेता है बीजेपी के, हामिद सदर नेता है बीजेपी के। ये एक लम्बी–चौड़ी लिस्ट है और ये लिस्ट आम आदमी पार्टी या फिर मैं अपने मनगढंत तरीके से नहीं बनाई है। ये सारे के सारे केस कोर्ट कें रजिस्टर्ड है, पुलिस थानों में रजिस्टर्ड हैं और हर तरीके से कहीं ना कहीं इनके खिलाफ रिकार्ड मिलेगा। अध्यक्ष जी जैसा मैने बोला एक सरकार जो 2013 में आई वो इस जिम्मेदारी के साथ उनके नेता आए कि इस दिल्ली की जनता ने माँ ने, बहन ने, बेटियों ने हमको अपने बड़े और छोटे भाईयों के रूप में अपनी सुरक्षा सौंपी है, तो दिन रात वो काम करते हैं वो महिला की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उनके अंदर इस बात को विश्वास को भरने के लिए कि जो ये नेता है जो ये मंत्री हैं जो ये विधायक है, इनकी जिम्मेदारी आप एक बेटी के रूप में बहन के रूप में हो। उसके उल्ट साल 2013 के बाद जो 14 में केन्द्र की सरकार आई निर्भया के कांड के बाद उनका टॉप मोस्ट लीडर से लेकर लास्ट तक के लोग जो है सब लोग पाये जाते हैं इनके सारे के सारे महिला उत्पीड़न के केसेज में।

माननीय अध्यक्षः राखी जी कंक्ल्यूड अब। प्लीज कंक्ल्यूड करिए अब।

श्रीमती राखी बिरलाः हम और सब ओर बात न करके सिर्फ दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में आज जैसा मेरे सभी साथियों ने बताया कि दिल्ली आज एक रेप का कैपिटल बन गई है। दिल्ली की सड़कों पर हमारी माँ–बहन–बेटियाँ अपने आप को अकेला असुरक्षित महसूस करती हैं। मैं आज आपके माधयम से उप–राज्यपाल महोदय से ये कहना चाहती हूं कि आपको रोकने का बड़ा शौक है। कभी आप दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य सेवाएं रोक

देते हैं, कभी आप दिल्ली के लोगों का पानी रोक देते है, कभी दिल्ली के गरीब, दलित के बच्चों को बेहतर शिक्षा देनी की ट्रेनिंग ले जाने के लिए जो अध्यापकगण फिनलैंड जा रहे हैं आप उनकी फाईलों को रोक देते हैं। अगर एलजी महोदय, उप-राज्यपाल महोदय को कुछ रोकना है तो वो दिल्ली के क्राइम को रोकिये और जो दिल्ली पुलिस है उसकी घूसखोरी की आदत को रोकिये। उसकी accountability और उसकी responsibility को फिक्स करिये। उप-राज्यपाल को की क्या ये जरूरत नहीं थी कि इतना बड़ा जो अंजलि का केस हुआ, 14 घंटे तक उस परिजन को उस बेटी की शिनाख्त नहीं कराई गई। पोस्टमार्टम के लिए जो है कमेटी नहीं गठित की गई या फिर एफआईआर के अंदर 302 की धारा नहीं जोड़ी गई। क्या उनको संज्ञान लेना जरूरी नहीं था। क्या दिल्ली पुलिस की responsibility या उन लोगों की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। जिनकी जो है लापरवाही से जिनके लचर रवैये की वजह से एक बेटी जो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करती थी, अपनी विधवा माँ का इलाज करा रही थी, अपने छोटे भाई बहनों की पढाई सुनिश्चित करा रही थी वो अपनी जान खो देती है, जान गवां देती है और अध्यक्ष जी आपको मुझे नहीं पता इस सदन को जानकारी है या नहीं है ये एक जनवरी की घटना थी 31 दिसम्बर और 1 जनवरी की रात की घटना थी जिसने ना सिर्फ दिल्ली ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया को दहला दिया। उसके बाद खबर आती है कि जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो कल रात को ये फैडरेशन वाले लोगों की जहां कुश्ती संघ अध्यक्ष के लोगों का धरना चल रहा था उनसे जब वो मिलकर निकल रही थी तो उनकी गाड़ी को भी टक्कर मारी जाती है रोड़ के ऊपर और एक शराब के नशे में व्यक्ति उनको जो है दो-तीन

बार उनकी गाड़ी को टक्कर मारता है और जब वो उतरती हैं उनका हाथ गाडी में फंसा रहता है उनके साथ बदतमिजी होती है। तो आप ये सोच लीजिए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली की बहन-बेटियों की सुरक्षा पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। जहां पर सामान्य वर्ग की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो वही महिला आयोग की दिल्ली की अध्यक्ष के साथ सरे बाजार रोड पर बदतमीजी की जाती है। तो मैं उप-राज्यपाल महोदय से सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि सिर्फ विरोध के लिए किसी का विरोध करना ठीक नहीं है। आप भी किसी बेटी के बाप होंगे, आप भी किसी के भाई होंगे और आपके परिवार में भी माँ-बहनें होगी महिलाएं होंगी जो एक जिम्मेदार पद पर आपको देखते हुए अपने जैसी लाखों हजार बेटी और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की उम्मीद आपकी ओर देख रही है। तो कम से कम राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली की आधी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित हो और जो इसके जिम्मेदार लोग हैं जो अधिकारी इसके अन्तर्गत आते हैं उनकी identification करके उनकी रिस्पोंसिब्लेटी को फिक्स किया जाए। तब तो मुझे लगेगा कि आप दिल्ली का भला करना चाहते हैं नहीं तो जो अभी तक के आपके क्रियाकलाप हैं, जो अभी तक के उप-राज्यपाल महोदय के कदम हैं वो सिर्फ ये ही दिखा रहे हैं, ये ही प्रतीत कर रहे है कि जो व्यक्ति दिल्ली के एक जिम्मेदार बेटे के रूप में, दिल्ली के एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री बड़े भाई के रूप में माननीय अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार काम कर रही है...

माननीय अध्यक्षः राखी जी अब कंक्ल्यूड करिए। प्लीज कंक्ल्यूड करिए।

श्रीमती राखी बिरलाः तो आप एलजी के रूप में सिर्फ उस सरकार के कामों को रोकने, उस सरकार के कामों में अडंगा लगाने और उस सरकार के

साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर टकराव के जो है पूरे प्रोजेक्ट को लेकर बैठे हैं और अपने आकाओं को रोज़ आज मैने ये फाइल रोक दी, आज मैंने वो फाइल रोक दी सिर्फ आपका काम इतना रह गया है। अगर वास्तव में आप एक पिता है, एक पति है और एक भाई है तो मैं आज यहां से आपसे गुज़ारिश करना चाहती हूं कि दिल्ली की हर एक बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित हो इसके लिए आप दिल्ली सरकार का सहयोग करें और बेहतर से बेहतर कदम उठाने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ लगकर आप इस कार्यवाही को आगे बढ़ाये। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इसने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया और मुझे लगता है कि सिर्फ ये विषय चर्चा का ना रह जाए इस पर महत्वपूर्ण कदम उठे। इसके लिए जो हमारी विधान सभा की भी कमेटियां हैं वो भी दिल्ली पुलिस के अलग-अलग लोगों को बुलाकर जो है सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके लिए मापदंडों को तय करें और उस पर चर्चा करे। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द। जय भारत।

माननीय अध्यक्षः श्रीमान शिवचरण गोयल जी।

श्री शिवचरण गोयलः अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस गम्भीर दर्दनाक...

माननीय अध्यक्षः चलिए आप बोलिए-बोलिए।

श्री शिवचरण गोयलः और संवेदनशील मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी नाम सबका भी आ जाए एक्सटेंड भी ना किया जाए ये कैसे हो सकता है।

श्री शिवचरण गोयलः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। कंझावला का जो केस हमारी बेटी के साथ हुआ, नववर्ष की पूर्व संधया पर मुझे लगता है कि आजादी के 75 साल दिल्ली में केस देखेंगे तो इससे बड़ा दर्दनाक केस नहीं होगा। जिसके अंदर पूरी पुलिस ने लीपापोती की गई ताकि हमारी बिटिया को न्याय ना मिल सके और कई एलिगेशन भी लगे उसके ऊपर। कहीं उसने शराब पी रखी थी, बदचलन थी। ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में साढ़े पांच लाख कैमरे लगा रखे हैं कि आज जितने भी कार्यवाही करते जाएं उसका पूरा पर्दाफाश हमारे कैमरे करते रहेंगे, आप करते रहें और हम उसका पर्दाफाश करते रहेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री ने हर चौराहे पर, हर रोड पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिये हैं। यदि वो सीसीटीवी कैमरे नहीं होते तो कहीं ना कही अब न्याय भी नहीं मिलता हमारी बिटिया को। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर 302 धारा लगी और आज मैं कल न्यूज़ देख रहा था कि हर वो हमारी बिटिया के साथ महिलाओं के साथ जो भी केस होता है उसके पीछे ज्यादातर ये भाजपाईयों का हाथ क्यों होता है। कल हैदराबाद में भाजपा नेता ने युनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह से एक स्टूडेंट के साथ महिला स्टूडेंट के साथ उत्पीड़न किया और कल ही जो भाजपा नेता विधायक उन्नाव उसको कल जमानत मिली जिसका केस मेरे ख्याल पूरे भारत में बच्चे-बच्चे को पता है और हर केस के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा नेता शामिल होता है। तो ये जो कैसेज बढ रहे है और आज दिल्ली कहीं ना कहीं क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। इसके ऊपर बहुत गम्भीर विषय है। मैं अपनी विधान सभा का आपको। दिवाली से दो दिन पहले हमारे सुदर्शन पार्क में धनतेरस का दिन था, 32 साल का एक नौजवान हर्ज़ चौधरी वो सुबह काम से निकला और

शाम को वो तनख्वाह लेकर पीरागढ़ी चौक पर खड़ा था। दो बदमाश आए उन्होंने उस पैसे से छिना झपटी की। उसके खून पसीने की कमाई थी। उसने पैसे देने में आनाकानी की उसके ऊपर 12 चाकू मारे गए और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस में फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां उसकी मृत्यु हो गई। जिन्होंने चाकू मारे थे उसके पास उसके ऊपर मुझे ज्ञात हुआ कि 42 केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। इस तरह से बेखौफ अपराधी सड़कों पर घूमेंगे और इस तरह से इनकी हत्या होगी। उस परिवार में दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। जिसकी उम्र अभी तीस साल की थी वो विधवा और पूरा परिवार उस लड़के पर आश्रित था। आज वो परिवार मेरे से गुहार लगा रहा है कि आज जो स्थिति बन चुकी है हमें इसका न्याय मिले। वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन अभी भी वो अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। तो आये दिन हमारे क्षेत्र में इस तरह की वारदातें, मोबाइल चोरी होना, चैन स्नेचिंग होना। रोज की रोज मेरे ऑफिस में बच्चे आते हैं कहते हैं कि जी हम कॉलेज जा रहे थे पूरा डाटा इस मोबाइल के अंदर रिकार्ड था। पूरी प्रोफाइल इसके अंदर रिकार्ड थी और आज वो चोरी हो गया। हम घर में क्या शक्ल दिखायेगे मां-बाप से। यानि कि पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है और आज एक भय, हर जगह शराब बिक रही है, ड्रग्स बिक रही है। तो तमाम सारी चीजें जो भी दिल्ली में हो रही है सारी हमारे विधायक साथी ने बताई है। लेकिन इसके ऊपर कोई ना कोई एक दिशा निर्धारित करने की जरूरत है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सारी बातें हमारे विधायक साथियों ने कह दीं तो अपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती: अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस पर बोलना शुरू करूं इसके पहले मैं। अध्यक्ष महोदय, ये जो आज मोहल्ला क्लीनिक की बात उठी थी। मेरे पास मार्निंग में दो मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टर्स का फोन आया कि जी हमारी बिजली काटने वाले हैं तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं सदन के कि मोहल्ला क्लीनिक्स के बिजली कनेक्शन कट रहे हैं फॉर ड्यूज़। कोई ड्यूज़ हैं पैन्डिंग तो इसका संज्ञान लें। अध्यक्ष महोदय आज साथियों ने बहुत डिटेल में हर aspect पर इसकी जो लॉ एंड ऑर्डर की मुसीबत है दिल्ली में उसकी चर्चा की। आज कुछ देर पहले मुझे मालूम पड़ा स्वाति जी से खुद मालूम पड़ा किस प्रकार से उन्होंने कल एम्स के बाहर जब वो खड़ा हुईं चैक करने के लिए किस प्रकार से स्थिति बदली हैं, क्या अंजलि वाली घटना से दिल्ली ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, दिल्ली पुलिस ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, क्या भाजपा जगी है या नहीं जगी है। तो कल जब वो खड़ी हुईं वहां, तो बता रहे है कि कई बार गाड़ियां रूकी कि आप चलो। आप मेरे साथ चलो। जब उन्होंने मना किया तो एक गाड़ी दोबारा घूम करके आई और उनका हाथ पकड़ कर खींचने का प्रयत्न किया। इसको पूरा विडियो में कैप्चर किया गया और एम्स जैसे जगह पर कोई पीसीआर वैन या कोई सिक्योरिटी की उपलब्धता नहीं थी। वैसे तो मैं दाद देना चाहूंगा स्वाति मालीवाल जी की डीसीडब्ल्यू के चेयरपर्सन के रूप में इस प्रकार की जो उन्होंने प्लान की खुद कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था ठीक है कि नहीं, इसके लिए उनका धन्यवाद देना चाहिए कि अपनी जान की बाजी लगा करके और जोखिम भरा काम किया उन्होंने तो इसके लिए उनका धन्यवाद देना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं सदन की तरफ से उनको। अध्यक्ष महोदय, अभी विनेश फोगाट करके

वो जो रेसलर्स एसोशिएशन है वो भी वहां अभी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और साफ-साफ सभी लोगों ने इस बात को रिकार्ड पर लाने का प्रयत्न किया किस प्रकार से भाजपा का एक सांसद बृजभूज़ण शरण सिंह के ऊपर उन्होंने मोलेस्टेशन का एक्यूजेशन लगाया है लेकिन देखने वाली बात है कि इस व्यक्ति ब्रजभूज़ण शरण सिंह के ऊपर पहले भी एलीगेशंस हैं। भाजपा का सांसद है क्या यही क्राइटेरिया रह गया है कि आप वहां बने रहेंगे, कुछ भी करते रहिये बने रहेंगे। मुझे याद आ रहा है जब हम छोटे थे तो रामानंद सागर जी की जो रामायण आती थी उसमें जब रावण वध हो रहा था तो उसका एक सिर मारो वो फिर भी रावण हंसता है वापस आ जाता है सिर। दूसरा मारो फिर भी वो रावण हंसता है वापस आ जाता है सिर। तो मुझे लग रहा है की जो हम लोगों ने बार-बार, बार-बार कभी इस अधिकारी को कभी उस अधिकारी को कभी इस विभाग को कभी उस विभाग को जो लाने का प्रयत्न कर रहे हैं इसका मेजर सिर एलजी साहब हैं। अगर ये सर इनफैक्ट अगर वो कहें एक कदम और आगे जाएं तो भाजपा के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं क्योंकि उन्हीं के इशारे पर इस तरह कार्यक्रम हो रहा है तो जब तक भाजपा के मोदी जी के संज्ञान में तो बात आई है जब तक वहां से इस बात की खबर नहीं ली जाए की भई दिल्ली के अंदर औरतें असुरक्षित हैं, दिल्ली की सरकार काम करने में रोकी जा रही है तो सबकुछ का जेनेसिस जो है वो भाजपा के मोदी जी हैं। अध्यक्ष महोदय, तो ये आज की तारीख में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है तो दिल्ली पुलिस क्या करे। मेरे साथियों ने अभी अभी कहा की थाना लेवल कमेटी का नहीं हुआ फोर्मेशन। अब एक ही नोटीफिकेशन है मैं उसको देख रहा था लीगली भी देख रहा था कि एक ही नोटीफिकेशन से डिस्ट्रिक्ट

लेवल कमेटी बनती है और उसी नोटीफिकेशन से थाना लेवल कमेटी बनती है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बन गई क्यों, क्योंकि उनके जो सांसद हैं दिल्ली में वो सातों के सात बीजेपी के हैं। थाना लेवल कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो सारे एमएलए होते हैं ये बहुत बढ़िया चल रहा था जब हम फस्ट टाइम एमएलए बनकर आए थे उस वक्त क्षेत्रों के अंदर सारे एसएचओ को बुलाकर के जिस प्रकार से हम बात पूछते थे की भई इस पर काम नहीं हुआ उस पर काम नहीं हुआ तो अगली बार यानी की 2015 में जब सरकार बनी तो थाना लेवल कमेटी को इन्होंने डिस्मेंटल कर दिया। हमने बार-बार इस बात को उठाया और ये इल्लीगल भी है। कानूनन अगर एक ही नोटीफिकेशन से दो चीजें होती हैं और एक को कंटीन्यू करो और एक को डिस्कंटीन्यू करो ये तो इल्लीगल हैं अनकांस्टिट्यूनल हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में निर्भया हुआ उसमें बहुत हल्ला-गुल्ला हुआ बहुत सारे नये कानून बने लेकिन आज तक स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है। मैं अपने क्षेत्र से आपको एक उदाहरण देता हूं। एक महिला उनकी माइनर बच्ची गायब हो गई। अब माइनर बच्ची के गायब होने के बाद उन्होंने पुलिस में खूब चक्कर लगाया हम भी वहां गये हमने पुलिस से बातचीत की डीसीपी से बातचीत की उसके बाद यहां तक की हमने habeas corpus petition डाला दिल्ली हाइकोर्ट में। हाइकोर्ट ने आदेश दिया आज 6 महीना हो गया है वो माइनर बच्ची अभी तक दिल्ली पुलिस को नहीं मिली है। विडंबना यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की भतीजी का पर्स गायब हो जाए तो कुछ घंटों में सोनीपत से ले आते हैं दिल्ली पुलिस वाले लेकिन एक माइनर बच्ची गायब हो तो हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी पिछले 6 महीने से वो बच्ची गायब है। अध्यक्ष महोदय जिस प्रकार से राखी ने कहा की करीब-करीब एक

ही समय दो महत्वपूर्ण घटना घटी इस देश में एक केजरीवाल जी के रूप में दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में एक नया शासन आया। माननीय मोदी जी के रूप में एक नया प्रधानमंत्री देश को मिला। जो-जो विभाग माननीय केजरीवाल साहब के हाथ में आया चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बिजली का हो, पानी का हो उसमें ऐसे काम हुए की पूरे देश में क्या विदेशों के अंदर भी इसकी चर्चा है। दूसरी तरफ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी और दिल्ली में खासकर के दिल्ली पुलिस, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर जो तीनों केन्द्र सरकार के पास हैं deterioration इतना हुआ है लॉ एंड ऑर्डर में आज बच्चियां, महिलाएं, बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं बाहर निकलने से ये अपने आप में एक शर्मशार कर देने वाली घटना है चूंकि हम सारे विधायक गये थे सीपी साहब से मिलने के लिए। जब हमने वहां पूछा की भई 12 किलोमीटर तक जिस बॉडी को घसीटा गया इसमें 302 क्यों नहीं लगा उनके पास जवाब नहीं था। जिन अधिकारियों ने उसको बचाने का प्रयत्न किया उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया उनके पास जवाब नहीं था। साफ-साफ दिख रहा था की चूंकि उन दरिंदों में एक व्यक्ति भाजपा का है और इसी कारण से पूरी दिल्ली पुलिस को लगा दी गई है की भई अगर भाजपा के अच्छा टीवी चैनलों पर भी वो कल भगवंत मान जी बोल रहे थे वहां तेलंगाना में की माननीय मोदी जी ने सबकुछ बेचा बेल बेचा, रेल बेचा सब बेचा लेकिन एक चीज़ खरीद लिया मीडिया खरीद लिया। मीडिया खरीदा और बाकी सब बेचा। मीडिया ने भी इस बात को दिखाने का प्रयत्न नहीं किया की उन दरिंदों में एक दरिंदा भाजपा का है इनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है। यहां तक की उत्तराखंड का जो मंत्री का बेटा था उत्तराखंड में उस बच्ची के साथ ब्लात्कार किया उसकी

हत्या की उसकी चर्चा तक नहीं है। तो जिस प्रकार से हर तरफ भाजपा की इमेज खराब न हो जाए, भाजपा की इमेज में दाग न लग जाए, भाजपा जो झूठी बार-बार, बार-बार ये दावा करती है कि हमारे यहां बेटियां सुरक्षित हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब ढ़कोसला साबित हो रहा है अध्यक्ष महोदय और भाजपा का आज ये हाल है जो बंदर और चिड़िया के घोंसले का था। वो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थीं और कहा की भई बंदर को बोला आप क्यों बारिश में भीग रहे हो किसी पेड़ के नीचे आ जाओ जहां बच जाओगे, बंदर ने कहा अच्छा तू हमें शिक्षा देती है हम तेरी भी करते हैं उसी प्रकार से बंदर ने उसका सारा वो घोंसला नोच लिया और कहा तू भी भीग। तो जो यहां पर चल रहा है दिल्ली के अंदर एक एजुकेशनल रिफार्म्स, मेडिकल रिफार्म्स इससे सीखने की बजाय आप बंदर तो पहचान लो बंदर कौन है। सीखने की बजाय कि भई अपनी लाइन लंबी करें इनसे सीखें। अभी मतलब आप देखें अखबार के अंदर न्यूज में आ रहा है कि भई मधय प्रदेश में किसी व्यक्ति को अपनी बूढ़ी मां को ले जाना पड़ा अपने कंधे पर उनके पास एंबूलेंस तक नहीं है। किसी को खाट पर ले जा रहे हैं, किसी को साइकिल पर ले जा रहे हैं तो भाजपा शासित प्रदेशों में जो हालत है गवर्नेंस की वहां अगर केजरीवाल जी के हेल्थ के मॉडल से सीखते तो देश के लिए बेहतर होता। स्कूल के मॉडल से सीखते तो देश के लिए बेहतर होता लेकिन सीखने के बजाय जो यहां के आज मार्निंग से मैं सुन रहा था किस प्रकार से अधिकारियों को लगाकर के चीफ सेक्रेटरी को लगाकर के हर तरफ पंगू बनाने का प्रयत्न किया। एमसीडी चुनाव के पहले इन्होंने हर वो प्रयत्न किया जिससे की एमसीडी में उसका प्रभाव लिया जा सके यहां तक की मुख्यमंत्री साहब ने कहा भी सदन के अंदर कहा

की एलजी महोदय ने खुद कहा की इनकी तो संख्या 20 की आ रही थी ये तो हमारा फल है की 104 इनके आ गये चुनकर के इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है अध्यक्ष महोदय। तो मैं आज आपके माधयम से यह कहना चाहता हूं कि लॉग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो और हां अगर आप देखें लॉग टर्म में शिक्षा एक बदलाव कर सकता है। अच्छी शिक्षा, मैंटल साइकॉलोजी को डेव्लप कर सकता है अच्छे के तरफ। अध्यक्ष महोदय, अरविंद केजरीवाल जी ने जो एजुकेशन में रिफार्म शुरु किया है वो लॉग टर्म प्लान है क्रिमनेलिटी को और क्राइम को कम करने का। अगर क्रिएटिव रूप में इंगेज नहीं करेंगे यूथ को तो क्राइम बढ़ेगा लेकिन भाजपा का उस तरफ कोई धयान नहीं है। इकलौती सरकार है ये पूरे हिन्दुस्तान में अरविंद जी की जिसने शिक्षा के माधयम से mind set curriculum, entrepreneurship curriculum बहुत क्रिएटिव जो स्कीम्स इन्होंने क्रिएट की हैं जिसके जरिये कंस्ट्रक्टिव रूप में एक आज ऊर्जा को एक दिशा देने का काम किया है इससे सीखते भाजपा वाले अगर उनको तनिक चिंता होती।

माननीय अध्यक्षः कंक्ल्यूड करिये सोमनाथ जी कंक्ल्यूड करिये।

श्री सोमनाथ भारतीः लेकिन अध्यक्ष महोदय मुझे लग रहा है कि भाजपा ने फैसला कर लिया है कि न वो खुद भला करेंगे देश का न किसी को करने देंगे। आज बहुत निंदा का विषय है तो जिस प्रकार से अधिकारियों का दुरुपयोग करके हमारे काम रोके हैं उन्होंने, हमारे फंड रोके हैं उन्होंने और जो काम इकलौता उनका है लॉ एंड ऑर्डर का उस पर कोई काम नहीं कर रहे, न तो रिफार्म कर रहे हैं न फंड की युटिलाइजेशन कर रहे हैं। हां जो केजरीवाल

जी के पास था कि दिल्ली को सिक्योर कैसे किया जाए वुमन सिक्योरिटी पर कैसे काम किया जाए उस पर उन्होंने काम किया। आप देखें साढ़े चार लाख कैमरे दिल्ली में लगे आज दिल्ली जो है पूरी दुनिया में मोस्ट प्रोटेक्टेट सिटी है पूरी दुनियां के अंदर। आज जिस प्रकार से हमने बसों में मार्शल लगाया, बसों को इक्युप किया, बसों के अंदर हमने पैनिक बटन लगाये, सीसीटीवी कैमरे लगाये इन सारी सुविधाओं को हमने देने का प्रयत्न किया लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की जो उनके पास रिस्पांसिबिलिटी है उस पर वो लचर साबित हो रहे हैं और इसका एकमात्र कारण है की पॉलिटिकल विल नहीं है राजनीतिक इनके पास विल नहीं है कि इसको करेक्ट किया जाए इसी कारण से आज दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं असुरक्षित हैं इसकी मैं निंदा करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप इन बातों को कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास पहुंचाएं, होम मिनिस्टर के पास पहुचाएं की सदन की ये इस प्रकार से यहां विचार रखे गये और इस पर काम किया जाए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंहः थैंक यू स्पीकर साहब, देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर इस बहुत ही संवेदनशील चर्चा में समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। स्पीकर साहब, इकबाल अजीम जी का बहुत ही एक शानदार सेर है किः

'झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है,

झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है,

मगर सर इतना भी न झुकाओ कि इज्जत गिर जाए'

आज दिल्ली में जो केन्द्र सरकार ने नियुक्त कर रखे हैं एलजी साहब और जिस तरीके से चाहे पिटिशन कमेटी की डिस्कशन हो चाहे ये डिस्कशन हो जो दिल्ली के अफसरों का रवैया जो उनकी असल जिम्मेदारी बनती थी उसको छोड़कर जिस तरीके से सारे ऑफिसर एलजी साहब की चमचागिरी कर रहे हैं और एलजी साहब केन्द्र सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं और अपनी असल जिम्मेदारी भूले हुए हैं उस वजह से दिल्ली के ये हालात बने हुए हैं। लोग कहते हैं कि 1 तारीख को जो होता है, 1 तारीख को ऐसे काम करो जो सारा साल होते रहें पर इस साल जो 1 तारीख को खबरें देखने को मिली मैं उस भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी खबरें साल में दोबारा देखने को न मिलें। साल 2012 के अंदर निर्भया कांड हुआ था उसके बाद सरकारें बदल गईं। दो सरकारें बनीं एक दिल्ली में बनी एक केन्द्र में बनी। दिल्ली सरकार ने उससे सबक लिया महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता उन अपराधों के प्रति संवेदनशीलता के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाये, बसों के अंदर पैनिक बटन लगाये, बसों के अंदर कैमरे लगाये, बसों के अंदर मार्शल लगवाये, मोहल्लों में सिक्योरिटी गेट लगवाये, स्ट्रीट लाइट्स लगवाईं कि अपराध कम हो सकें दिल्ली के अंदर। अब ये नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो का जो डाटा है अध्यक्ष जी वो कहता है कि दिल्ली महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में देश में नंबर-1 हो चुकी है। अगर 100 अपराध दिल्ली के अंदर हो रहे हैं तो 40 अपराध सिर्फ महिलाओं के ऊपर होते हैं। अब बात तो होनी चाहिए थी हमारा सब्जेक्ट भी है steps to improve law and order situation and woman security in light of recent gruesome death of a girl in Kanjhawala भई ये जो लॉ एंड ऑर्डर है इसके अंदर सुधार होने चाहिए तो

सुधार कैसे होने चाहिए। दिल्ली पुलिस की अगर बात करें जिसका सीधा-सीधा कंट्रोल एलजी साहब के हाथ में है तो बार-बार कई डिकेड से दिल्ली पुलिस के अंदर रिफार्म्स की बात हो रही है और अब दिल्ली पुलिस के भी अधिकारियों से कर्मियों से बात करो तो वो कहते हैं जी हमारे पास स्ट्रैंथ की बहुत कमी है। एक लाख दिल्ली वालों के ऊपर 410 पुलिस वाले हैं मतलब 1000 दिल्ली वालों के ऊपर सिर्फ 4 पुलिस वाले तैनात हैं तो सिक्योरिटी कहां से होगी। इन चीजों के ऊपर धयान देने की बजाय एलजी साहब करते क्या हैं इधर तो ध्यान है ही नहीं अगर इधर धयान होता तो डिस्कस करते, दिल्ली पुलिस की बार-बार मीटिंग्स होती, दिल्ली पुलिस के उन लापरवाह पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी तय होती की भई ये तुम्हारा बीट का एरिया स्ट्रक्चर तो सारा बना हुआ है। अब आम आदमी को मालूम है जैसे रोहित भाई बता रहे थे की भई सरे आम यहां पर शराब बिक रही है, हमारे राजेन्द्र भाई बता रहे थे भई सबको मालूम है भई यहां पर नशा बिक रहा है तो क्या दिल्ली पुलिस के उस बीट ऑफिसर को नहीं मालूम होगा यहां नशा बिकता है। सबसे पहले वो वहां से पैसे कलैक्ट करता होगा अध्यक्ष जी जाकर। तो इन अधिकारियों की ड्यूटी एलजी साहब को तय करनी चाहिए थी पर एलजी साहब के पास फुर्सत है ही नहीं। एक टाइमली एक्शन बाय पुलिस में बड़ी दिक्कत है अध्यक्ष जी। 2015 का आनंद विहार का वाक्या है कि एक लड़की ने थाने में शिकायत दी भई ये आदमी मेरे को बड़े दिनों से घूर रहा है उस शिकायत के ऊपर कार्यवाही करने की बजाय पुलिस ने तो कंप्लेंट एज यूजअल रिसीव करके रख ली। उस शिकायत करने के बाद वो आदमी इतनी खुंदक में आ गया की उसने उस लड़की का मर्डर कर दिया। ये ही अगर पुलिस कोई सख्त एक्शन उसके ऊपर ले लेती

तो बार-बार ये घटनायें रिपीट ना होतीं। आज दिल्ली के अंदर अपराधी इतने बेखौफ घूम रहे हैं कि कानून का कोई डर ही नहीं रह गया और नोर्मली अध्यक्ष जी जनता के पास लोकतंत्र में अलग-अलग महकमों के लिये दिल्ली में तो थ्री लेयर सिस्टम बना हुआ है कि एमसीडी से रिलेटिड कोई काम हो तो लोग निगम के दफ्तर निगम पार्षद के दफ्तर चले जाते हैं, दिल्ली सरकार का कोई काम होता है तो विधायकों के दफ्तर आ जाते हैं सारे विधायक मिलते हैं। एम.पी. साहब जिनके पास मोटे-मोटे तौर पर एक-दो ही विभाग हैं दिल्ली पुलिस है डीडीए, दिल्ली पुलिस की हर दिन शिकायतों की भरमार हमारे दफ्तरों में रहती है क्योंकि एम.पी. साहब का तो नाम तक किसी को नहीं मालूम अध्यक्ष जी मिलना तो बहुत दूर की बात है और नाम मालूम है तो लोगों को ये नहीं मालूम की एम.पी. साहब आये कब थे, एम.पी. साहब से मिला कैसे जाता है। सोमनाथ भाई ने बहुत बढ़िया बात की हमने भी बहुत सारी मीटिंगें पहले एक साल में कीं जो थाना लैवल कमेटी होती थी पर बंद कर दिये अध्यक्ष जी अब पब्लिक जाये तो किसके पास जाये। एल.जी. साहब के पास कोई जा सकता है दिल्ली का आम बंदा एल.जी. साहब तो हमें टाइम नहीं देते, एल.जी. साहब तो दिल्ली के चुने हुये नुमाइंदें जो हैं विधायक हैं उनको टाइम नहीं देते एल. जी. साहब तो मुख्यमंत्री साहब को चार-चार दिन इंतज़ार कराते हैं तो जनता जाये तो जाये कहां। अध्यक्ष जी तो इस सिस्टम पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है अध्यक्ष जी, जो हालात दिल्ली के बन चुके हैं हर दिन बद से बद्तर ये हालात होते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार अपने तौर पर जैसा मैंने शुरू में भी बोला, बहुत अच्छा काम कर रही है एक मेरे को और याद आया कि मोहल्ला रक्षक दल इसी हाउस से प्रपोज़ हुये थे कि हर मोहल्ले में दिल्ली सरकार की

तरफ से मोहल्ला रक्षक दल दिये जायेंगे, 25-25 का ग्रुप बनेगा सिविल डिफेंस वॉलेन्टियर वहां पर तैनात किये जायेंगे। लोगों को सुरक्षा मिलेगी और पुलिस को भी काम में हैल्प मिलेगी अब खुद इनके बस की है नहीं कि पुलिस फोर्स बढ़ा लें, हम बढ़ाते हैं तो हमें बढ़ाने नहीं देते तो ये सिलसिला कहीं ना कहीं इस सिलसिले पर ब्रेक लगनी चाहिये इन अधिकारियों से भी उस परमेश्वर से ही प्रार्थना कर सकते हैं अध्यक्ष जी कि इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है कि इनको थोड़ी सद्बुद्धि दें एल.जी. साहब को थोड़ी सद्बुद्धि आये, इन अधिकारियों को थोड़ी सद्बुद्धि आये कि जिस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं जो उनका कर्तव्य बनता है थोड़ी सी भी शर्म बची है तो अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ दिल्ली वालों के हक के लिये कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करें ताकि आप भी अल्टिमेट्ली सबको उस भगवान को मुंह दिखाना है कल को मुंह दिखाने के लायक हों और उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं जो सौरभ भाई ने आज सदन में प्रस्ताव रखा है कि दिल्ली विधानसभा के अंदर एक Bill of Shame जरूर बनाई जाये अध्यक्ष जी ताकि लोगों बार-बार इनके चेहरे उजागर किये जायें कि दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिलने के बाद भी ये दिल्ली वालों के साथ धोखा कर रहे हैं और दिल्ली वालों के साथ हर कदम पर उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं आज के इस चर्चा में समय देने के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी क्योंकि जो सब्जेक्ट है जो विषय है बहुत ही संवेदनशील है तो इस सदन की तरफ से कोई कड़ा संदेश इस तरीके से आप कोई रूलिंग दें कोई व्यवस्था दे जायें ताकि इस व्यवस्था में जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं दिल्ली वुमेन कमिशन की चेयरपरसन तक सुरक्षित नहीं हैं तो आम महिलाओं की तो बात ही छोड़ दें एक कड़ा संदेश आपकी

तरफ से इस सदन की तरफ से जाये ऐसी हम आप सब से उम्मीद करते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी, थैंक्यू।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, अंतिम वक्ता बी.एस. जून जी।

श्री बी.एस. जूनः धन्यवाद सर, सर न्यू ईयर की शाम को जो ये केस हुआ इन्वेस्टिगेशन चल रही है हम भी चाहते हैं ये सदन भी चाहता है पूरी देश की जनता चाहती है उस लड़की को न्याय मिले पर जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्या उस लड़की को पूर्ण और उचित न्याय मिलेगा, मूल क्वेश्चन यही है। जिस कन्डिशन में लड़की की बॉडी मिलती है उसकी बॉडी पर ना कोई कपड़ा था, उसकी बॉडी के कुछ limbs पार्ट वो भी गायब थे और बॉडी पर जो flesh होता है वो भी नहीं था एक स्कैलेटन मिला था पुलिस को और पुलिस ने कहा कि उसको ड्रैग किया गया 12 घंटे 12 किलोमीटर तक और पुलिस केस रजिस्टर करती है 279-304/ए rash driving causing death not amounting to murder जिस लड़की को 12 किलोमीटर तक ड्रैग किया गया था वो एक्सिडेंट केस कैसे हो सकता है। सबसे पहले गलती पुलिस ने ये की कि उन्होंने एक्सिडेंट का केस दर्ज कर लिया, सेम नाइट को या अगले दिन बॉडी मिलने के बाद बॉडी की कंडीशन देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ 304 आईपीसी में केस रजिस्टर होना चाहिये था जो पुलिस ने नहीं किया पहली खामियां भी खामियाजा पुलिस पहली नाकामी पुलिस की ये थी, सर उसके बाद कुछ दिनों बाद एक लड़की का स्टेटमेंट होता है निधि का 164 सीआरपी से मजिस्ट्रेट के सामने, वो बोलती है जब कार से टक्कर लगी स्कूटी की मैं उसी पर थी मैं गिर गई डर के मारे भाग गई लड़की उस कार में फंस गई,

कार वालों को पता था की लड़की उस कार में फंसी हुई है और वो चिल्ला रही थी लड़की नीचे से लेकिन ये कार लेकर भाग गये इसका मतलब एक आई विट्नेस है अगर आई विट्नेस उसमें था और बाद में वो लड़की को ड्रैग करते हुये ले गये तो उस लड़की की स्टेटमेंट के बाद उसमें 304 एड क्यों नहीं हुआ आज तक पुलिस ने इस बात का जवाब नहीं दिया जो अल्टिमेंट्ली 17 तारीख को आकर उन्होंने 302 एड किया। सर अगर 304 एड किया तो 279 304/ए कैसे हो गया। 279 होता है negligent act और 304 है culpable homicide not amounting to murder जिसमें इन्टेंशन भी है और नॉलिज भी है जिस दिन 304 एड किया तो एक्सिडेंट के सैक्शन हटा देने चाहिये थे। आज भी एफआईआर अगर आप देखेंगे तो एफआईआर में 279 304/ए, 304 120/बी और 302 लगी हुई है अब एक गाड़ी में 4 या 5 लड़के हैं जो शराब पिये हुये हैं टक्कर मारते हैं लड़की को ड्रैग करते हुये ले जाते हैं, 120/बी की क्या एविडेंस है आपके पास, मैं consequences की बात कर रहा हूं जो आगे सामने आयेंगे ट्रायल में, 120/बी की आपके पास एविडेंस क्या है, सर 120/बी होता है prior meeting of mind जो कि इन्सिडेंट से पहले होता है। उस गाड़ी में क्या डिस्कशन हुई क्या उनकी बातें हुईं ना तो आपके पास कोई रिकार्डिंग है ना की आपके पास कोई विडियो सीडी है तो आपने 120/बी कैसे लगा दी। उसके बाद सर आता है मोटिव, मदन लाल जी ने ठीक कहा कि मोटिव था अगर मोटिव निधि के बयान से प्रुफ हो रहा था तो उसी दिन 302 लगा देनी चाहिये थी लेकिन इन्होंने मोटिव के ग्राउंड पर पुलिस कहती रही मोटिव नहीं है 302 नहीं लगेगा। नैक्सट आता है सर आईडैंन्टिफिकेशन, उस गाड़ी में कितने आदमी थे पुलिस के अनुसार 5 थे, कौन कह रहा है ये आज तक किसी

ने आईडैंन्टिफाई नहीं किया उनको, ट्रायल में आप कैसे साबित करोगे कि ये वो ही लोग हैं जो गाड़ी चला रहे थे निधि ने भी आईडैंटिफाई नहीं किया अगर किया होता तो अभी तक उनकी judicial TIP Test identification parade हो रही होती वो भी नहीं हुई तो उनको identify court में करेगा कौन accused का स्टेटमेंट दूसरे accused के खिलाफ inadmissible होता है कोर्ट में वो चलेगा नहीं, मैं कह दूं मेरे साथ 4 लड़के और थे लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं है आपको judicial way में उनकी identity establish करनी पड़ेगी जो आप अभी तक नहीं कर पाये। इस केस के जो Investigating Supervisory Officer थे वो थे डीसीपी हरिन्दर सिंह, आपको याद होगा डीसीपी हरिन्दर सिंह वही हैं जो CS assault केस में भी थे उसमें भी इन्होंने हमारे 3 विधायकों पर 120/बी लगा दी कि जी 120/बी के तहत जो है ना इन्होंने हमारा एक meeting of mind हुआ और सी.एस. के साथ एसॉल्ट किया, कोर्ट में केस गया क्या हुआ 13 में से 11 विधायक डिस्चार्ज हो गये इन्क्लुडिंग सी.एम. एंड डिप्टी सी.एम. क्योंकि कोर्ट ने कहा कैसी conspiracy हो गई, conspiracy तो है ही नहीं, तो ये श्रीमान जी एक्सपर्ट हैं 120/बी वो करने के लिये और इनको भूख रहती है पब्लिसिटी की, मीडिया के सामने आने की अभी आप दो-तीन दिन पहले हमने टीवी पर देखा कि ये फुल यूनिफार्म में उस गाड़ी के नीचे घुस रहे हैं ये देखने के लिये कि बॉडी फंस सकती है या नहीं फंस सकती है अरे भई ये आपका काम थोड़ा है ये फोरेंसिक वालों का काम है गाड़ी में बॉडी फंस सकती थी नहीं फंस सकती थी और कितनी दूर तक बॉड़ी ड्रैग हुई ये फोरेंसिक वाले बतायेंगे लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने फोटो खिंचवाने थे वो गाड़ी के अंदर घुसे हुये हैं और फोटो खिंच रहे हैं मिडिया

वालों को बुला रखा है तो ये केस इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो ना scientific way से हो रही है जो इनका ढर्रा है पुराना पुलिस का उसी के अनुसार हो रही है और अल्टिमेटली शायद मिडिया ट्रायल की वजह से पब्लिसिटी की वजह से 304/बी conviction हो जाये लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सिर्फ ये एक्सिडेंट से ये केस आगे नहीं बढ़ पायेगा तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस एल.जी. साहब के पास है लेकिन पुलिस ने आज तक अपना रवैया नहीं बदला सर ऐसा ही केस एक बीएमडब्ल्यू कांड हुआ था दिल्ली में कई साल पहले बीएमडब्ल्यू में कोई चार-पांच सोते हुये आदमियों को कुचल दिया था वो केस चला उसमें एक सरकारी वकील थे सीनियर एडवोकेट और Defense Counsel थे मिस्टर आर. के. आन्नद, सीनियर एडवोकेट उन्होंने ऐसी खिचड़ी पकाई कि जी एक्सिडेंट बीएमडब्ल्यू से नहीं हुआ ये तो ट्रक से हुआ था ये साबित कर दिया कोर्ट में और अल्टिमेट्ली हाई कोर्ट ने उसका cognizence लिया, उस केस में सज़ा हुई जो complainant था वो भी टूट गया था लेकिन हाई कोर्ट ने उसको भी नोटिस दिया कि तुमने झूठ क्यों बोली, आर.के. आन्नद का जो सीनियर डेज़िग्नेटिड वकील का दर्जा था वो छीन लिया हाई कोर्ट ने और आयु खान आज तक नज़र नहीं आये कि वो प्रैक्टिस में हैं या नहीं हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है पुलिस बिल्कुल ईन्सेंसेटिव है अगर ये थोड़ा-बहुत इस लड़की को न्याय मिलेगा तो इस बात पर मिलेगा कि इसमें मीडिया ट्रायल हो, अगर मीडिया ट्रायल होता है तो हमारे देश में conviction हो जाती है नहीं तो सेंकड़ों केस आते हैं और चले जाते हैं। बीएमडब्ल्यू कांड के बाद एक धोला कुंआ का ट्रक का एक ऐसा ही केस हुआ था जिसमें एक आदमी को ड्रैग किया

एक-दो फर्लांग ट्रक वाले ने, उन सब केसिज़ में 304/बी एफआईआर हो रही थी जबकि यहां एक्सिडेंट के केस की एफआई आर हो रही है जबकि लड़की की बॉडी beyond recognition थी और फिर भी आप एक्सिडेंट का केस रजिस्टर कर रहे हो तो मैं तो चाहता हूं उस दु:खी परिवार को न्याय मिले, अच्छे वकील मिलें उनको अच्छा सरकारी वकील मिले और उनको न्याय मिले लेकिन जिस टाइप की इन्वेस्टिगेशन हो रही है मुझे नहीं लगता इस परिवार को या इस जो लड़की चली गई उसको न्याय मिलेगा। सर बहुत संसेटिव इश्यू है हमें इसको जरूर पुलिस कमिश्नर, एल.जी. या होम मिनिस्ट्री में भेजना चाहिये कि इन्वेस्टिगेशन प्रोपर हो ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद फैक्ट्स पर अब हमारे साथी बहुत कुछ बोल चुके हैं बहुत-बहुत शुक्रिया सर।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, अब माननीय मंत्री गोपाल राय जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री गोपाल राय (माननीय पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन अभी कंझावला के अंदर जिस तरह से दिल्ली की बेटी के साथ दर्दनाक और क्रुर घटना हुई उसको लेकर के चर्चा कर रहा है। दिल्ली सरकार और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना की स्थिति को समझते हुये पहले ही जिम्मेदारी के साथ और सक्रियता के साथ बहुत सारे कदम उठाये हैं। सदन के अंदर अभी इस घटना के कानूनी पहलू पर हमारे माननीय विधायकों ने चर्चा की, इसके प्रशासनिक पहलू पर चर्चा की, इसके सामजिक पहलू पर चर्चा की। अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखें तो सदन के अंदर कल से जो चर्चायें चल

रही हैं उन सारी चर्चाओं का एक तार जुड़ता है और निश्चित रूप से इस सदन के अंदर चिंता के साथ-साथ हमें लगता है कि अब नये सिरे से एक चिंतन को भी विकसित करने की जरूरत है, इसका समाधान क्या हो सकता है क्योंकि ऐसा लगता है कि जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति बनी हुई है मुझे लगता है कि पूरे भारत के अंदर किसी भी राज्य के अंदर चुने हुये सदन में इस तरह से मातम मनाने की मजबूरी नहीं है, हम तीन दिन से मातम मना रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक ठप्प कर दिया गया हम मातम मना रहे हैं, जल बोर्ड का पेमेंट रोक दिया गया हम मातम मनाने की स्थिति में केवल हैं, दिल्ली के अंदर कंझावला कांड होता है दर्दनाक घटना होती है हम क्यों मातम मनाने की स्थिति में हैं, दिल्ली के अंदर झुग्गियों को उजाड़ने का नोटिस दे दिया केवल हम मातम मनाने की स्थिति में हैं। जिस तरह से भारत के लोकतंत्र के अंदर इस सदन को केवल मातम मनाने का मंच बनाने की मजबूरी पैदा हुई है, मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय चिन्तन से ही लोकतंत्र पैदा हुआ भारत के अंदर पहले लोकतंत्र नहीं था। आदिम ज़माने में जब पहले हमारे यहां ancient history में उल्लेख मिलता है कि संघ हुआ करते थे लेकिन भारत के अंदर सामंती व्यवस्था से राजशाही की व्यवस्था हुई, कुछ लोगों ने चिंतन किया तभी सामंती व्यवस्था से राजशाही की व्यवस्थायें आई। आज दिल्ली के अंदर सदन के अंदर हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं हमें लगता है कि आज वो वक्त आ गया है क्योंकि आज दिल्ली के अंदर अगर इस तरह की घटनायें बार-बार, बार-बार, बार-बार हो रही हैं तो उसका कुछ कारण है। अध्यक्ष जी, मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कल टेलिविज़न में सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार और Lieutenant Governor की तरफ से तुज़ार मेहता जी सुप्रीम कोर्ट के सामने

कल बोले अपने आखिरी पक्ष को रखते हुये कि हम दिल्ली को अराजकता में नहीं छोड़ सकते, अध्यक्ष जी इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिये कि दिल्ली के अंदर अराजकता को पैदा कौन कर रहा है। दिल्ली के अंदर अगर कंझावला कांड होता है और सभी हमारे साथियों ने कहा सारे जानकार कानून के वकील हैं अगर दिल्ली के अंदर कंझावला कांड होता है और उसके बाद पुलिस चुपचाप देखती रहती है उसके बाद घटना के बाद उसके बाद पुलिस लापरवाही करती है अगर उसके बाद भी आरोपियों को पुलिस बचाने की आखिरी कोशिश करती है जनता की आवाज उठती है तब होम मिनिस्टरी हिलती है 302 का मुकद्मा दर्ज होता है दिल्ली के अंदर अराजकता कौन पैदा कर रहा है, दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाकर के सबूत इकट्ठा करने वाला मुख्यमंत्री अराजकता पैदा कर रहा है या दिल्ली का Lieutenant Governor भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने के लिये दिन-रात एक कर रहा है वो अराजकता पैदा कर रहा है, कौन अराजकता पैदा कर रहा है दिल्ली के अंदर झुग्गियों को बसाने वाला अराजकता पैदा कर रहा है दिल्ली का मुख्यमंत्री या दिल्ली की झुग्गियों को उजाड़ने का नोटिस देने वाला अराजकता पैदा कर रहा है कौन अराजकता पैदा कर रहा है, दिल्ली के लोगों के मोहल्ला क्लिनिक में इलाज दर्द से पीड़ित लोगों का इलाज करने वाला अराजकता पैदा कर रहा है या वहां पर इलाज ना हो तनख्वाह रोक करके मोहल्ला क्लिनिक को ठप्प करने वाला अराजकता पैदा कर रहा है दिल्ली के लोगों को पानी ना मिले इसके लिये पेमेंट रोककर के षड़यंत्र करने वाला अराजकता पैदा कर रहा है या अराजकता दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री जो हर घर में जिसके घर में पैसा नहीं है उसको भी पानी पिलाने का काम कर रहा है वो अराजकता पैदा कर रहा है अराजकता पैदा

कौन कर रहा है अध्यक्ष महोदय। अराजकता पैदा इसलिये की जा रही है क्योंकि अध्यक्ष महोदय आज दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का कोई माई–बाप नहीं है इस दिल्ली के अंदर सिस्टम ऐसा बनाया गया। ये 70 विधानसभा के प्रतिनिधि चुनकर के यहां बैठे हैं इनको 5 साल बाद जनता की अदालत में जाना पड़ता है अगर आज ये नहीं करेंगे तो कल इनको जवाब देना पड़ेगा, लोकतंत्र में इसीलिये चुने हुये प्रतिनिधियों को सबसे ऊपर बिठाया गया क्योंकि उनको जनता की अदालत में जाना पड़ता है ब्यूरोक्रेसी को जनता की अदालत में नहीं जाना पड़ता Lieutenant Governor को जनता की अदालत में नहीं जाना पड़ता अगर आज दिल्ली के अंदर ये विधायक कुछ नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेंगे, मंत्री कुछ नहीं करेंगे तो उनको जनता की अदालत में जाना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, Lieutenant Governor जनता की अदालत में नहीं जाने वाले, जिस तरह से एक ऑर्डर से रात में गुजरात से चापलूसी करके और उसके इनाम के रूप में अटैची लेकर के दिल्ली के Lieutenant Governor के बंगले मे आ गये, कल दिल्ली को अराजकता के कारागार में झोंककर के ये फिर बैग उठायेंगे और निकल जायेंगे, जनता की अदालत में इन लोगों को जाना है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, जो दिल्ली का सिस्टम है दिल्ली के सिस्टम को सुधारा नहीं जायेगा, दिल्ली में सिस्टेमेटिक संस्थागत परिवर्तन की जरूरत है क्योंकि एल.जी. महोदय को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वृक्षरोपण का, पुलिस लेकर के रात में बैनर लगाते हैं और सुबह मुख्यमंत्री के पोस्टर बैनर फड़वाते हैं। एल. जी. साहब को वहां गुंडागर्दी करने के लिये समय है आज सदन पूछ रहा है हिम्मत है तो Lieutenant Governor जवाब दें कंझावला में आज तक उस Lieutenant Governor को जो डेली फोटो खिंचवाता है, डेली अखबार में न्यूज़

छपवाता है, डेली video film बनवाता है आज तक Lieutenant Governor के पास हिम्मत क्यों नहीं हुई कि जाकर के उसकी माँ के सामने आंख से आंख मिलाकर के एक बार उसके आंसु तो पोंछ देते, अराजकता कौन फैला रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली में केवल हमारी जिम्मेदारी प्रतिनिधि बनकर के यहां आने और यहां मातम मनाने की नहीं है अध्यक्ष महोदय। सरकार की तरफ से हम कहना चाहते हैं, सरकार के चुने हुये सरकार की जिम्मेदारी है जहां तक हो सकता है संवैधानिक तौर पर जो अधिकार है उसमें हम लड़ेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिये लड़ेंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय इस सदन का एक सदस्य होने के नाते भी मैं कहना चाहता हूं हमें इस पर चिंतन करना पड़ेगा और हम कहते हैं बंद हैं तो और भी खोलेंगे हम, रास्ते हैं कम नहीं तादाद में, नया रास्ता बनाना होगा। दर्द होता है अरे कल जब हम विधानसभा के सदस्य नहीं थे, कल जब हमारी सरकार नहीं थी, कल जब हम मंत्री नहीं थे तब भी दिल्ली वालों के दर्द के लिये लड़ने की हिम्मत हमारे पास थी आज ऐसा लगता है कि चुन लिये गये तो हमें बेड़ियों में बांध दिया गया हमारी आवाज़ बंद कर दी गई और अगर सच के लिये बोलते हैं तो गुनाहगार साबित किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं:

''दर्द बहुत है सीने में कहा नहीं जाता

लेकिन करें क्या मजबूरी है फिर भी ये दर्द सहा नहीं जाता।''

इसके लिये लड़ना पड़ेगा बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित करने से पहले मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय

उप-मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, सभी मंत्रीगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधुड़ी जी तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, इसके अलावा सदन के संचालन में सहयोग देने के लिये विधानसभा सचिवालय तथा दिल्ली सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ, विभिन्न विभागों और सुरक्षा एजेंसियों तथा मिडिया का भी धन्यवाद करता हूं। अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रीय गान के लिये खड़े हों।

(राष्ट्रीय गान)

अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई।)

....समाप्त....

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।